www.indiatodayhindi.in

यूपीः मांग मनवाने के लिए प्रदर्शन

टीकाकरणः निजी क्षेत्र की सुस्त चाल

आयुध कारखानों का कायापलट

9 770971 372703

18 अगस्त, 2021 50 रुपए

इंडिया टुडे

लवलीना बोरगोहेन, मीराबाई चानू और पी.वी. सिंधु

तोक्यो ओलंपिक

बेटियों का दमखम

महिला खिलाड़ियों ने जहां देश को गौरवान्वित किया, वहीं हमारा समग्र प्रदर्शन निराशाजनक था. भविष्य में ज्यादा पदक जीतने के लिए क्या करने की जरूरत है

RNI NO 45823/86 REGISTERED NO. DL(ND)-11/6042/2021-22-2023; LICENSED TO POST WPP NO U(C)-31/2021-23; FARIDABAD/46/2020-22

अग्रिम सप्ताह के लिए प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित; एलपीसी दिल्ली-आरएमएस-दिल्ली-110006 से प्रत्येक शनिवार और सोमवार को प्रेषित; कुल पन्नों की संख्या 52 (आवरण सहित)

VISIT…

SATHYABAMA

INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(DEEMED TO BE UNIVERSITY)

ENGINEERING | ARCHITECTURE | MANAGEMENT

ARTS & SCIENCE | LAW | DENTAL | PHARMACY | NURSING

For more details, contact -

9940058263 | 9940168007 | 9940069538

www.sathyabama.ac.in

\SathyabamaOfficial @sathyabama.official @SathyabamaSIST YouTube \Sathyabama

प्रधान संपादक की कलम से

Only books magazine

हरेक ओलंपिक के दौरान देश में बहुत हाय-तौबा मचती है कि भारत का जत्था अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शन क्यों नहीं करता. इस साल तोक्यो ओलंपिक भी अलग नहीं है. टीम इंडिया का कुल प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. 5 अगस्त को 85 पदक विजेता देशों की तालिका में भारत 62वीं पायदान पर घिसट रहा था. अदने-से कतर और कोसोवो भी दो-दो पदक जीतकर उससे आगे थे.

हमारे कई एथलीट अपनी संभावनाओं पर खरे नहीं उतरे. भारतीय निशानेबाजी टीम का धराशायी होना एक उदाहरण भर है. भारत के दो सबसे शानदार मुक्केबाज पहले ही दौर में बाहर हो गए. गौर करने की बात यह है कि ओलंपिक में उतरने से पहले भारतीय एथलीटों को कई बाधाएं पार करनी पड़ती हैं—खेलों का दयनीय बुनियादी ढांचा, राजनीति के अखाड़े बन चुकी खेल संस्थाएं और संवेदनशून्य अफसर. हमारे खिलाड़ी जब दुनिया के सर्वोच्च खेल अखाड़ों में पहुंचते हैं तो और भी गंभीर परेशानियां नतीजों पर असर डालती हैं. 2018 में नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कोच ने एक गोपनीय रिपोर्ट भेजी, जो कहती है कि भारत के 72 फीसद निशानेबाज हर बड़े मुकाबले में क्षमता से कमतर प्रदर्शन करते हैं. दबाव से निपटने और खुद को नियम-कायदों में रख पाने की उनकी अक्षमता को वे इसकी वजह बताते हैं. रिपोर्ट कहती है कि हमारे पास अकूत प्रतिभा है, कमी है तो खेल विज्ञान की. यही वह है जिसे बीजिंग ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा हाथ न आने वाला '1 प्रतिशत' कहते हैं, जो हार को जीत में बदल सकता है.

21 जुलाई, 2021 का आवरण

भारतीय महिला एथलीटों का प्रदर्शन अलबत्ता मौजूदा ओलंपिक में आशा की किरण है. आगे बढ़ने के लिए उन्हें असाधारण हुनर की जरूरत पड़ती है, उस समाज में जो अब भी पितृसत्तात्मक है. भारतीय परिवारों में व्याप्त पुत्र-मोह और लिंग-चयन की प्रथाओं से लड़ने से लेकर घर और कार्यस्थलों पर भेदभाव झेलने और पोषण तथा शिक्षा के लिए जद्दोजहद करने तक उन्हें क्या-क्या नहीं करना पड़ता. लैंगिक खाई पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मार्च 2021 की जेंडर गैप रिपोर्ट कहती है कि भारत इस खाई को केवल 62.5 फीसद ही पाट पाया, जो 2019 के 66.8 फीसद से भी कम है. भारत की 59 फीसद निरक्षर आबादी महिलाएं हैं. यह तोक्यो में भारतीय महिलाओं के प्रदर्शन को इतना उल्लेखनीय बनाने वाले कारणों में से महज एक है. 2021 तक व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाओं में भारत के कुल 17 पदकों में से महज पांच महिलाओं ने जीते थे. तोक्यो में वे अब तक भारत के पांच में से तीन पदक जीत चुकी हैं. महिला हॉकी टीम ने पहली बार सेमीफाइनल में धमाकेदार प्रवेश किया. यहां तक कि जो महिलाएं जीत नहीं सकीं—तलवारबाज भवानी देवी, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और गोला फेंक एथलीट कमलप्रीत कौर—वे भी पूरे जोश और दमखम से लड़ीं.

भारतीय महिलाओं ने बेशक अपने पुरुष समकक्षों को पीछे छोड़ दिया है. उनकी कामयाबियों की साख तब और बढ़ जाती है जब उनमें से किसी का भी सफर आसान नहीं रहा. महिला हॉकी टीम की जोशीली कप्तान रानी रामपाल की जिंदगी बहुत जद्दोजहद से भरी थी और वे खेल में आईं ही इसलिए कि अपने परिवार के लिए पक्का घर बना सकें और दो जून की रोटी जुटा सकें. नन्ही कद-काठी की मीराबाई चानू तोक्यो में रजत पदक जीतने से पहले लकड़ियां बीना करती थीं ताकि अपने गांव के घर में आग जलाकर सर्द रातों को गर्म कर सकें. लवलीना बोरगोहेन के गांव में उनके घर तक पक्की सड़क नहीं थी, पर इससे मुक्केबाजी में कांस्य तक पहुंचने का उनका जज्बा जरा कम नहीं हुआ. ये तंगहाली की हृदयविदारक कहानियां हैं, जिनसे महिला एथलीटों की मुश्किलों और संघर्ष की थोड़ी झलक मिलती है.

पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता, जो 41 वर्षों में इस खेल में भारत का पहला पदक है. महिला टीम का सेमीफाइनल में प्रवेश उस खेल में नई जान आने के उत्साहवर्धक संकेत हैं जिसमें कभी भारत का दबदबा हुआ करता था. इसके अलावा, रवि कुमार दहिया ने पुरुषों की 57 किग्रा कुश्ती के फाइनल में अपना पदक पक्का किया.

हमारी आवरण कथा 'बेटियों का दमखम' तोक्यो में हमारे प्रदर्शन की पड़ताल करती है. यह कंसल्टिंग एडिटर बोरिया मजूमदार ने लिखी है. हमारे यहां प्रतिभा या डीएनए की कमी नहीं. कमी है तो उसे फलीभूत करने की. हमें वही करना होगा जो खेलों के महाशक्ति देशों ने किया—खेल संस्कृति का निर्माण. वैसे ही जैसे हमने सैकड़ों खेल अकादमियां बनाकर और स्कूल से लेकर लीग स्तर और फिर राष्ट्रीय टीम तक बेहतरीन खिलाड़ियों को छांटने-चुनने की प्रक्रिया कायम करके क्रिकेट में किया है. हमें ओलंपिक खेलों का 'क्रिकेटीकरण' करना होगा. इसमें राज्य सरकारों को आगे आने होगा. मसलन, भारत की पुरुष और महिला हॉकी टीमें ओडिशा सरकार के समर्थन के बूते बेहतरीन कोच जुटा पाईं और विश्वस्तरीय संस्थाओं में प्रशिक्षण ले पाईं.

हम कई देशों से सीख सकते हैं. पुरुष और महिला दोनों तीरअंदाजी में पूरी तरह हावी दक्षिण कोरिया पदक जीतने की संभावना से ओतप्रोत अपने खिलाड़ियों को सभी मौसमों में कारगर स्थितियों और खचाखच भरे स्टेडियमों में प्रशिक्षण देता है, ताकि वे मुकाबलों के तनाव के अनुरूप अपने को ढाल सकें. सात खेलों—वेटलिफ्टिंग, तैराकी, जिम्नास्टिक्स, गोताखोरी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और निशानेबाजी—पर अपने एकाग्र फोकस से चीन ने स्वर्ण पदकों का अच्छा अंबार बटोर लिया और पदक तालिका में अमेरिका से आगे निकल गया. ब्रिटेन ने 1996 के अटलांटा ओलंपिक में एक ही पदक जीता था. देश ने 1997 से लॉटरी का पैसा ब्रिटिश खेलों में लगाना शुरू किया और डेढ़ दशक के भीतर ब्रिटिश टीम ने लंदन 2012 में 29 स्वर्ण पदक जीते.

अपने पदकों की संभावनाओं में इजाफे के लिए हमें तैराकी और एथलेटिक्स सरीखे व्यक्तिगत खेलो में अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी. खेलों को विलासिता मानने का अपना रवैया हमें तजना होगा. खेल कई तरह से राष्ट्र की संस्कृति की झलक देते हैं. खेलों में कामयाबी के लिए मजबूत संस्थाओं, अनुशासन, प्रतिबद्धता और जीतने की इच्छाशक्ति की जरूरत है. पेरिस के 2024 ओलंपिक तीन साल दूर हैं और 2018 लॉस एंजेलिस गेम्स अब से सात साल दूर. यही वक्त है जब हम कमर कस लें और खेलों में नई जान फूंकने की सुव्यवस्थित योजना शुरू करें. आखिर हम 1.3 अरब लोगों का देश हैं. राष्ट्रीय गौरव बढ़ाने के लिए ओलंपिक में कामयाबी से बेहतर कोई दूसरा तरीका नहीं है. राष्ट्रवाद और अंतरराष्ट्रीय कद बढ़ाने के तमाम संदिग्ध अफसानों से यह कहीं बेहतर है. अगर हम तत्काल और ईमानदारी से योजना बनाकर आगे नहीं बढ़ते तो खेलों में कीर्ति और राष्ट्रीय गौरव की हमारी उम्मीदें ओलंपिक के छल्लों में अटकी रहने को अभिशप्त रहेंगी.

अरुण पुरी

(अरुण पुरी)

इंडिया टुडे

www.indiatodayhindi.in

चेयरमैन और प्रधान संपादक: अरुण पुरी
वाइस चेयरपर्सन: कली पुरी
ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर: दिनेश भाटिया
ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर: राज चेंगप्पा
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर: मनोज शर्मा
एडिटर: अंशुमान तिवारी
सीनियर एडिटर: मोहम्मद वक़ास
एसोसिएट एडिटर: शिवकेश मिश्र, शुभम शंखधर, आशीष मिश्र (लखनऊ)
असिस्टेंट एडिटर: मनीष दीक्षित, सुजीत ठाकुर
राज्य ब्यूरो:, अमिताभ श्रीवास्तव (पटना), रोहित परिहार (जयपुर), एम.जी. अरुण (मुंबई), राहुल नरोन्हा (भोपाल), अमरनाथ के. मेनन (हैदराबाद)
ग्रुप क्रिएटिव एडिटर: नीलांजन दास
एसोसिएट आर्ट डायरेक्टर: चंद्रमोहन ज्योति
असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर: असित रॉय
ग्रुप फोटो एडिटर: बंदीप सिंह
फोटो डिपार्टमेंट: यासिर इकबाल, राजवंत रावत, चंद्रदीप कुमार, मंदार सुरेश देवधर (मुंबई)
चीफ फोटो रिसर्चर: प्रभाकर तिवारी
प्रिंसिपल फोटो रिसर्चर: सलोनी वैद
प्रोडक्शन चीफ: अभिनव पुगला
एसोसिएट पब्लिशर: अनिल फर्नांडीस
इंपैक्ट टीम
सीनियर जनरल मैनेजर: जीतेंद्र लाड (वेस्ट)
जनरल मैनेजर: मयूर रस्तोगी (नॉर्थ), उपेंद्र सिंह (बेंगलूरू)
डिप्टी जनरल मैनेजर: इंद्रनील चटर्जी (ईस्ट)
ग्रुप चीफ मार्केटिंग ऑफिसर: विवेक मल्होत्रा
सेल्स एवं ऑपरेशन
सीनियर जनरल मैनेजर: दीपक भट्ट (नेशनल सेल्स)
जनरल मैनेजर: विपिन बग्गा (ऑपरेशंस)
डिप्टी जनरल मैनेजर: राजीव गांधी (नॉर्थ)
रीजनल सेल्स मैनेजर: सैयद आसिफ सलीम (वेस्ट)
डिप्टी रीजनल सेल्स मैनेजर: एस. परमशिवम (साउथ)
सीनियर सेल्स मैनेजर: पीयूष रंजन दास (ईस्ट)

INDIA TODAY GROUP

वर्ष: 35; अंक: 38; 12-18 अगस्त 2021; प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित

- **संपादकीय कॉर्पोरेट कार्यालय:** लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, इंडिया टुडे ग्रुप मीडियाप्लेक्स, एफसी-8, सेक्टर 16-ए, फिल्म सिटी, नोएडा-201301, फोन: 0120-4807100;
- **ग्राहकी चंदा भेजें:** इंडिया टुडे (हिंदी), पो. बॉक्स 114, नई दिल्ली-110001
- **ग्राहक सेवा:** कस्टमर केयर, इंडिया टुडे ग्रुप, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301, टोल फ्री फोन नं. 1800 1800 100 (बीएसएनएल/एमटीएनएल लाइनों से) फोन: दिल्ली, फरीदाबाद से (95120) 2479900; शेष भारत से (0120) 2479900. (सोम से शुक्र-सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक), फैक्स: (0120) 4078080. ई-मेल: wecare@intoday.com
- **सर्कुलेशन कार्यालय:** लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301
- **इंपैक्ट कार्यालय:** 1201, 12वां तल, टावर 2ए, वन इंडियाबुल्स सेंटर, (जुपिटर मिल्स) एस.बी. मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम)-मुंबई-400013. फोन: 022-66063355 फैक्स: 022-66063226
- **क्षेत्रीय विज्ञापन कार्यालय:** ए1-ए2, एनके सेंटर, विनुज्य निकुंज, उद्योग विहार, फेज-5, गुड़गांव, हरियाणा, फोन: 0124-4948400;
- 201-204 रिचमंड टावर्स, द्वितीय मंजिल, 12 रिचमंड रोड, बंगलुरु-560 025 फोन: 2212448, 226233, टेलेक्स: 0845-2217 INTO IN. फैक्स: 080-2218335.
- रजिस्टर्ड कार्यालय: एफ-26, फर्स्ट फ्लोर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

- लिविंग मीडिया इंडिया लि. विश्व भर में सर्वाधिकार सुरक्षित. किसी भी रूप में सामग्री की नकल प्रतिबंधित. इंडिया टुडे अनिमंत्रित प्रकाशन सामग्री को लौटाने की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता.
- सभी विवादों का निबटारा दिल्ली/नई दिल्ली की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों और फोरमों में किया जाएगा.

- **लिविंग मीडिया इंडिया लि. के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक मनोज शर्मा द्वारा एफ-26, फर्स्ट फ्लोर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और थॉमसन प्रेस इंडिया लि., 18-35, माइलस्टोन, दिल्ली-मथुरा रोड, फरीदाबाद-121 007 (हरियाणा) में मुद्रित.**
संपादक: राज चेंगप्पा

सुर्खियां
मेहमान का पन्ना: पोर्न और पूर्वाग्रह
पेज 6

अर्थात्: गए रोजगार बनाम नए रोजगार
पेज 15

भीतर

फुरसत
सिनेमा: इससे बढ़कर कुछ नहीं
पेज 48

सवाल-जवाब/नागेश कुकनूर: हाशिए वालों का हमदर्द
पेज 50

भाजपा
16 पार्टी की सूरत बदलने के नए सूत्र
अपनी 'ब्राह्मण-बनिया' पार्टी की छवि को बदलने की कोशिश कर रही है भाजपा.

टीकाकरण
20 सार्वजनिक स्वास्थ्य निजी समस्याएं
आपूर्ति में सुधार के बावजूद निजी क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों का प्रदर्शन कमजोर है.

उत्तर प्रदेश
24 मांगें मनवाने का मौसम
चुनावों से पहले कर्मचारियों के साथ-साथ अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों के लिए मोर्चा खोला.

प्रतिरक्षा
39 आयुध कारखानों का कायापलट
सभी 41 आयुध कारखानों को सात नए सार्वजनिक रक्षा उपक्रमों में ढालने से सैन्य उद्योग को जीवनदान मिलेगा?

वन्य जीव
45 जानवरों का ख्याल
बिजली के तार जमीन के नीचे बिछाने और पशु ओवरपास बनाने सरीखे उपायों की सुध अब आई.

इंडिया टुडे
इंडिया टुडे मैगजीन मिलने में दिक्कत हो रही है?
9311409555 पर नाम पता या 'हेलो' संदेश भेजें.
या मेल करें: Moreinfo@intoday.com
हम आपसे संपर्क कर लेंगे.

आवरण: **नीलांजन दास**, डिजिटल इमेजिंग: **अमरजीत सिंह नागी**
आवरण फोटो: बीएफआइ, **पारस मेंदीरत्ता/एसएआइ**, और **गेट्टी इमेजेज**

पाठकों के लिए सूचना: कभी-कभी आपको इंडिया टुडे पत्रिका में 'इम्पैक्ट फीचर' या 'एडवरटोरियल' या 'फोकस' के पन्ने नजर आएंगे. ये विज्ञापन होंगे और इन्हें बनाने में पत्रिका के संपादकीय स्टाफ शामिल नहीं होते.

INDIA TODAY GROUP

पाठकों को सलाह दी जाती है कि पत्रिका में प्रकाशित किसी भी वस्तु, सेवा या व्यक्ति के विज्ञापन और प्रचार से संबंधित सामग्री से वचनबद्धता कायम करने, पैसा भेजने या खर्च करने से पहले उचित जांच-पड़ताल कर लें. विज्ञापनदाताओं के किसी भी दावे का उत्तरदायित्व इंडिया टुडे ग्रुप का नहीं है. ऐसे किसी भी तरह के दावों को विज्ञापनदाता अगर नहीं पूरा करता है तो इंडिया टुडे ग्रुप के प्रकाशनों के मुद्रक, प्रकाशक, एडिटर-इन-चीफ और एडिटर इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे.

INDIA TODAY

BREAKING NEWS

JUST A TAP AWAY

DOWNLOAD THE APP NOW

AVAILABLE ON

बिहार: आत्मनिर्भरता की ओर
पेज 9

राजस्थान: जनजातियों और हिंदुत्व की जद्दोजहद
पेज 12

सुर्खियां

उत्तराखंड: पहाड़ पर आप का करंट
पेज 14

Only books magazine

इलस्ट्रेशन: सिद्धांत जुमडे

मेहमान का पन्ना

पोर्न और पूर्वाग्रह

अमृता नारायणन

पिछले महीने पुलिस ने पोर्न (अश्लील सामग्री) की तस्करी के आरोप में राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया. कुंद्रा ने कहा कि वह इरॉटिक (कामोत्तेजक) सामग्री बांट रहे थे, पोर्नोग्राफिक नहीं. चूंकि हम विवादित सामग्री के ब्योरों से अनजान हैं, हमें नहीं पता मुद्दा क्या है, पर यह याद दिलाता है कि कानून पोर्नोग्राफी और इरॉटिका के बीच फर्क को लेकर संवेदनशील नहीं है. कुंद्रा के मामले में लगाई गई सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 67ए 'खुल्लमखुल्ला सामग्री' बांटने पर रोक लगाती है. यह कानूनी भाषा अपने रजामंद जोड़ीदार के साथ खुल्लमखुल्ला यौन होम वीडियो खरीदने या गिरोह के साथ सामूहिक बलात्कार करने से पहले यौन हिंसक वीडियो प्राप्त करने के बीच फर्क नहीं करती.

पोर्नोग्राफिक सामग्री बांटने के खिलाफ कानून इरादतन भले रक्षा करता हो, पर अपने असर में यह जनता को नादान मानकर बर्ताव करता है. पोर्नोग्राफिक सामग्री के वितरण को वैधानिक दायरे में लाकर कानून असल में इस सार्वजनिक चर्चा पर नियंत्रण करता है कि यौनिकता के दायरे में क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं. मसलन, अगर कुंद्रा के मामले में मीडिया ने निषिद्ध सामग्री के इरॉटिक या पोर्नोग्राफिक होने पर बहस की गरज से उसका स्वरूप बताया है, तो पूरी संभावना है कि ऐसी रिपोर्ट खुद कानून का उल्लंघन हो.

पोर्नोग्राफी के प्रसार के कानून के नतीजतन कुंद्रा जैसे मामलों का मीडिया कवरेज 'कॉप्स ऐंड रॉबर्स' के शैलीगत रूपक से चिपके रहने को बाध्य है. पोर्नोग्राफी की तस्करी के मामले बार-बार दोहराए गए दृश्यों वाले धारावाहिकों की तरह एक जैसे तरीके से पेश किए जाते हैं जिसमें मुस्तैद पुलिस अफसर पोर्नोग्राफी के तस्करों का 'भांडा फोड़' देते हैं. ऐसी तुरत-फुरत प्रतिक्रिया इस लंबे-चौड़े बौद्धिक सोच-विचार की संभावना पर पानी फेर देती है कि समाज के तौर पर खुल्लमखुल्ला यौन सामग्री के साथ हमारा रिश्ता क्या होना चाहिए. सार्वजनिक चर्चा निजी ईको चैंबरों में चले जाने को मजबूर हो जाती है. सोच-विचार को इस तरह तहखानों में कैद करना खुल्लमखुल्ला यौन सामग्री में मौजूद विविध संभावनाओं को

Sunfeast YiPPee! noodles

MOOD Masala

Enduring Value

MAIN MASALA FOR TASTE

+

MOOD MIX FOR YOUR MOOD

Match your mood with YiPPee! Mood Masala noodles, packed with 2 masala sachets!

Creative Visualization | Serving Suggestion

कम कर देता है. यह हमें अपनी यौन रुचियों की सामूहिक भिन्नताओं को जानने और प्रोत्साहित करने से रोकता है.

पोर्नोग्राफी और इरॉटिका के फर्क को नफीस बनाने की सामान्यीकृत कोशिशों का हश्र निरपवाद रूप से यौन रुचि के एक रूप पर दूसरे के हावी होने में होता है. आखिरकार यह बेहद व्यक्तिपरक फर्क है. बीडीएसएम पोर्न के ग्राहकों को वह सब खूबसूरत और इरॉटिक लगता है जो रोमांस पोर्न के ग्राहकों को पोर्नोग्राफिक लगता है. इसलिए इसका कोई वस्तुपरक पैमाना नहीं हो सकता कि क्या पोर्नोग्राफिक या इरॉटिक है, लेकिन सामग्री और संदर्भ अहम जान पड़ते हैं.

पोर्नोग्राफिक सामग्री तात्कालिकता से परिभाषित होती है. मरियम-वेबस्टर शब्दकोश पोर्नोग्राफी को ऐसे परिभाषित करता है, ''कृत्यों का सनसनीखेज निरूपण ताकि तीव्र, भावनात्मक प्रतिक्रिया जगाई जा सके.'' पोर्न फास्ट फूड है और इरॉटिका धीमे-धीमे, स्वाद ले-लेकर खाने का अनुभव. मरियम-वेबस्टर यह भी कहती है: पोर्नोग्राफी ऐसी सामग्री है जिसका ''इरादा यौन उत्तेजना उत्पन्न करना'' है, जबकि इरॉटिक को ''यौन प्रेम या इच्छा जगाने के प्रति समर्पित या प्रवृत्त'' सामग्री के तौर पर परिभाषित किया गया है. यह इरॉटिक सामग्री से पोर्नोग्राफी में फर्क करता मालूम देता है, पर इसके अलावा इरॉटिक ऐसे भावनात्मक शब्दों से भी जुड़ा है जिनका तात्पर्य कामवासना के साथ-साथ जुड़ाव और गहरी चाह भी है.

वाकई, आमोद-प्रमोद के तेज बनाम धीमे साधन होने के अलावा, पोर्नोग्राफी लोकप्रिय तौर पर इरॉटिका के मुकाबले मानवीय एहसासों का कम लिहाज करने के लिए जानी जाती है. सिर्फ यही नहीं कि व्यक्ति कहीं भी ले जाकर और अपनी सुविधा से आमोद-प्रमोद के मॉडल का इस्तेमाल कर सकता है, पोर्नोग्राफी देखने या सुनने वाले को तत्काल और तैयारशुदा सुख देकर किसी खास व्यक्ति के इंतजार की तकलीफ से बख्श देती है. पोर्नोग्राफी की अच्छी बात यौनिकता की स्वतंत्रता और स्वायत्तता है, जिसमें तमाम किस्म की संभावनाएं हैं जो एक ही पार्टनर के साथ मुमकिन नहीं हो सकती हैं.

संदर्भ भी पोर्नोग्राफी और इरॉटिका में फर्क करता नजर आता है. पोर्नोग्राफी पर आपत्ति जताने वाले भी इससे सहमत नजर आते हैं कि सेक्सुअली और भावनात्मक रिश्ते की पूर्ति के संदर्भ में किसी जोड़े का पोर्न देखना 'इरॉटिक' और स्वीकार्य है. पोर्न को भविष्य के असली दुनिया के अनुभव के तौर पर पूर्वाभ्यास भी माना जाता है. अगर हम पोर्नोग्राफी को अवैध बनाते हैं, तो हम कह रहे होते हैं कि लोग अपने अन्य यौन स्वाद को नहीं तलाशें. अगर यह वैध होता तो हम इंडस्ट्री को विविध रुचि मुहैया करने के लिए, और उससे भी बेहतर, पहली बार वालों के लिए सही सेक्स एजुकेशन मुहैया कराने के लिए सहमत करा सकते थे.

पोर्नोग्राफी की आलोचनाएं ऐतिहासिक तौर पर नारीवाद से आईं, जिसमें कट्टर नारीवादी रोबिन मॉर्गन ने ये मशहूर लफ्ज कहे थे कि ''पोर्नोग्राफी थ्योरी है, बलात्कार प्रैक्टिस है.'' उनके इन शब्दों ने पोर्नोग्राफी में महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा की जायज चिंता को

अगर पोर्न वैध होता तो हम इंडस्ट्री को विभिन्न तरह की रुचियों, और उससे भी बढ़कर, पहली बार वालों के लिए सेक्स एजुकेशन मुहैया कराने के लिए सहमत करा सकते थे

सामने रखा. इस आपत्ति के मूल में यह चिंता थी कि हिंसक पोर्नोग्राफी देखने से हिंसक और अपमानजनक व्यवहारों को असल दुनिया में आजमाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी. मगर व्यवहार पर पोर्नोग्राफिक सामग्री के प्रभाव पर की गई रिसर्च साफ और भरोसेमंद तरीके से दोनों के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं करतीं. कुछ अध्ययन तो कहते हैं कि हिंसक पोर्नोग्राफी देखना इतना संतोषजनक भी हो सकता है कि असल दुनिया में हिंसक यौनिकता के असल कृत्य कम हो जाएं.

तब से नारीवाद पोर्न की अपनी आलोचना को आम एतराज से हटाकर एक मांग विशेष पर ले आया. वह यह कि पोर्न में औरतों की व्यक्तिपरकता और इरॉटिक रुचियों की झलक होनी चाहिए. इसका अर्थ कुछ निश्चित किस्म के पोर्न को खारिज करना नहीं है. *साइबरसेक्सी* (2018) में ऋचा कौल पडते की रिसर्च हमें बताती है कि भारतीय महिलाओं की दिलचस्पी भिन्न-भिन्न पोर्नोग्राफिक सामग्री में है. 2018 में *लंदन रिव्यू ऑफ बुक्स* में लिखते हुए अमिया श्रीनिवासन ने पोर्नोग्राफी पर मौजूदा नारीवादी रुख दर्ज किया: ''अगर एक औरत कहती है कि उसे पोर्न में काम करना, या आदमियों के साथ सेक्स करने के लिए धन मिलना, या रेप की फंतासियों में लिप्त होना, या ऊंची ऐड़ी की जूतियां पहनना अच्छा लगता है—और यहां तक कि ये चीजें उसे अपने नारीवादी चाल-चलन के हिस्से के तौर पर अच्छी ही नहीं बल्कि मुक्तिदायक भी लगती हैं—तो नारीवादी होने के नाते हमें उस पर विश्वास करने की जरूरत है.''

नारीवादी पहले के मुकाबले पोर्नोग्राफी के प्रति अब भले ही खुले हों, लेकिन पोर्नोग्राफी की सीमाएं उन्हें अब भी खिजाती हैं. पोर्न का बहुत ज्यादा इस्तेमाल और रिश्तों के एवज में पोर्न का इस्तेमाल जितना नारीवाद की चिंता का विषय है उतना ही मनोविज्ञान का भी. गौण व्यंजन के बजाए मुख्य व्यंजन के तौर पर पोर्नोग्राफी उपयोगकर्ता को आत्मकामी, स्वनिर्देशित अंदरूनी दुनिया में कैद करके उसकी अंतरंगता और जुड़ाव की क्षमता कम कर सकती है. ऐसी अंदरूनी दुनिया में, जहां दूसरे व्यक्ति की आत्मीयता को नियमत: अनदेखा या नष्ट किया जाता है.

हम पोर्नोग्राफी को लेकर खफा होते हैं तो इसका अर्थ है कि हमने यौन रुचि में असहनीय फर्क देखा है जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते. मसलन, औरतों की व्यक्तिपरकता को मिटाना ऐसी यौन रुचि का एक उदाहरण है, जिसे कई बर्दाश्त नहीं कर सकते. यह भी विचार योग्य है कि पोर्नोग्राफिक के काम को—यानी दक्षता और तेजी से पहुंचाया गया लक्ष्य निर्देशित यौन आनंद जो दूसरे लोगों की भावनाओं से स्वतंत्र हो—पुलिसिया नियंत्रण की जरूरत शायद न हो, हो सकता है कि यह यौन रुचि पर पुलिसिया नियंत्रण की ही उपज हो.

सामाजिक तौर पर मीडिया यह बतलाता नजर आता है कि हम दो खानों में बंटे हैं: ऐसे लोग हैं जो दृश्य यौन उत्तेजना के आनंद में लिप्त हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो उनके बारे में पढ़ना, उनका पीछा करना, उन्हें खोज निकालना और सजा देना पसंद करते हैं. जहां पोर्नोग्राफी की भूख पर पुलिसिया नियंत्रण है, वहीं अश्लील सामग्री देखने वालों को पकड़ने, उनके बारे में बताने की भूख को हाथोहाथ लिया जाता है. फ्रांसीसी मनोविश्लेषक जाक लाकां हमें याद दिलाते हैं कि सुपरईगो (पराअहम्) अपने स्वभाव से ही अश्लील है, यह हमेशा और ज्यादा अपराधों का भूखा है.

अमृता नारायणन मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषक हैं. उनकी किताब 'इन अ रैप्चर ऑफ डिस्ट्रेस—हाऊ सेक्सुएलिटी इज कंस्ट्रक्टेड इन मॉडर्न इंडिया' ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से आने वाली है.

सोनू किशन

साथ-साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह (बाएं)

Only books magazine

बिहार

आत्मनिर्भरता की ओर

अमिताभ श्रीवास्तव

अगड़ी जाति (भूमिहार) के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को, 31 जुलाई को जनता दल (यूनाइटेड) (जद-यू) का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनकर और 2 अगस्त को पेगासस जासूसी विवाद की जांच की मांग करके, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संकेत दिए कि उनकी पार्टी न केवल सामाजिक आधार बढ़ा रही है, बल्कि अपनी तर्कसंगत छवि को कायम रखना चाहती है. इसके साथ ही, नीतीश कुमार भाजपा के ऐसे पहले सहयोगी बन गए हैं जिन्होंने पेगासस जासूसी विवाद की जांच की मांग की है. मुख्यमंत्री ने 12 जुलाई को उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति को खारिज किया, फिर 24 जुलाई को उन्होंने जाति आधारित जनगणना की मांग की, जिसके लिए केंद्र ने 20 जुलाई को मना कर दिया था. लब्बोलुबाब यह है कि मुख्यमंत्री ने दिखाया कि वे एक महीने में तीन अहम मुद्दों पर भाजपा के साथ इत्तेफाक नहीं रखते हैं.

वर्ष 2020 के चुनावों के बाद विधानसभा में जद (यू) की ताकत कम हो गई है और पार्टी में बड़ा मंथन चल रहा है. यह सब दिसंबर, 2020 में शुरू हुआ जब नीतीश ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ दिया और आर.सी.पी. सिंह को अपना उत्तराधिकारी चुना. माना गया था कि नीतीश अपना पूरा ध्यान सरकार चलाने पर केंद्रित रखना चाहते हैं और संगठन के विस्तार का काम आर. सी.पी. सिंह करेंगे. दो महीने बाद मार्च, 2021 में उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी रालोसपा का जद (यू) में विलय कर लिया. जुलाई में, जद (यू) ने केवल एक मंत्री पद के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होना स्वीकार किया और महीने के आखिर में मुंगेर के सांसद ललन सिंह पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए. ललन सिंह को अध्यक्ष चुनना, पार्टी के सामाजिक दायरे को बढ़ाने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा गया. ललन सिंह को उनकी वफादारी के लिए पुरस्कृत करने के अलावा, उनका उत्थान जद (यू) की उस 'आत्मनिर्भर अभियान' का भी हिस्सा है जिसके तहत पार्टी 'लव-कुश' से परे अन्य जाति वर्गों में भी पैठ बढ़ाना चाहती है.

अक्तूबर 2003 में गठित जद (यू) में ललन सिंह के अध्यक्ष बनने से पहले केवल चार अध्यक्ष रहे हैं—जॉर्ज फर्नांडीस, शरद यादव, नीतीश कुमार और आर.सी.पी. सिंह. फर्नांडीस ईसाई थे तो अन्य तीन अध्यक्ष ओबीसी समुदायों से हैं. ललन सिंह जिस भूमिहार जाति से आते हैं, वह संख्यात्मक रूप से अहम और सामाजिक रूप से बहुत प्रभावशाली है तथा लगभग सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मौजूद है. हालांकि ललन सिंह को अभी अपने समुदाय के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरना बाकी है, पर राज्य के कई हिस्सों में उनका प्रभाव है. संयोग से, 2011-12 में बिहार के सवर्ण आयोग के लिए किए गए एक पूर्व सर्वेक्षण के अनुसार, राज्य की कुल आबादी का लगभग पांचवां हिस्सा ऊंची जातियों का है जिनमें हिंदू (ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ) और मुस्लिम (शेख, सैयद और पठान) दोनों शामिल हैं.

जद (यू) को उम्मीद है कि ललन सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने से उसे अपना सामाजिक आधार बढ़ाने में मदद मिलेगी

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का हिस्सा होने के नाते, जद (यू) को हमेशा एक ऐसी पार्टी के रूप में देखा गया है जो अपनी अति पिछड़ी जातियों (ईबीसी) और महादलित वोटों को भाजपा को हस्तांतरित करती है और बदले में, भगवा पार्टी से बड़े पैमाने पर अगड़ों और वैश्य समुदाय का वोट हासिल करती है.

लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में इसमें बहुत उलट-फेर हो गया. तब भाजपा को जद (यू) के पारंपरिक मिले, लेकिन यह अगड़ी जातियों का वोट नीतीश की पार्टी को नहीं दिला सकी. इससे भी बदतर, जब भाजपा नेतृत्व ने जद (यू) के विरोधी चिराग पासवान को सीधे-सीधे निशाने पर लेने से इनकार कर दिया, तो ऐसी अफवाहें गर्म थीं कि भाजपा जद (यू) की हैसियत कम करके सत्ता में अपने मनमाफिक साझेदारी व्यवस्था बनाना चाहती है. माना जाता है कि 2020 के चुनावों में पासवान के नीतीश विरोधी अभियान के साथ-साथ इस धारणा ने भी अगड़ों को जद (यू) से दूर कर दिया.

ऐसे में अब जद (यू) अगड़ी जाति के वोटरों को वापस अपने साथ लाने के लिए चतुराई से कदम आगे बढ़ाना चाहती है. बिहार में अगला चुनाव 2024 में होगा लेकिन पार्टी इस समय का उपयोग अपना सामाजिक आधार बनाने के लिए करना चाहती है. दरअसल, विधानसभा में अपनी पार्टी की ताकत 2015 के 71 से गिरकर 2020 में 43 सीट हो जाने के बाद, नीतीश कुमार ने तय कर लिया है कि अब वे गठबंधन सहयोगियों पर बहुत निर्भर नहीं रहेंगे.

जद (यू) को उम्मीद है कि ललन सिंह की पदोन्नति से पार्टी को अपने सामाजिक आधार का विस्तार करने और उच्च जातियों के अधिक नेताओं को समायोजित करने में मदद मिलेगी. जाहिर है, ललन सिंह को अब एक बड़ी लड़ाई की कमान संभालनी है. ■

मध्य प्रदेश

और कितना इंतजार?

प्रदेश में शहरी निकायों और पंचायत चुनावों में लगभग दो साल की देरी हो चुकी है. अब भी इसको लेकर राज्य सरकार हिचक रही

Only books magazine

राहुल नरोन्हा

मध्य प्रदेश में एक के बाद एक अलग-अलग सियासी दलों की सरकारों ने अनुकूल चुनावी परिणाम हासिल करने के इरादे से शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की प्रक्रिया के साथ काफी छेड़छाड़ की है. इसके कारण शहरी निकायों और पंचायत चुनाव कराने में लगभग दो साल की देरी हुई है. इसके अलावा, शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों के चुनावों में अत्यधिक देरी ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिसमें 73वें और 74वें संशोधन के रूप में संवैधानिक शासनादेश भी खतरे में है.

पिछले हफ्ते, सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका का जवाब देते हुए, राज्य सरकार ने अदालत को सूचित किया कि निकट भविष्य में शहरी निकाय चुनाव कराना संभव नहीं है. ऐसे में इस कदम के पीछे संभावित राजनैतिक कारण क्या हैं और देरी किन कारणों से हुई है?

मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 के अनुसार, नगर निकायों के चुनाव उनका कार्यकाल समाप्त होने से 6 महीने पहले होने चाहिए. अधिकांश निर्वाचित निकायों का कार्यकाल दिसंबर 2019 में समाप्त हो गया. उस समय, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एक कदम उठाया था जिसका उद्देश्य पार्टी को नगर निकाय चुनाव जीतने में मदद करना था. पार्टी के रणनीतिकारों का मानना था कि शहरी क्षेत्रों में भाजपा का दबदबा रहता है, इसलिए कांग्रेस शहरी निकायों में सीधे चुनाव के रास्ते पर्याप्त संख्या में सीटें नहीं जीत पाएगी. इसलिए, यह निर्णय लिया गया कि स्थानीय चुनावों की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले कानून मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1956 में संशोधन किया जाए और फिर से अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली लाई जाए.

दूसरे शब्दों में कहें तो इसमें मतदाता नगरसेवकों का चुनाव करते हैं और वे नगरसेवक शहरी निकायों के अध्यक्ष या महापौर को चुनते हैं. यह माना गया था कि राज्य में कांग्रेस सत्ता में है इसलिए अप्रत्यक्ष चुनावों को प्रभावित कर लेगी और केवल पार्टी का समर्थन करने वाले लोग ही निकायों के प्रमुख चुने जाएंगे. भाजपा के विरोध के बावजूद इस आशय का एक संशोधन पारित किया गया. पड़ोसी छत्तीसगढ़ ने भी ऐसा ही किया और वांछित परिणाम हासिल किए.

छत्तीसगढ़ में शहरी निकाय चुनावों में कांग्रेस ने अप्रत्यक्ष चुनाव के बाद शानदार जीत हासिल की. कांग्रेस सरकार एक कदम आगे बढ़ी. वह भोपाल नगर निगम जो कि इंदौर के बाद राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहरी निकाय है, को विभाजित करना चाहती थी क्योंकि उसे लगा कि वह दो विभाजित निकायों में से कम से कम एक को जीतने में जरूर सक्षम होगी. कागज पर एक प्रस्ताव तैयार किया गया था, लेकिन इसके लागू होने से पहले ही, मार्च 2020 में, कांग्रेस सरकार गिर गई और शिवराज सिंह चौहान सत्ता में लौटे.

भाजपा के अंदरुनी सूत्रों का कहना है कि पार्टी को लगता है कि उसे अप्रत्यक्ष चुनाव तरीके से ही आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि अब पार्टी सत्ता में है

भाजपा सरकार शुरू में कोविड की पहली लहर से जूझ रही थी और जब नवंबर में 28 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव हुए, तो पार्टी ने शहरी निकाय चुनाव कराने की तैयारी भी शुरू कर दी. भाजपा सरकार 2020 में एक अध्यादेश लाई और अप्रत्यक्ष चुनावों को सक्षम बनाने के लिए नगर निगम अधिनियम 1956 में किए गए संशोधन को निष्प्रभावी करते हुए उन्हें पूर्ववत कर दिया. हालांकि, अध्यादेश अब समाप्त हो चुका है और भाजपा के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि पार्टी को लगता है कि उसे अप्रत्यक्ष चुनाव तरीके से ही आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि अब भाजपा सत्ता में है. 2019 में, सत्ता में होने के कारण कांग्रेस अप्रत्यक्ष चुनावों के जरिए अधिकांश नगर निकायों को अपने कब्जे में लेने के जिन फायदों की आस में थी, वे सारे फायदे अब सत्ता में बैठी भाजपा उठा सकती है.

सूत्रों ने यह भी कहा कि भाजपा मान रही है कि रोस्टर के माध्यम से सीटों का जिस प्रकार

एएनआइ

कहीं और

इस साल फरवरी में उज्जैन में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (बाएं से दूसरे) पार्टी के अन्य नेताओं के साथ

यूं फंसा पेच

- मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 के अनुसार, नगर निकायों के चुनाव उनका कार्यकाल समाप्त होने से छह महीने पहले होने चाहिए. लेकिन अधिकांश निर्वाचित निकायों का कार्यकाल दिसंबर, 2019 में खत्म हो चुका है
- मध्य प्रदेश की पूर्व कांग्रेस सरकार ने नगर निगम अधिनियम, 1956 में संशोधन किया और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाने का फैसला किया
- भाजपा सरकार साल 2020 में अध्यादेश लाई और उस संशोधन को निष्प्रभावी कर दिया
- आरक्षण के मसले पर नगर निकायों के चुनावों का मसला न्यायालय में चल रहा है
- चुनावों में देरी निकायों को कमजोर बनाती है और यहां जानबूझकर देरी की जा रही है

आरक्षण किया गया है, वह विभिन्न प्रमुख शहरी निकायों में अच्छे उम्मीदवारों को खड़ा करने के लिए पार्टी के अनुकूल नहीं था. उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई थी और मार्च 2021 में उच्च न्यायालय ने तब तक के लिए चुनाव पर रोक लगा दी जब तक कि आरक्षण की व्यवस्था से संबंधित संदेह दूर नहीं हो जाते. इससे पहले उच्च न्यायालय में एक और याचिका दायर कर शहरी निकाय चुनाव को अविलंब कराने की मांग की गई थी. फरवरी में उच्च न्यायालय ने चुनाव प्रक्रिया शुरू कराने का आदेश दिया था. उच्च यायालय में दायर एक अन्य याचिका में आरक्षण को चुनौती दी गई और 15 मार्च को अदालत ने आरक्षण प्रक्रिया में संदेह के कारण चुनाव पर रोक लगा दी. राज्य सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दायर की है और बताया है कि मौजूदा नियमों के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था की गई थी.

कोविड की दूसरी लहर ने अप्रैल और मई में राज्य को बुरी तरह से प्रभावित किया और शहरी निकायों में चुनाव की बात सरकार की प्राथमिकताओं में पीछे चले गए. हालांकि, तीन विधानसभा क्षेत्रों और एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारियां होने के साथ, शहरी निकाय चुनावों पर भी ध्यान केंद्रित हो गया है.

नगर प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मीडिया को बताया कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी एसएलपी में कहा है कि शहरी निकाय चुनाव तुरंत कराना संभव नहीं है क्योंकि कुछ प्रक्रियाएं अभी पूरी किए जाने की जरूरत है. हालांकि, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार की ओर से किए गए सीटों के आरक्षण को बरकरार रखा है. इस बीच, शहरी और पंचायत चुनाव कराने वाली संस्था, राज्य चुनाव आयोग ने भी अदालत को सूचित किया है कि वह अभी चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है.

सूत्रों ने बताया कि भाजपा सरकार अभी चुनाव कराने से इसलिए हिचक रही है क्योंकि उसे लगता है कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान मौतों की अधिक संख्या और उच्च महंगाई, विशेष रूप से पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमत, इसे नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं. कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता कहते हैं, ''कांग्रेस चुनाव के लिए तैयार है, जबकि भाजपा डरी हुई है और मतदाताओं का सामना नहीं करना चाहती है, इसलिए वह चुनाव में देरी कर रही है.''

मध्य प्रदेश में कुल 407 तीन स्तरीय शहरी निकाय हैं जिनमें 16 नगर निगम, 99 नगरपालिका और 292 नगर परिषद शामिल हैं. इनमें से 15 शहरी निकायों जहां निर्वाचित निकाय अभी कार्य कर रहे हैं, को छोड़कर बाकी सभी में चुनाव होने हैं. नगरीय निकायों में जहां निर्वाचित निकायों ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है, महापौर के कार्य मंडल आयुक्तों (डिविजनल कमिश्नर) को और नगर पालिकाओं में अध्यक्षों के कार्य जिला कलेक्टरों को सौंपे गए हैं.

जहां शहरी निकाय चुनावों को लेकर भाजपा और कांग्रेस, दोनों दलों में नेताओं का एक वर्ग बहुत उत्साहित है और चुनाव कराने की मांग जोर-शोर से उठ रही है, वहीं पंचायत चुनाव कराने की मांग बहुत कम या नहीं के बराबर दिखती है. तीन स्तरीय पंचायत निकायों ने भी जनवरी 2020 में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है. लेकिन पंचायतों में चुनाव पार्टी की तर्ज पर नहीं होते हैं इसलिए उनकी ज्यादा मांग नहीं उठ रही है. पंचायतों में भी जिन निकायों ने कार्यकाल पूरा कर लिया है, उनके पदाधिकारियों को सेवा विस्तार दिया गया है.

तो चुनाव न कराने से शहरी निकायों और पंचायतों को दिए गए संवैधानिक शासनादेश का क्षरण कैसे होता है? संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम 1992 के वक्तव्यों और उद्देश्यों में, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ''कई राज्यों में स्थानीय निकाय कई कारणों से कमजोर और अप्रभावी हो गए हैं, जिनमें नियमित चुनाव कराने में विफलता, लंबे समय तक अधिक्रमण और शक्तियों तथा कार्यों का अपर्याप्त हस्तांतरण शामिल हैं. नतीजतन, शहरी स्थानीय निकाय स्वशासन की जीवंत और उत्साहपूर्ण लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में प्रभावी ढंग से प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं हैं.'' दूसरे शब्दों में, चुनाव में देरी ऐसे निकायों को कमजोर बनाती है और मध्य प्रदेश में जो हो रहा है वह तो जानबूझकर की जा रही देरी है.

वरिष्ठ अधिवक्त विभूति झा कहते हैं, ''पंचायतों में पदाधिकारियों ने पांच साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है. उन्हें सेवा विस्तार दिया गया है और वे अभी भी अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं. यह तब हो रहा है जब वे केवल पांच साल के लिए चुने गए थे. इस देरी से लोकतंत्र और जमीनी स्तर पर लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का क्षरण हो रहा है.'' वे पूछते हैं, ''कोविड का इस देरी के लिए एक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है. जब विधानसभा चुनाव हो सकते हैं तथा अन्य राज्य भी स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव करा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश ऐसा क्यों नहीं कर सकता?'' ■

राजस्थान

जनजातियों और हिंदुत्व की जद्दोजहद

रोहित परिहार

राजेश भोजक/पीटीआई

बीती 21 जुलाई को एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें अंबागढ़ किले की प्राचीर पर फहराए गए भगवा ध्वज को उतारते समय फाड़ने का दृश्य था. ध्वज को एक सप्ताह पहले ही स्थानीय हिंदुत्ववादी संगठनों ने लगाया था और इसे राजस्थान आदिवासी मीणा संघ के अध्यक्ष तथा गंगापुर शहर से निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा के नेतृत्व में उतारा गया था. मीणा इस बात से नाराज थे कि संघ से जुड़े संगठन स्थानीय जनजातीय समुदाय की पूजनीय देवी अंबा माता के किले में स्थित मंदिर पर कब्जे का प्रयास कर रहे थे.

जल्द ही सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों की ओर से आपत्तिजनक टिप्पणियों की बाढ़ आ गई, जिसमें कुछ वर्गों ने इन घटनाओं को 'सनातन भगवे' से जोड़ने की कोशिश की. हिंदू समूहों और विवादास्पद सुदर्शन टीवी चैनल के प्रधान संपादक सुरेश चव्हाणके समेत कई प्रत्यक्ष रूप से असंबद्ध लोगों ने भी जनता से 1 अगस्त को किले तक मार्च करने और 'जय श्री राम' लिखा भगवा ध्वज फिर से स्थापित करने का आह्वान किया. स्थिति विस्फोटक न हो इसलिए चव्हाणके और रामकेश मीणा दोनों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर पुलिस की तैनाती की गई और किले को सील कर दिया गया.

शुरुआत में भाजपा इस विवाद से दूर रही लेकिन मीणा समुदाय की ओर से विरोध की खबरों के बाद पार्टी ने अपने सांसद और इसी समुदाय के प्रभावशाली नेता किरोड़ी लाल मीणा को मैदान में उतारा. उनकी पहली कार्रवाई रामकेश मीणा और कांग्रेस पर यह कहते हुए हमला करना था कि वे हिंदुओं और आदिवासी मीणाओं के बीच विभाजन की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने यह भी घोषणा की कि वे किले पर ''ध्वज फहराएंगे''. चारों ओर पुलिस की भारी तैनाती के बावजूद किरोड़ी लाल और उनके साथी बारिश के बीच घने जंगल के रास्ते किले पर चढ़ गए और 1 अगस्त की सुबह झंडा फहराया. लेकिन यह भगवा झंडा नहीं था; यह मीणा समुदाय का झंडा था. इस कदम से दोनों पक्ष कुछ देर के लिए शांत हो गए, लेकिन जल्द ही मामला फिर से गर्मा गया.

मीणा इस बात से नाराज हैं कि हिंदुत्ववादी संगठनों ने किले में स्थित उनकी पूजनीय देवी अंबा माता के मंदिर पर कब्जा जमाने का प्रयास किया

दरअसल, यह पूरा प्रकरण जून में शुरू हुआ जब यह पता चला कि बदमाशों ने मंदिर में मूर्तियों को नुक्सान पहुंचाया और इसके बाद वहां नई मूर्तियां स्थापित की गईं. इस मामले में प्रारंभिक संदेह स्थानीय मुस्लिम समुदाय पर केंद्रित था और पुलिस ने कुछ किशोरों को हिरासत में भी लिया. फिर, जुलाई में पता चला कि किले में एक ऊंचे डंडे पर भगवा ध्वज फहराया गया था.

आदिवासी मीणा संघ ने तभी तय कर लिया कि अब बहुत हो गया. पहले से ही कुछ नाराजगी थी कि वहां मूर्तियों को बदल दिया गया था और मीणाओं की मूल अंबा देवी के स्थान पर वहां सनातनी अंबिका देवी की मूर्ति रख दी गई थी.

पुरातात्विक स्थल के रूप में सूचीबद्ध अंबागढ़ किले के खंडहरों के बारे में मान्यता है कि वे कभी जयपुर और आमेर की शासक रही मीणा जनजाति के अब तक बचे अंतिम अवशेषों में शामिल हैं. एक हजार साल पहले मीणा शासकों को हरा कर ही कछवाह राजपूतों ने जयपुर राजवंश की स्थापना की थी.

संघर्ष की जड़
भाजपा के किरोड़ी लाल मीणा किले में; भगवा झंडा उतारने का दृश्य

रामकेश मीणा का कहना है कि सौहार्द्रपूर्ण ढंग से ध्वज हटाने के लिए उन्होंने भगवा ध्वज लगाने वाले लोगों को भी साथ लिया था क्योंकि उन लोगों को ''अपनी गलती का एहसास'' हो गया था. जयपुर के पुलिस कमिशनर आनंद श्रीवास्तव ने भी *इंडिया टुडे* से इसकी पुष्टि की. लेकिन चव्हाणके की सार्वजनिक ललकार के बाद, रामकेश और उनके साथियों ने घोषणा की कि ''किले में या तो मीणा झंडा होगा या तिरंगा हो सकता है, लेकिन हम आरएसएस प्रायोजित भगवा ध्वज नहीं लगाने देंगे''. जल्द ही, राज्य के बाहर के भी बहुत से लोग मीणा समुदाय के पक्ष का समर्थन करते हुए वाक्युद्ध में शामिल हो गए. इस मामले में मीणाओं की ओर से काफी मुखर रहे लोगों में गुजरात के विधायक और भारत ट्राइबल पार्टी (बीटीपी) के संस्थापक छोटूभाई वसावा और भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे. जाट और गुर्जर समुदायों के कुछ नेताओं ने भी अपना समर्थन दिया. राजस्थान के चोरासी से बीटीपी विधायक राज कुमार रोट ने पिछले साल उदयपुर जिले के सलूंबर में भी इसी तरह के एक प्रयास पर प्रकाश डाला जिसमें हिंदुत्ववादी शक्तियों ने सोनारपहाड़ी में एक आदिवासी मंदिर को 'रूपांतरित' करने की कोशिश की थी.

प्रतिक्रिया के डर से, भाजपा शुरू में इस मुद्दे पर चुप रही. लेकिन पार्टी विधायक और पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी इसमें बड़ी साजिश देखते हुए कहते हैं, ''मीणाओं का एक छोटा सा वर्ग पूरे समुदाय को हिंदुओं से अलग करने की कोशिश कर रहा है; यह आदिवासी आबादी को अलग और गैर-हिंदू इकाई के रूप में एकजुट करने की योजना का हिस्सा है. यह भारत को कमजोर करने की चाल है...''

कांग्रेस और भाजपा, दोनों ने इस प्रकरण को तूल न देने की कोशिश की है, लेकिन राजस्थान में आदिवासी अधिकारों का मुद्दा जल्द ही राजनैतिक गर्मागर्मी की वजह बन सकता है. अभी राजस्थान विधानसभा की 200 में से 25 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं और वे एक दर्जन अन्य सीटों के परिणामों को भी प्रभावित करते हैं. मीणा यहां का प्रमुख आदिवासी समुदाय है, जिसे शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण का काफी फायदा हुआ है. समुदाय का नौकरशाही में दबदबा है और मीणाओं तथा दक्षिणी राजस्थान की गरीबी से त्रस्त अन्य जनजातियों के बीच समानताएं बहुत सीमित हैं.

आदिवासी अधिकारों का मुद्दा गत 9 मार्च से चल रहा है जब युवा कांग्रेस प्रमुख और गहलोत के विश्वासपात्र आदिवासी विधायक गणेश घोगरा ने यह दावा करके विधानसभा में हंगामा खड़ा कर दिया था कि आदिवासियों की अलग संस्कृति है और उन पर हिंदू धर्म थोपा जा रहा है. भाजपा ने तब से कांग्रेस से पर दबाव बना रखा है कि वह आदिवासियों को हिंदू मानने या न मानने के बारे में अपना रुख साफ करे. इसी बीच, बहुत से लोग यह भी सवाल कर रहे हैं कि क्या गैर-हिंदू आदिवासियों को आरक्षण मिलना चाहिए. इसी बीच, 13 मार्च को एक अन्य कांग्रेस विधायक, गोपाल मीणा और निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा ने जयपुर में मीणा समुदाय के सम्मेलन में जनगणना के प्रारूप-पत्र में अलग कॉलम के साथ अलग राष्ट्रीय आदिवासी धार्मिक कोड की मांग उठाई.

उसी दिन, राज्य भाजपा ने भी जवाब दिया. जयपुर में एक संगोष्ठी में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने आदिवासियों को सनातनी हिंदू कहा और एक जैसे धार्मिक रीति-रिवाजों का उदाहरण देते हुए मीणाओं को 'विष्णु के वंशज' बताया.

महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले विधानसभा चुनाव में दो सीटें जीतकर सभी को चौंका देने वाली बीटीपी ने आदिवासियों को गैर-हिंदू घोषित करने और उनके लिए एक अलग कोड की मांग करने का समर्थन किया है. बीटीपी के कांग्रेस से संबंध अस्थिर रहे हैं. पिछले साल सचिन पायलट के विद्रोह के दौरान इसने गहलोत का समर्थन किया था, लेकिन डूंगरपुर जिला परिषद अध्यक्ष चुनाव में बीटीपी उम्मीदवार को हराने के लिए कांग्रेस और भाजपा में गठजोड़ होने पर पिछले दिसंबर में उसने सरकार से समर्थन वापस ले लिया.

दोनों मुख्य राजनैतिक दल राज्य के जनजातीय वोटों पर कब्जा करते रहे हैं और प्रत्येक पक्ष उत्सुकता से देख रहा होगा कि उन्हें आदिवासियों में गैर-हिंदुओं/हिंदुओं की बहस से कितना लाभ मिल सकता है. भाजपा धर्म परिवर्तन के मुद्दे को भी जोरशोर से उठा रही है, जिससे गैर-आदिवासी क्षेत्रों में अपने हिंदू वोट बैंक को मजबूत करने में मदद मिलेगी. साथ ही, वह अंबागढ़ किले के मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोलने के लिए आंदोलन शुरू करने की धमकी भी दे रही है. राजनैतिक दलों ने शायद ही कभी राजस्थान में आदिवासी कार्ड खेलने की कोशिश की हो, लेकिन ऐसा लगता है कि वे अब तक अछूते रहे इस मुद्दे को भी हड़पने के लिए तैयार बैठे हैं. ■

संजय तेवनी

उत्तराखंड

पहाड़ की चढ़ाई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उत्तराखंड दौरे के समय कर्नल अजय कोठियाल

पहाड़ पर आप का करंट

अखिलेश पांडे

उत्तराखंड आपदा के बाद केदारनाथ को फिर से स्थापित करने में महती भूमिका चुके सेवानिवृत्त कर्नल अजय कोठियाल अब राज्य में आम आदमी पार्टी (आप) को स्थापित करने का बीड़ा उठा चुके हैं. पिछले पूरे हफ्ते वे राज्य के विभिन्न जिलों में युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित कर प्रदेश के युवाओं से सवाल-जवाब करते दिखे. उनके इस कार्यक्रम में भारी संख्या में युवा जुटे. इस संवाद कार्यक्रम में उन्होंने राज्य में स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा को मजबूत करने के साथ ही सशक्त भू-कानून की जरूरत पर जोर दिया. ये मुद्दे आजकल राज्य के जनमानस को झकझोरते नजर आ रहे हैं. सभी मुख्य सियासी दल इन विषयों पर आगामी चुनाव को ध्यान में रखकर अच्छी-खासी सक्रियता दिखा रहे हैं.

आप ने राज्य में लोगों के बीच पैठ बनाने के लिए चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न देने की मांग को उठाया. आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 16 जुलाई को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर पर्यावरणविद सुंदर लाल बहुगुणा को भारत रत्न देने की मांग की. इससे पहले 15 जुलाई को दिल्ली विधानसभा में दिवंगत बहुगुणा के चित्र और पत्थर के पोर्टेट का केजरीवाल ने अनावरण किया. दिल्ली विधानसभा सभागार में आयोजित समारोह में बहुगुणा के परिजनों को सम्मानित भी किया गया. नतीजतन, सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा और आप, दोनों के बीच इस मांग को लेकर जबदरस्त बयानबाजी दिखी. आप बहुगुणा के सहारे भाजपा को राज्य के हितों के खिलाफ काम करने वाली पार्टी साबित करने में जुट गई है.

इससे पहले भी केजरीवाल अपने उत्तराखंड दौरे से राज्य में राजनैतिक हलचल बढ़ा चुके हैं. केजरीवाल ने घोषणा की कि आप की सरकार बनते ही यहां हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, पुराने बिल माफ किए जाएंगे और नए सिरे से बिल शुरू किए जाएंगे. उन्होंने साथ ही वादा किया कि राज्य में कोई पावर कट नहीं होगा और 24 घंटे बिजली दी जाएगी. उन्होंने राज्य के किसानों को मुफ्त बिजली देने की बात भी कही. केजरीवाल का यह कुछ ही घंटों का दौरा उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह फूंकने में कामयाब रहा. आप पार्टी से जुड़कर खासे सक्रिय नजर आ रहे रविंद्र जुगरान राज्य के वरिष्ठ आंदोलनकारियों में से एक हैं. वे पहले भाजपा में थे. उनका कहना है कि केजरीवाल के इस दौरे ने राज्य में चुनाव का नैरेटिव सेट कर दिया है.

केजरीवाल ने घोषणा की कि आप की सरकार बनते ही उत्तराखंड में हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी और पुराने बिल माफ किए जाएंगे

आगामी विधानसभा चुनावों की नैया मुफ्त बिजली की कश्ती पर सवार होकर पार लगाने की तैयारी में जुटी आप शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, महंगाई आदि पर भी आने वाले दिनों में प्रहार करने की योजना बना रही है. हालांकि 300 यूनिट मुफ्त बिजली हर माह आप कैसे देगी, इसका कोई ब्ल्यू प्रिंट उसने राज्य के सामने नहीं रखा है. लेकिन कोठियाल का दावा है कि मुफ्त बिजली देने की गारंटी के पीछे पूरा होमवर्क है. कोठियाल कहते हैं, ''आप की ओर से पूरी तरह कैलकुलेट करके उत्तराखंड के लिए यह मॉडल बनाया गया है. यह एक लॉजिकल मैथमैटिकल कैलकुलेशन के तहत है, जिसके माध्यम से सरकार के बजट में जनता के हितों को लेकर ध्यान दिया जाना है. सरकार का जो वार्षिक बजट है, उसी बजट में से बिजली के बजट को अलग करके ही उत्तराखंड की जनता को 300 यूनिट मुफ्त बिजली आप सरकार देगी.''

हालांकि केजरीवाल से पहले ही राज्य के ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने बिजली बोर्डों की पहली ही बैठक के बाद घोषणा कर दी थी कि प्रदेश में 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी. उन्होंने 200 यूनिट तक बिलों में 50 फीसद की छूट देने की भी बात कही थी. लेकिन उसके एक दिन बाद ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रावत के प्रयासों पर यह कहकर विराम लगा दिया कि ऐसा सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है और जब प्रस्ताव आएगा तो सभी पहलुओं पर विचार करके निर्णय होगा. इससे भाजपा सरकार आप के निशाने पर आ गई. वहीं कांग्रेस केजरीवाल की घोषणा को हवाहवाई कह रही है. कांग्रेस ने कहा कि आप के पास इसका कोई रोडमैप नहीं है, ऐसे में वह पार्टी कैसे बिजली मुफ्त देने की बात कह रही है. इसके साथ ही, कांग्रेस अब खुद भी कहने लगी है कि अगर उसकी सरकार आई और प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक रही तो वह जनता को 300 यूनिट से भी अधिक बिजली मुफ्त देगी.

आप की बिजली मुफ्त देने की घोषणा की बाबत पूछे जाने पर मुख्यमंत्री धामी ने इतना भर कहा, ''भाजपा सरकार अच्छी और सस्ती बिजली दे रही है. उत्तराखंड के हित में जो भी होगा हम करेंगे.'' जाहिर है, बिजली आगामी चुनावों में बड़ा मुद्दा न बन जाए, इसको लेकर सरकार भी सजगता बरत रही है. ■

अर्थात्

गए रोजगार बनाम नए रोजगार

अंशुमान तिवारी

दुनिया-बदल तकनीकों के पैमाने पर अगर कंप्यूटरों, इंटरनेट, मोबाइल का पूर्वज तलाशना हो तो हमें 18वीं सदी की नहरें, रेलवे और स्टील मिलेंगे, जिनमें इतनी पूंजी झोंकी गई कि संकट फूट पड़े और बर्बादी का इतिहास बन गया.

लेकिन बाद के दशकों में इतिहास ने बदलने का तरीका बदल दिया. डॉट कॉम बबल के बाद भी इंटरनेट की गति नहीं रुकी. ऐसा ही उन तकनीकों के साथ हुआ जिनके जरिए बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ. मंदी के झटके लगते रहे लेकिन फिर कैनाल पैनिक (1797) या रेल पैनिक (1847) नहीं दोहराए गए.

1942 तक दुनिया समझ गई थी कि खुले बाजार का मकसद बराबरी स्थापित करना नहीं है बल्कि नई तकनीक से नए उत्पाद/सेवाएं लाना, उत्पादन व प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, मुनाफा कमाना और नए तरह के रोजगार तैयार करना था.

इस सकारात्मक ध्वंस (क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन) को पहले पहल ऑस्ट्रियन अर्थविद जोसफ शंपिटर ने पकड़ा था जिनके सिद्धांतों पर मार्क्सवाद की छाया थी. दूसरी बड़ी लड़ाई के साथ आई नई तकनीकें जिनकी छाया में यह ध्वंस आज का इनोवेशन बन गया. इस के साथ ही रोजगारों के आयाम पूरी तरह तब्दील हो गए.

महामारी और महामंदी के बाद दुनिया बदलती है. कोविड पार की नई अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा का रसायन सरकारों की आत्ममुग्धता में नहीं, श्रमिकों या मानव संसाधन की दक्षता पर केंद्रित है.

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी ग्लोबल कंपीटीटिवनेस रिपोर्ट 2020 नए आर्थिक चोला बदलने में दुनिया के करीब 37 प्रमुख देशों की तैयारियों और क्षमताओं का आकलन किया है. जानना जरूरी है कि नए रोजगार कहां से आएंगे और भारत कितना तैयार है.

- दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में करीब 48 फीसद नौकरियां ऑटोमेशन और तकनीकी उठा-पटक का शिकार होंगी. अब नए डिजिटल कौशल के दम पर ही टिका जा सकेगा.
- महामारी पार की अर्थव्यवस्था सूचना तकनीक के बहुआयामी इस्तेमाल, डिजिटल कौशल, रोजगारों के लचीलापन और डिजिटल कारोबारों के मुफीद कानूनी ढांचे पर केंद्रित होगी.
- इस बदलाव की तैयारी से लैस दस प्रमुख देशों में भारत शामिल नहीं है. इस सूची में अमेरिका जापान, सिंगापुर, जर्मनी चीन, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, इज्राएल, स्वीडन, कोरिया, हांगकांग, फिनलैंड तो हैं हीं लेकिन सऊदी अरब, अमीरात, कतर, मलेशिया और एस्टोनिया की मौजूदगी चौंकाती है.
- तकनीक की ताकत पर आगे बढ़ती दुनिया में ग्लोबल पेटेंट आवेदन में भारत मीलों पीछे है. जापान, अमेरिका, जर्मनी के अलावा कोरिया और चीन पेटेंट की ताकतवाले पांच शीर्ष देश हैं.
- वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक विश्व के शीर्ष उद्यमियों को भारत की उत्पादन वैल्यू चेन के जल्दी आधुनिक या ग्लोबल होने की उम्मीद नहीं है. वे भारत को आपूर्ति का स्रोत बनाने नहीं जा रहे हैं.

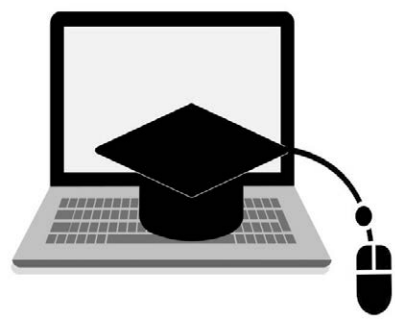

कोविड के बाद करीब आधी नौकरियां ऑटोमेशन और तकनीकी उठा-पटक का शिकार होंगी

नई प्रतिस्पर्धा

बीते सौ वर्ष तीन बड़ी मंदी आईं. हर बार यह साबित हुआ कि कारोबार में बढ़त के बीच जो कंपनियां तकनीकी बदलाव में निवेश को टालती हैं वे भी मंदी के दौरान नई तकनीकों की शरण में चली जाती हैं. हर बड़ी मंदी रोजगारों और कौशल का पूरा ढांचा बदल देती है.

प्रतिस्पर्धा की नई ग्लोबल नापजोख बताती है कि अगले एक दशक में किसी देश में ग्लोबल ताकत उसके स्कूलों से तय होगी. लोगों को बार-बार प्रशिक्षण देकर प्रतिस्पर्धी (रिस्किलिंग) बनाना होगा. इन पैमानों पर भारत की रैंकिंग बेहद घटिया है.

2009 की मंदी के बाद दुनिया के जिन शहरों में अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा नुक्सान हुआ वहां नई भर्तियों में नए कौशल की मांग तेजी से बढ़ गई. कई जगह तो कंपनियों ने अपनी पांच साल पुरानी रोजगार-कौशल नीति ही बदल डाली.(हावर्ड बिजनेस रिव्यू 2017)

भारतीय रोजगारों के बाजार में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है. अब 2015-16 के बाद आईं मोबाइल डेटा, मशीन लर्निंग, क्लाउड, नैनो टेक, थ्रीडी आदि तकनीकें ही भविष्य का नेतृत्व करेंगी. चीन और कोरिया के साथ सऊदी अरब ने नई दक्षताओं में बढ़त लेकर दुनिया को चौंका दिया है. युवा आबादी को तकनीकी कौशल से लैस करने में मिस्र, तंजानिया और बल्गारिया अब अमेरिका और जापान से आगे निकल रहे हैं. (डब्ल्यूईएफ)

भारत का रोजगार परिदृश्य गहरे अंधेरे में है. नए लेबर फोर्स सर्वे (पीएलएफएस जुलाई 2019-जून 2020) ने बताया है कि बेराजगारी में सबसे बड़ा हिस्सा स्नातकों का (17.2 फीसद) का है. इसके बाद डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट और पोस्ट ग्रेजुएट नौकरी की तलाश में टूट रहे हैं.

नेताओं को इस बात की फिक्र ही नहीं है कि 2016 से 2020 के बीच स्नातकों कौशल बढ़ाने के मामले में भारत, जी 20 देशों में आखिरी पंक्ति में खिसक गया है. (डब्ल्यूईएफ-ग्लोबल कंपीटीटिवनेस रिपोर्ट 2020)

भारत में नए, अच्छे और संगठित रोजगारों का बाजार अभूतपूर्व रचनात्मक ध्वंस से मुखातिब है. महामारी और बदलती तकनीकें, 'गई' नौकरियों की वापसी असंभव बना रही हैं लेकिन क्या नई नौकरियों के लिए भी हम तैयार हो पा रहे हैं?

@anshuman1tiwari

इलस्ट्रेशनः असित रॉय

पार्टी की सूरत बदलने के नए सूत्र

भाजपा युवा नेतृत्व की एक नई पंक्ति के साथ अपनी 'ब्राह्मण-बनिया' पार्टी की छवि को बदलने की कोशिश कर रही है, जहां महिलाएं और पिछड़ा वर्ग भविष्य में पार्टी के विकास की धुरी हो सकते हैं

अनिलेश एस. महाजन

संजीव वर्मा/गेट्टी इमेजेज

पांच जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा/दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों के अखिल भारतीय कोटे में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के विद्यार्थियों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी. यह राजनैतिक रूप से मौके को भांपकर किया गया फैसला लगता है क्योंकि कुछ महीनों बाद पांच राज्यों में चुनाव होने वाले हैं.

सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जाहिर तौर पर इसमें चुनावी फायदे का हिसाब-किताब लगा रही है. वैसे तो यह चुनाव से पहले वोटरों के एक वर्ग को लुभाने का बढ़िया एकतरफा प्रयास लगता है, लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि यह पार्टी की छवि बदलने की भाजपा और संघ परिवार की बड़ी योजना का हिस्सा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत भाजपा का शीर्ष नेतृत्व, पार्टी का पुनर्निर्माण कर रहा है जिसमें जातियों के एक नए अंकगणित पर ध्यान केंद्रित किया गया है. महिलाओं और युवा नेताओं की नई पंक्ति तैयार करते हुए पार्टी मुख्य रूप से ओबीसी और दलितों के साथ जीत का एक नया फार्मूला ईजाद कर रही है.

नई भाजपा न केवल वोट के लिए ओबीसी जातियों को साधने की कोशिश कर रही है, बल्कि अपने काडर और नेतृत्व के पदों के लिए भी उनके युवाओं को आगे बढ़ा रही है. इसके लिए, महाराष्ट्र में पार्टी स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण की रक्षा के लिए आंदोलन चला रही है. राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर स्थानीय निकाय चुनाव स्थगित करने के लिए कहा है क्योंकि कोटे पर फैसला लंबित है (लड़ाई सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गई है). पंजाब में, अकाली दल का साथ छूटने के बाद भाजपा ओबीसी (31.3 प्रतिशत मतदाता) और दलितों (31.9 प्रतिशत) के बीच अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है.

इस भारी-भरकम वोट बैंक को रिझाने के लिए पार्टी ने इन समुदायों को व्यापक राजनैतिक प्रतिनिधित्व देने और शिक्षा के साथ सरकारी सेवाओं में समान आरक्षण देने की प्रतिबद्धता जताई है. चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में पार्टी ने ओबीसी (गैर-यादव) और दलित (गैर-जाटव) जातियों का गठबंधन तैयार किया है और उन्हें मजबूत करने की कोशिश कर रही है. केंद्र 127वें संविधान संशोधन विधेयक पर भी काम कर रहा है जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी सूची तैयार करने की शक्तियां बहाल करेगा. 5 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में, यह कहते हुए राज्य सरकारों से

नया प्लान
भाजपा संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के साथ अमित शाह और जे.पी. नड्डा

ताकि भगवा दल और चमके

नारी शक्ति
पार्टी संगठन में, 12 उपाध्यक्षों में से 5 महिलाएं हैं, 75 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 10 महिलाएं भी हैं. केंद्रीय मंत्रिमंडल में अब 11 महिला मंत्री हैं

अगली पीढ़ी के नेता
गृह राज्य मंत्री 35 वर्षीय निसिथ प्रमाणिक सबसे कम उम्र के कैबिनेट सदस्य हैं; 36 वर्षीय के. अन्नामलाई तमिलनाडु इकाई के प्रमुख हैं. राज्य इकाई प्रमुखों की औसत आयु 55 वर्ष है; राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की औसत आयु 58 वर्ष है

ओबीसी एवं दलितों को बढ़ावा
कैबिनेट में अब 27 ओबीसी मंत्री हैं, जिनमें से 12 दलित हैं. पार्टी पिछड़े नेताओं को जिला/राज्य स्तर पर भी अधिक जिम्मेदारी दे रही है

अब ब्राह्मण/बनिया की पार्टी नहीं
भाजपा धीरे-धीरे इस जातीय गठबंधन से बाहर निकल रही है, जिसका जनसंघ के जमाने से पार्टी औरसंघ परिवार पर दबदबा रहा है

यह शक्ति छीन ली थी कि 2018 के कानून में ऐसी शक्तियां सिर्फ केंद्र तक सीमित हैं.

पिछले सात वर्षों में संघ परिवार और भाजपा ने राष्ट्रवाद-लोकलुभावनवाद का एक ऐसा हिंदूवादी संस्करण पेश किया था, जो दलितों, ओबीसी और एसटी के बीच कई समुदायों को बड़ा भा रहा है. इसका संबंध उस वोटर केमिस्ट्री से भी था जिसे मोदी ने तैयार किया है. मोदी के रूप में पहली बार भाजपा के पास एक ऐसा नेता था जो आरएसएस प्रोडक्ट था और ओबीसी जाति से आता था. इससे भाजपा और संघ को ब्राह्मणों और बनियों का संगठन होने की अपनी छवि बदलने का अवसर मिला. '90 के दशक भाजपा का नेतृत्व दो ब्राह्मणों (अटल बिहारी वाजपेयी और मुरली मनोहर जोशी) और एक बनिया (एल.के. आडवाणी) के हाथ में रहा जिससे भाजपा को ब्राह्मण-बनियों की पार्टी कहा जाने लगा. यहां तक कि प्रमोद महाजन, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और अनंत कुमार के रूप में, नेतृत्व के दूसरे पायदान पर भी ब्राह्मणों का एकाधिकार था. आरएसएस नेतृत्व में भी इन दोनों समुदायों के प्रचारकों का ही बोलबाला था.

आज, पार्टी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा और केंद्रीय संगठन मंत्री बी.एल. संतोष ब्राह्मण हैं लेकिन अन्य आठ महासचिव विभिन्न जातियों से हैं. 62 वर्ष की डी. पुरंदेश्वरी को छोड़कर अन्य सभी महासचिव अपनी उम्र के पचासवें दशक के मध्य में हैं. भाजपा मंडल दौर की राजनीति, जहां उसने आरक्षण विरोधी आंदोलन चलाकर उच्च जातियों के बीच अपना आधार पक्का किया और सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गई, को बहुत पीछे छोड़ चुकी है. मोदी ने इसमें भी एक बड़ी भूमिका निभाई है. उन्होंने खुद को चायवाला, संघर्ष से पैदा हुए एक स्वनिर्मित व्यक्ति के रूप में पेश करके क्षेत्रीय दलों की मंडल राजनीति के लिए ऐसी आदर्श काट तैयार की जो अगड़ी जातियों के मध्यवर्ग को भी लुभाती थी. अगड़ी जातियों के मध्यवर्ग को खुश करने के लिए कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेजों में आर्थिक रूप से कमजोर अगड़ों के लिए 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखी हैं.

मंत्रिमंडल में हाल में हुए फेरबदल के बाद मोदी सरकार में अब 27 ओबीसी और 12 दलित मंत्री हैं (कुल 78 में से) और स्वतंत्र भारत में पिछड़ी जातियों को दिया गया आज तक का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है. पिछले दो दशकों में जनता दल के पतन और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियों से नेताओं के बड़े पैमाने पर पलायन से भाजपा को व्यापक लाभ हुआ. राज्य स्तर पर भाजपा और संघ परिवार उन जाति समूहों का मुकाबला करने के लिए जातियों के एक नए गठबंधन पर काम कर रहे हैं, जो परंपरागत रूप से पार्टी के खिलाफ लामबंद होते रहे हैं. वे महसूस करते हैं कि आरक्षण का सारा लाभ कुछ वर्गों ने हथिया लिया और यह एक बड़ा गतिरोध बिंदु है. इसलिए उत्तर प्रदेश में, भाजपा यादवों (सपा के कट्टर समर्थकों) और जाटवों (बसपा के

मुख्य वोट-बैंक) के खिलाफ गुस्से को भुना रही है क्योंकि उन्होंने अपनी-अपनी श्रेणी के अधिकांश संसाधनों और आरक्षण के लाभों पर कब्जा कर लिया है.

अगला बड़ा काम इन जाति समूहों को भाजपा की विचारधारा के साथ ढालना है. संघ नेताओं का कहना है कि भर्ती किए गए दलबदलू चुनाव के समय तो मददगार हो सकते हैं, लेकिन संगठन निर्माण में ज्यादा योगदान नहीं देते. दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर श्री प्रकाश का तर्क है, ''ओबीसी और दलित मतदाताओं को मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सिर्फ मोदी के पिछड़ी जाति से होने और हिंदुत्व की राजनीति के कारण आकर्षित नहीं करती बल्कि इसलिए भी लुभाती है क्योंकि उनके नेतृत्व वाली सरकार ने विकास और वर्ग के नाम पर जातीय राजनीति से तालमेल भी बिठाया है.''

2018 में मोदी सरकार ने जाति आधारित जनगणना पर प्रारंभिक कार्य शुरू किया लेकिन आंतरिक दबाव के कारण इसे छोड़ दिया गया. अब फिर इस पर विचार हो रहा है

तीन दशकों से अधिक समय तक इसका विरोध करने के बाद, भाजपा-संघ परिवार में एक बड़ी लॉबी उनकी भी है जो यह मानते हैं कि देश को जाति-आधारित जनगणना की आवश्यकता है. मूल रूप से जनता परिवार ने इसकी मांग की थी. बिहार विधानसभा ने दो बार जाति आधारित जनगणना के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया है, जिसे भाजपा ने भी समर्थन दिया था. जनगणना में फिलहाल एससी और एसटी वर्ग के आंकड़े जुटाए जाते हैं, लेकिन पिछड़े वर्गों के नहीं. 2018 में, मोदी सरकार ने जाति-आधारित आंकड़ों पर प्रारंभिक कार्य शुरू किया था, लेकिन बाद में आंतरिक दबावों के कारण इसे छोड़ दिया गया. भले ही सरकार ने जुलाई में संसद में जाति आधारित जनगणना का सार्वजनिक रूप से विरोध किया था, लेकिन भाजपा के शीर्ष सूत्रों का कहना है कि पार्टी इस विषय पर अब विचार कर रही है.

आरएसएस के एक शीर्ष नेता कहते हैं, ''उत्तर प्रदेश में, भाजपा का ध्यान समुदायों के तीन समूहों—सवर्णों और ओबीसी तथा दलितों के एक वर्ग पर है, लेकिन हमारे पास ओबीसी और दलितों के उस खास वर्ग के बीच पर्याप्त काडर आधार नहीं है. इस संबंध में प्रयास जारी हैं.'' इसमें स्थानीय निकाय चुनावों में लक्षित समुदाय के नेताओं को टिकट देना, उनके सामाजिक प्रतीकों का निर्माण और वे जिस पंथ या मत संप्रदायों को मानते हैं उनके धार्मिक नेताओं के साथ जुड़ना आदि शामिल हैं. ओबीसी और दलित युवाओं को आरएसएस में पद देने की संघ की योजना को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ बढ़ावा मिला है और इन समुदायों के स्वयंसेवक आगे आए हैं. आरएसएस नेता कहते हैं कि इसके लिए ''न केवल राजनैतिक इच्छाशक्ति बल्कि सामाजिक परिवर्तन की भी जरूरत होगी.''

पार्टी को युवा रखना है

नए रूप वाली भाजपा भी राजनीति में महिलाओं और युवाओं की अधिक भागीदारी चाहती है. इसलिए शाह, नड्डा, संतोष और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को शिक्षित, योग्य पेशेवर, विशेष रूप से महिलाओं, ओबीसी, दलितों और आदिवासियों में से युवा प्रतिभाओं की पहचान करने का काम सौंपा गया है, जिन्हें भविष्य के नेताओं के रूप में तैयार किया जा सकता है. भाजपा के एक शीर्ष नेता का तर्क है कि जाति-आधारित संगठन 1990 के दशक में अपने उदय के बाद ढह गए, क्योंकि उनके पास आरक्षण के अलावा देने के लिए बहुत कुछ नहीं था. वे कहते हैं, ''युवा पीढ़ी और महिला नेताओं को तैयार करना पार्टी की भावी विस्तार रणनीति का हिस्सा है.''

हाल ही में हुए कैबिनेट फेरबदल में 35 वर्षीय निसिथ प्रमाणिक सबसे कम उम्र के मंत्री बने. मंत्रिपरिषद की औसत आयु घटकर 58 हो गई, जिसमें 72 वर्षीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश सबसे बड़े थे. केंद्र के फैसले का असर भाजपा शासित राज्यों में भी दिख रहा है.

कर्नाटक में 78 वर्षीय बी.एस. येदियुरप्पा की जगह उनके शिष्य 61 वर्षीय बी. बोम्मई; और उत्तराखंड में 56 वर्षीय तीरथ सिंह ठाकुर की जगह 43 वर्षीय पुष्कर सिंह धामी ने ली. इसी तरह, 69 वर्षीय सुशील मोदी ने बिहार में युवा नेताओं तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के लिए जगह बनाई. संयोग से, पूर्व आरएसएस प्रमुख के.एस. सुदर्शन ने वाजपेयी और आडवाणी को बाहर निकालने के लिए 75 साल की सीमा का सुझाव दिया था.

दक्षिण में मिशन कमल को जारी रखने के लिए भाजपा नए जाति समीकरणों और युवा नेताओं पर बहुत अधिक भरोसा कर रही है, जो उन्हें लगता है कि लंबी दौड़ में हैं. जुलाई में, 36 वर्षीय के. अन्नामलाई को तमिलनाडु इकाई का प्रमुख बनाया गया था; तेलंगाना इकाई के प्रमुख बंदीसंजय कुमार 50 वर्ष के हैं, जबकि कर्नाटक में नलिन कटील 55 वर्ष के हैं. राज्य इकाई के प्रमुखों में गुजरात के 66 वर्षीय सी.आर. पाटिल सबसे उम्रदराज हैं. इसी तरह नड्डा की टीम में सभी महासचिवों की उम्र 56 साल से कम है; नड्डा खुद 60 साल के हैं.

संगठन को नए सिरे से खड़ा करने के अलावा, युवा पीढ़ी के नेता मोदी-शाह की जोड़ी के लिए वफादारों का एक नया समूह भी लाते हैं. इस साल मार्च में आरएसएस में भी पीढ़ीगत बदलाव आया. 73 वर्षीय सुरेश भैयाजी जोशी ने 66 वर्षीय दत्तात्रेय होसबाले के लिए महासचिव या सरकार्यवाह की जगह बनाई; 57 वर्षीय अरुण कुमार और 58 वर्षीय रामदत्त चक्रधर पांच सह-सरकार्यवाहों की टीम में शामिल हुए. अरुण कुमार ने 66 वर्षीय कृष्ण गोपाल से सरकार के साथ संपर्क कार्य की जिम्मेदारी भी ली.

इस बीच, भाजपा महिला मोर्चा की प्रमुख वनती श्रीनिवासन बताती हैं कि कैसे महिलाएं पार्टी में अधिक जिम्मेदारी ले रही हैं. 75 सदस्यीय भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अब 12 महिलाएं हैं; 12 में से 5 महिलाएं उपाध्यक्ष भी हैं. हाल के कैबिनेट फेरबदल में महिला मंत्रियों की संख्या बढ़ाकर 11 हो गई—मनमोहन सिंह के समय की तुलना में एक अधिक—और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को छोड़कर, सभी लोकसभा से हैं. कुल मिलाकर, यह भाजपा संगठन में आमूल-चूल परिवर्तन का समय है, पार्टी को उम्मीद है कि यह इसे और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएगी. ■

इंडिया टुडे
देश की भाषा में देश की धड़कन

INDIA TODAY GROUP

यूपी की धान खरीद व्यवस्था में कई छेद
लालफीताशाही के शिकंजे में कारोबार
सरना: पुराने धर्म पर नई बहस
इंडिया टुडे
कोविड-19 वैक्सीन
कितनी सुरक्षित? कितनी कारगर?
बाजार में आने के लिए तैयार नई वैक्सीन से जुड़े सारे अहम सवालों के जवाब

राम मंदिर को माना गया मोदी की प्रमुख उपलब्धि
अनुच्छेद 370 हटाने को मिला जोरदार समर्थन
बेरोजगारी मानी गई सबसे बड़ी समस्या
इंडिया टुडे
देश का मिजाज सर्वेक्षण
मोदी और हिंदुत्व का बोलबाला
देशव्यापी छमाही सर्वेक्षण से जाहिर है कि नरेंद्र मोदी लोकप्रियता के शिखर पर बरकरार हैं और संघ परिवार के एजेंडे को मिली जबरदस्त बढ़त

सबसे भरोसेमंद स्रोतों से, सबसे सटीक जानकारी

सब्सक्राइब करें और पाएं 21% तक की छूट

हां! मैं इंडिया टुडे को सब्सक्राइब करना चाहता/चाहती हूँ

अपनी पसंद के सब्सक्रिप्शन को टिक करें और फॉर्म को इस पते पर भेज दें– **वी केअर, लिविंग मीडिया इंडिया लि. सी–9, सेक्टर–10, नोएडा 201302 (भारत)**

टिक करें	अवधि	कुल अंक	कवर प्राइस (₹)	ऑफर प्राइस (₹)	डिस्काउंट
☐	2 वर्ष	104	~~5200~~	4099	21%
☐	1 वर्ष	52	~~2600~~	2199	15%

कृपया फॉर्म को ब्लॉक लेटर में भरें

मैं चेक/डीडी जमा कर रहा/रही हूँ जिसकी संख्या.....है और इसे दिनांक..... को लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड के पक्ष में ..... (बैंक का नाम).....रुपये की धनराशि (दिल्ली से बाहर के चेक के लिए ₹ 50 रुपये अतिरिक्त जोड़ें, समान मूल्य के चेक मान्य नहीं होंगे) के लिए बनवाया गया है.

नाम..... पता.....

..... शहर..... राज्य..... पिन.....

मोबाइल..... ईमेल.....

सब्सक्राइब करने के लिए यहां स्कैन करें.

ऑफर के विषय में विशेष जानकारी के लिए निम्न माध्यमों से संपर्क भी कर सकते हैं

हमारे टॉल फ्री नंबर पर कॉल करें
18001800100 (0120) 2479900

ईमेल भेजें
wecare@intoday.com

लॉग ऑन करें
subscriptions.intoday.in/indiatoday-hindi

लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड इस ऑफर या इसके अंश को कभी भी समाप्त करने या आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है. अन्य नियम व शर्तों की जानकारी के लिए कृपया देखें-www.indiatoday.in

सार्वजनिक स्वास्थ्य निजी समस्याएं

आपूर्ति में सुधार के बावजूद निजी क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों का प्रदर्शन कमजोर ही नजर आता है. टीकाकरण को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है?

सोनाली आचार्जी

इम्युनिटी की रसीद

बीएलके हॉस्पिटल, राजेंद्र नगर, दिल्ली के टीकाकरण केंद्र पर 10 मई, 2021 को बिलिंग काउंटर पर कतार में खड़े लोग

चंद्रदीप कुमार

मई 2021 के बाद से, टीकाकरण दर ने रफ्तार पकड़ी है. जुलाई में, भारत ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया के उस महीने के लिए निर्धारित लक्ष्य को हासिल किया. मंत्री ने रोजाना औसतन 43 लाख खुराक के साथ जुलाई के लिए कुल 13.5 करोड़ कोविड टीके की खुराक देने का लक्ष्य रखा था. जून में 11.9 करोड़ खुराकें दी गई थीं, और वह भी टीकाकरण कार्यक्रम के लिए मील का पत्थर रहा था. जून में, मई में दी गई खुराकों की तुलना में 96 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई थी. मई में औसतन 19 लाख टीके रोजाना लगाए गए थे.

3 अगस्त तक, भारत में कुल 47.4 करोड़ खुराकें दी जा चुकी थीं, जिसमें 36.9 करोड़ वयस्कों को कम से कम एक खुराक मिली चुकी थी और 10.4 करोड़ का दोनों खुराकों के साथ पूर्ण टीकाकरण हो चुका था. हालांकि, अभी लंबा रास्ता तय करना है. 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की वयस्क आबादी लगभग 94 करोड़ है, जिसका अर्थ है कि सभी के पूर्ण टीकाकरण के लिए 188 करोड़ खुराक की जरूरत है. 2021 के अंत तक वयस्कों के शत प्रतिशत टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, टीकाकरण कार्यक्रम को अब प्रति दिन 93 लाख खुराकों का लक्ष्य लेकर चलना होगा.

पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन पी. श्रीनाथ रेड्डी कहते हैं, ''कोविड के खिलाफ हमारी लड़ाई में टीके अहम हैं. हम उनके बिना सामूहिक प्रतिरक्षा तक नहीं पहुंच सकेंगे. लोगों को टीकों के लिए किफायती, सुलभ चैनल दिए जाने की जरूरत है और उनको टीके की सुरक्षा को लेकर भी आश्वस्त किए जाने की जरूरत है.'' केंद्र सरकार ने आने वाले महीनों में टीकों की बेहतर आपूर्ति का आश्वासन दिया है. वितरण भी उतना ही जरूरी है. सरकार ने टीका निर्माताओं के उत्पादन का 25 फीसद हिस्सा निजी अस्पतालों के लिए रखा है, लेकिन टीकाकरण की गति बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र को शामिल करने के फैसले के वांछित परिणाम अब तक नहीं देखे गए हैं.

क्षमता से कम उपयोग की समस्या

सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पिछले ढाई महीनों में हुए कुल टीकाकरणों में निजी क्लिनिकों और अस्पतालों का हिस्सा केवल 7 फीसद है. आंकड़े निजी क्षेत्र की कमियों को उजागर करते हैं. मई से 15 जून तक, लगभग 8,30,000 खुराक निजी अस्पतालों ने लगाई हैं, जबकि मई में कुल 1.2 करोड़ खुराक, निजी अस्पतालों ने निर्माताओं से सीधे खरीदी थीं. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, जुलाई 2021 के अंत तक राज्यों और निजी अस्पतालों के पास तीन करोड़ से ज्यादा अप्रयुक्त टीके थे. कुछ राज्यों में टीकों के कम उपयोग का आंकड़ा भी अन्य राज्यों की तुलना में काफी बड़ा है. राज्य सरकारों के आंकड़ों के अनुसार, जहां आंध्र प्रदेश के निजी अस्पतालों को मई से 35 लाख खुराक की आपूर्ति की गई है पर अब तक केवल 4,63,000 खुराक का उपयोग किया गया है. उसी तरह तमिलनाडु में, अब तक दी गई लगभग एक करोड़ खुराकों में से, केवल 5 फीसद निजी केंद्रों में दी गई थीं. इन राज्यों ने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अप्रयुक्त खुराकों के पुन: आवंटन के लिए कहा है. अन्य राज्य निजी क्षेत्रों के लिए आरक्षित कोटे को कम करने की मांग कर रहे हैं. मसलन, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से निजी अस्पतालों के लिए होने वाले मौजूदा 25 फीसद आवंटन को घटाकर पांच फीसद करने के लिए कहा है.

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने की वजह से निजी क्षेत्र को फटकार लगाई है. उन्होंने कहा, ''आप सभी (निजी क्षेत्र) ने मांग की थी और मुझे याद है कि आप इसके लिए मुझसे कितना लड़े थे तथा टीकाकरण को निजी क्षेत्र के लिए खोलने की मांग की थी. लेकिन आज, आप खुद को आवंटित किए गए 25 फीसद टीके को भी नहीं खरीद रहे हैं.'' गोयल ने कहा, ''मुझे याद है कि एक उद्योग समूह ने कहा था कि वह एक करोड़ टीकाकरण करेगा और दूसरे ने कहा था कि वह सुदूर क्षेत्रों में जाकर टीकाकरण करेगा. लेकिन टीके के प्रति हिचक को खत्म करने के लिए अभियान चलाने और अपने 25 फीसद कोटे का इस्तेमाल करने कोई बिहार, उत्तर-पूर्व, झारखंड और छत्तीसगढ़ नहीं गया.''

प्रमुख कारक

सरकार के अनुसार, निजी केंद्रों से संबंधित चार प्रमुख समस्याएं देखी जा रही हैं. पहली, कई अपने लिए निर्धारित खुराक की पूरी मात्रा के लिए ऑर्डर नहीं दे रहे हैं. दूसरी, ऑर्डर देने के बाद भी कुछ मामलों में पूरा भुगतान नहीं किया गया है. तीसरी, कुछ क्लिनिक भेजी गई खुराक की पूरी मात्रा एक बार में नहीं उठा रहे. और चौथी, पूरी खुराक उठाने वाले असल में उतने टीके लगा नहीं रहे हैं.

कोविड प्रबंधन पर नेशनल टास्क फोर्स के प्रमुख डॉ. वी.के. पॉल कहते हैं, ''हमें निजी क्षेत्र के पास उपलब्ध टीकों का बेहतर उपयोग करना

चाहिए. लोगों को टीके लगवाने निजी क्षेत्रों के पास जाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.'' संयुक्त स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल के अनुसार, राज्यों को भी टीकाकरण अभियान के लिए अपनी योजना को गति देने की जरूरत है. वे कहते हैं, ''दो सप्ताह पहले पता चल जाता है कि कितने टीके आने वाले हैं, तो उन्हें समुदाय और टीकाकरण केंद्रों से जुड़ने और सुनिश्चित करने की जरूरत है कि पूरी उपलब्ध खुराक लोगों तक पहुंचे.''

निजी क्षेत्र में पूर्ण उपयोग की समस्या भी, एक नीतिगत समस्या है. ऑल इंडिया ड्रग ऐक्शन नेटवर्क (एआइडीएएन) की सह-संयोजक और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ मालिनी ऐसोला कहती हैं, ''शुरुआत में निजी क्षेत्र ने निर्माताओं से सीधा टीका पाने के अधिकार और टीकों की कीमत खुद तय करने के लिए खूब जोर लगाया. इसलिए 1 मई को हुए नीतिगत बदलाव को बड़े अस्पतालों और कॉर्पोरेट चेन के फायदे के लिए तैयार किया गया था.'' इसने निर्माताओं से सीधे थोक ऑर्डर करने की अनुमति दी और नतीजतन, बड़े कॉर्पोरेट चेन के ऑर्डर का आकार छोटे-से-मध्यम व्यवसायों से मेल नहीं खा सकता था. वे कहती हैं, ''वहीं, सरकारी और निजी क्लिनिकों के बीच मूल्य में बड़ा अंतर होने के कारण ज्यादातर लोग, विशेष रूप से छोटे शहरों में, सरकारी क्लिनिकों को चुनना चाहते हैं.''

हमसे चूक कहां हुई?

मई में, सरकार ने आयुष्मान भारत के पैनल में सूचीबद्ध अस्पतालों को टीकाकरण शुरू करने की अनुमति दी. केंद्रों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से, इसमें कुछ बुनियादी जरूरतों को पूरा करने वाले निजी अस्पतालों को शामिल किया गया था. वास्तव में, बड़े चेन अपने समूह की शाखाओं के लिए निर्माताओं से सीधे थोक ऑर्डर के लिए सौदेबाजी करने में सक्षम थे. स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय के एक अधिकारी जो अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहते, कहते हैं, ''एक अस्पताल समूह, एक एकल कॉर्पोरेट इकाई के रूप में कार्य कर रहा है, यहां तक कि कई राज्यों में अपने 20-25 अस्पतालों के लिए ऑर्डर दिया है.'' चूंकि इस तरह के थोक ऑर्डर पर मुनाफे का मार्जिन अधिक था, निर्माताओं ने इनके लिए आपूर्ति को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया. यह मई के मध्य में एक ऐसे चरण में पहुंच गया कि मिसाल के तौर पर, दिल्ली में छोटे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में कोई टीका उपलब्ध नहीं था, लेकिन निजी अस्पतालों में टीकाकरण के लिए बुकिंग की जा सकती थी.

इसके अलावा, कॉर्पोरेट चेनों ने एक नई व्यावसायिक रणनीति शुरू की, जहां कार में बैठे-बैठे टीका लगाने की सुविधा (ड्राइव थ्रू), या कॉर्पोरेट और आरडब्ल्यूए में टीकाकरण के लिए सेवा शुल्क के नाम पर अतिरिक्त रकम वसूली गई. नतीजतन, मई में कोवैक्सीन की एक खुराक की कीमत दिल्ली के एक सरकारी क्लिनिक में 250 रुपए थी, पर एक निजी अस्पताल में ड्राइव थ्रू के लिए 2,500 रुपए तक लिए गए. ऐसोला कहती हैं, ''टीकाकरण को ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए ऐसे नए मॉडल जोड़े गए थे जिसके लिए अधिक कीमत वसूली जा सकती थी. छोटे क्लिनिकों में खुराक की कमी हो गई और टीकाकरण बंद कर दिया गया. निजी क्षेत्र को शामिल करने का लक्ष्य—टीकाकरण केंद्रों और भौगोलिक पहुंच का विस्तार—खत्म हो गया.''

इसे ध्यान में रखते हुए 21 जून को केंद्र ने टीकाकरण नीति में संशोधन किया. अब, एक से अधिक स्थानों के लिए थोक खरीदारी का विकल्प नहीं है. प्रत्येक अस्पताल को अपनी खुराक के लिए कोविन के जरिए एक व्यक्तिगत जरूरत अनुरोध देना पड़ता है. राज्य सरकारों को भी टीकों की समान बिक्री सुनिश्चित करने की शक्ति दी गई ताकि छोटे निजी केंद्रों को भी टीके खरीदने का अवसर मिल सके. जहां सरकार 75 फीसद टीके खरीदेगी, वहीं निर्माता के मासिक उत्पादन का 25 फीसद निजी क्षेत्र के लिए रखा जा सकता है. निर्माता निजी कंपनियों को किस दाम पर खुराक बेचेंगे, उस पर अब कोई मूल्य सीमा नहीं है लेकिन उनके लिए सेवा शुल्क की सीमा प्रति खुराक 150 रुपए तय कर दी गई है. इस प्रकार, कोविशील्ड के लिए शुरुआती कीमत अब 780 रुपए प्रति खुराक, कोवैक्सीन के लिए 1,410 रुपए और राज्यों में निजी क्लिनिकों में स्पुतनिक V के लिए 1,145 रुपए हैं; लेकिन राज्य या केंद्र की ओर से संचालित केंद्रों पर ये टीके मुफ्त लगाए जाते हैं.

हालांकि, निजी केंद्रों पर टीकाकरण की दर कम बनी हुई है. विशेषज्ञों का कहना है कि 'कम से कम 3,000 शीशियों के ऑर्डर' की आवश्यकता, परेशानी के मूल में है. छोटे-से-मध्यम अस्पताल चेन के लिए, इतनी बड़ी खरीद थोड़ा मुश्किल वित्तीय प्रस्ताव है, खासकर तब जब उत्पाद को आगे बेचने पर जो लाभ वे कमा सकते हैं, उसकी एक सीमा तय की जाती हो. एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स (एएचपीआइ) जिसने हाल ही में भारत भर के 70 निजी अस्पतालों में उनके टीकाकरण की स्थिति को समझने के लिए एक सर्वेक्षण किया है, के अध्यक्ष गिरधर ज्ञानी कहते हैं, ''छोटे ऑर्डर का भी प्रावधान होना चाहिए... सरकारी

पीछे छूट रहा निजी क्षेत्र

भारत में हर माह तैयार होने वाले कोविड टीके का 25 फीसद हिस्सा निजी क्षेत्रों के लिए तय किया गया है, लेकिन टीकाकरण की उनकी रफ्तार धीमी है

7%

टीकाकरण, कुल टीकाकरण का, निजी क्लिनिक और अस्पतालों में मई 2021 के बाद से किए गए

8,30,000

टीके (तकरीबन) लगाए गए 15 जून से अब तक निजी क्षेत्रों की ओर से; जबकि कुल 1.2 करोड़ खुराक के ऑर्डर किए गए थे

4,63,000

टीके, निजी क्षेत्रों को दिए गए 35 लाख टीकों में से, लगाए गए आंध्र प्रदेश में. कुछ राज्यों में ज्यादा खुराक बची रह गईं; तमिलनाडु में निजी क्षेत्र को सिर्फ पांच फीसद खुराक दी गई

3 करोड़

अप्रयुक्त टीके राज्यों और निजी क्षेत्रों के पास पड़े हुए थे, 31 जुलाई तक

''निजी क्षेत्र ने टीके लगाने का अधिकार हासिल करने के लिए काफी जोर लगाया, इसलिए मुख्य तौर पर उनके फायदे के लिए मई में नीति को निर्धारण किया गया''

मालिनी ऐसोला

सह-संयोजक, ऑल इंडिया ड्रग ऐक्शन नेटवर्क (एआइडीएएन)

देबज्योति चक्रवर्ती

महामारी के खिलाफ एक और
कोलकाता के आर.एन. टैगोर हॉस्पिटल में 12 जून को स्पुतनिक V लगवाने के बाद फोटो खिंचवाती महिला

और निजी बिक्री के बीच अंतर को कम करने के लिए या तो निर्माता से मूल्य पर बातचीत के लिए विकल्प खुला होना चाहिए या छोटे ऑर्डर की अनुमति दी जानी चाहिए.'' सर्वेक्षण के अनुसार, 25 अस्पतालों ने कहा कि सरकार ने उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए कोई नोडल अधिकारी नियुक्त नहीं किया है. इस बीच, 39 अस्पतालों ने कहा कि नोडल अधिकारी तो नियुक्त किए गए हैं, लेकिन राज्य सरकारें उनकी चिंताओं को दूर करने के कोई प्रयास नहीं कर रही हैं.

समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है?

विशेषज्ञों ने निजी अस्पतालों में बिकने वाले टीकों की कीमत कम करने का सुझाव दिया है. नारायण हेल्थकेयर के अध्यक्ष डॉ. देवी शेट्टी कहते हैं, ''निजी अस्पतालों में एक खुराक की औसतन कीमत 1,000-1,200 रुपए है. दो खुराक का पर करीब 3,000 रुपए खर्च होंगे. एक युगल के लिए, टीके की पूरी खुराक का अर्थ है कि उन्हें 6,000 रुपए देने होंगे. इसके अलावा परिवार के अन्य सदस्य भी हैं. कितने लोग इसे वहन कर सकते हैं? बीते कुछ महीने मजदूर वर्ग और गरीबों के लिए मुश्किल रहे हैं. कई लोगों पास आय का कोई स्रोत नहीं है. सरकार को पैसे और खुराक देने के वक्त को लेकर बातचीत करनी चाहिए.''

राज्यसभा में 4 अगस्त को भाजपा सांसद सुशील कुमारी मोदी के सवाल के जवाब में मंडाविया ने कहा: ''एक महीने में, हमने देखा कि निजी केंद्रों की ओर से हासिल किए गए टीकों का 7 फीसद से 9 फीसद तक अप्रयुक्त रह गया. ऐसे में हमने उन खुराकों को सरकारी कोटे में शामिल करने का फैसला किया. इसलिए निजी क्षेत्र का कोटा घटाने की जरूरत नहीं है. टीकाकरण सुचारू ढंग से हो रहा है.''

केंद्र पहले ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआइआइ) और भारत बायोटेक को 4,500 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि का भुगतान कर चुका है. फिर भी, उत्पादन में उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है. सीरम महीने में लगभग 11-12 करोड़ खुराकें बना रहा है और उत्पादन बढ़ाने की उसकी कोई योजना नहीं है. वहीं, भारत बायोटेक एक महीने में लगभग 2.5 करोड़ खुराक का उत्पादन कर रहा है, जबकि जनवरी में यह कहा गया था कि यह जल्द ही एक महीने में बढ़कर चार करोड़ हो जाएगा. ऐसोला कहती हैं, ''यह तर्क कि निजी अस्पताल चेन को उच्च कीमत पर टीके बेचने से निर्माता अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं, काम नहीं कर रहा है. उत्पादन कम है क्योंकि निर्माता अपनी वर्तमान क्षमता तक पहुंच चुके हैं, इसलिए नहीं कि निर्माताओं के पास पैसा नहीं है.''

ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, जिसने अपनी पूरी वयस्क आबादी का टीकाकरण किया है, ने अपने निजी क्षेत्र का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक अनुकरणीय कार्य किया है. सरकार ने सभी जिलों और नगर निगमों को अस्पतालों के साथ बैठक करने को कहा ताकि उन्हें खरीद प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया जा सके और उनकी मांग और टीकाकरण की क्षमता को नोट किया जा सके. इसके आधार पर खुराक आवंटित की गई. उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में भी इसी तरह की सफलता देखी गई—जुलाई में जिले में किए गए टीकाकरण का 40 फीसद निजी केंद्रों में किया गया था.

अपोलो अस्पताल, दिल्ली के ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर डॉ. अनुपम सिब्बल कहते हैं, ''हमें खरीद में किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा.'' अपोलो समूह निजी क्षेत्र में सबसे बड़ा टीका प्रदाता रहा है. उन्होंने केवल तीन हफ्तों में दस लाख टीके की खुराकें लगाईं और सितंबर तक दो करोड़ खुराक का लक्ष्य रखा है. सिब्बल कहते हैं, ''हमें भी टीके लगवाने में लोगों की हिचकिचाहट जैसी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा—हर बार जब मीडिया में कोई रिपोर्ट आती है, तो लोग टीकों की सुरक्षा पर सवाल उठाने लगते हैं. हमारे डॉक्टर जानकारी मांगने वाले लोगों के सारे सवालों के जवाब देते हैं ताकि उन्हें जागरूक किया जा सके. हमने टीकों से मिलने वाली सुरक्षा पर शोध भी किया और इससे कई लोगों को अपनी झिझक दूर करने में मदद मिली है.''

वहीं, बेंगलूरू में एक प्रमुख निजी टीका प्रदाता फोर्टिस बेंगलूरू का कहना है कि 18 से ऊपर के सभी के लिए टीकाकरण की शुरुआत के बाद, अस्पताल को मांग बढ़ाने के लिए काम करना पड़ा. बन्नेरघट्टा रोड पर स्थित फोर्टिस की मेडिकल डायरेक्टर डॉ. प्रिया श्रीधरन का कहना है कि अस्पताल ने टीकाकरण को लेकर जागरूकता अभियानों के बाद मांग में वृद्धि देखी है. वे कहती हैं, ''हमें लोगों को बताना पड़ा कि आप टीका लगवाने के बाद भी कोविडग्रस्त हो सकते हैं, लेकिन उस स्थिति में आपको कोविड का गंभीर संक्रमण नहीं होगा.''

विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की रिप्रोडक्टिव (आर) संख्या बढ़कर 1 से अधिक हो गई है, जिसका अर्थ है कि पहले से ही संक्रमित व्यक्ति से औसतन एक से अधिक व्यक्ति संक्रमित हो रहे हैं और करीब 43 जिलों में कुल सकारात्मकता दर 10 फीसद से अधिक है, इसलिए देश को चाहिए कि हर महीने आपूर्ति होने वाले टीकों की पूरी खेप का उपयोग करने के लिए हरसंभव प्रयास करे. स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडु तथा केरल सहित आठ राज्यों में आर वैल्यू 1 से अधिक है. विशेषज्ञों की मानें तो वहां तेजी से टीकाकरण प्राथमिकता होनी चाहिए. विशेष रूप से केरल, असम, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जहां सेरोपोजिटिविटी कम है, यह दर्शाता है कि वहां लोग वायरस के संपर्क में कम आए या यहां उनके अंदर ऐंटीबॉडी कम तैयार हुई. पर्याप्त टीकाकरण के जरिए ही तीसरी लहर के प्रभाव को कम किया जा सकता है. ■

फोटोः मनीष अग्निहोत्री

खास रपट | उत्तर प्रदेश

मांगें मनवाने का मौसम

अगले साल विधानसभा चुनावों से पहले विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के साथ-साथ अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों के लिए मोर्चा खोल दिया है. योगी सरकार के सामने इनकी नाराजगी दूर करने की बड़ी चुनौती

आशीष मिश्र

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यालय, लोकभवन से सटा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का कार्यालय इन दिनों कर्मचारियों और अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का केंद्र बना हुआ है. 2 अगस्त की दोपहर एक बजे संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा के बैनर तले बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट (बीटीसी)/डिप्लोमा इन इलेमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) प्रशिक्षुओं ने भाजपा कार्यालय का घेराव कर नई शिक्षक भर्ती की मांग की. बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक बसों में लाद कर इको गार्डन छोड़ दिया जहां पर वे एक महीने से आंदोलन कर रहे थे. मोर्चा के अध्यक्ष रजत सिंह कहते हैं, ''सरकार ने वादा किया था कि बेसिक शिक्षा विभाग में हर वर्ष भर्ती लेंगे पर बीते दो साल से कोई भर्ती नहीं निकाली गई. फिलहाल करीब 21 लाख प्रशिक्षु टीइटी और सीटीइटी उत्तीर्ण कर बैठे हैं. हर वर्ष 10 से 15 हजार शिक्षकों की संख्या को जोड़कर सरकार को करीब 97,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया तुरंत शुरू करनी चाहिए.'' इससे पहले 29 जुलाई को 69 हजार शिक्षकों की भर्ती में 22 हजार पदों को जोड़ने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने भाजपा कार्यालय का घेराव किया था.

वहीं, 108-102 एंबुलेंस सेवा में तैनात करीब 20 हजार से अधिक कर्मचारियों ने 25 जुलाई की देर रात हड़ताल कर एंबुलेंस सेवा ठप कर

लखनऊ में
चारबाग रेलवे स्टेशन का घेराव करते पुलिस भर्ती के अभ्यर्थी (बाएं)
लखनऊ के
इको गार्डन में अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करते एंबुलेंस कर्मी (ऊपर)

दी. सरकार की चेतावनी के बावजूद प्रदेश भर से पहुंचे एंबुलेंस कर्मचारियों ने लखनऊ के इको गार्डन स्थित धरना स्थल पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया. एंबुलेंस सेवा ठप होने का खमियाजा मरीजों ने भुगता और हड़ताल के पहले ही दिन प्रदेश भर में 10 मरीजों ने एंबुलेंस न मिलने पर दम तोड़ दिया. एडवांस लाइफ सपोर्ट (एएलएस) एंबुलेंस का संचालन नई कंपनी जिगित्सा को सौंपा गया है. इससे पहले 108-102 एंबुलेंस सेवा के साथ एएलएस एंबुलेंस सेवा के संचालन की जिम्मेदारी भी जीवीके इएमआरआइ कंपनी के पास थी. एंबुलेंस कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे बताते हैं, ''250 एएलएस एंबुलेंस का संचालन करने वाली नई कंपनी न केवल कर्मचारियों को मानदेय कम दे रही है बल्कि ट्रेनिंग के नाम पर एडवांस भी जमा करा रही है. शासन से इस मामले की शिकायत की लेकिन कोई हल न निकलने पर 108-102 एंबुलेंस सेवा के कर्मचारी भी एएलएस एंबुलेंस कर्मियों के समर्थन में हड़ताल पर चले गए.'' एंबुलेंस कर्मियों की हड़ताल को 10 दिन से अधिक समय बीत चुका है. इस बीच एस्मा का हवाला देकर जीवीके इएमआरआइ कंपनी ने प्रदेश भर में ढाई हजार से अधिक कर्मचारियों को बर्खास्त कर नए कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह कहते हैं, ''एंबुलेंस संचालन की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है. मरीजों को कोई कठिनाई न हो इसका ध्यान रखा जा रहा है.''

प्रदेश में वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारी और विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं के अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर लामबंद होने लगे हैं. इलाहाबाद विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र विभाग के पूर्व प्रोफेसर वी. के. सक्सेना बताते हैं, ''विधानसभा चुनाव के नजदीक आने पर सरकार किसी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना चाहती. इस मौके का फायदा कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए उठाना चाहते हैं. मांगों पर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए ही धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं. राज्य में 18 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी हैं. विधानसभा चुनाव से पहले इनकी नाराजगी मोल लेना सत्तारूढ़ दल को नुकसान पहुंचा सकता है.''

वेतन, पेंशन को लेकर लामबंदी

लंबित मांगों पर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए जुलाई, 2020 में 'कर्मचारी शिक्षक अधिकारी एवं पेंशनर्स अधिकार मंच' का गठन किया गया था. इसमें विभिन्न विभागों के करीब 150 संगठन शामिल हैं. कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर मंच सितंबर में एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा बना रहा है. कर्मचारियों की पहली मांग पेंशन बहाली को लेकर है. तीन साल पहले कर्मचारियों की पेंशन संबंधी समस्याओं के निदान के लिए एक कमेटी बनाई गई थी. उसकी बैठक भी हुई लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल सका है. आज जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उन्हें शेयर बाजार से 500 से लेकर 1,200 रुपए तक महीना पेंशन मिल रही है. राज्य वेतन समिति की सिफारिशों को लागू न किए जाने से भी राज्य कर्मचारियों में आक्रोश है.

राज्य वेतन समिति-2016 ने चरणबद्ध ढंग से अपनी कुल सात रिपोर्ट फरवरी 2018 तक सरकार को सौंपी थी. इनमें पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स, महंगाई भत्ता, सुनिश्चित करिअर प्रोन्नयन, पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण से जुड़ी सिफारिशों वाली पहली और सातवीं रिपोर्ट पर कैबिनेट से निर्णय हो चुका है. समिति की बाकी पांच रिपोर्ट अब तक ठंडे बस्ते में है. इससे कर्मचारियों में नाराजगी पनप रही थी. जुलाई में राज्य वेतन समिति की पांच रिपोर्ट पर विचार करने के लिए मुख्य सचिव कमेटी का गठन किया गया है. नवगठित कमेटी की सबसे बड़ी चुनौती समय रहते अपनी संस्तुतियां देकर उसे लागू करवाने की है.

कर्मचारियों ने उन मांगो को भी प्राथमिकता के तौर पर पूरा करने की अपील की है जिनसे कोई वित्तीय भार नहीं पड़ने वाला. राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अतुल मिश्र बताते हैं, ''नर्सेज संवर्ग ने केंद्र के समान पदनाम की मांग की है. इससे सरकार को कोई वित्तीय क्षति नहीं पहुंचेगी. केंद्र में नर्सेज संवर्ग का पदनाम परिवर्तित कर दिया गया है, पर समझौते के बावजूद प्रदेश में नाम परिवर्तन नहीं हो सका. वही, फार्मेसिस्ट, लैब टेक्नीशियन और ऑप्टोमेट्रिस्ट संवर्ग की वेतन विसंगति मसले पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी को निर्णय करना है. फार्मेसिस्ट संवर्ग में लगभग सभी फार्मेसिस्ट पहले ही ऐसे वेतनमान में पहुंच चुके हैं जहां प्राथमिक वेतनमान परिवर्तन से सरकार पर वित्तीय भार नहीं आएगा. यही स्थिति लैब टेक्नीशियन एवं ऑप्टोमेट्रिस्ट की भी है.''

विभिन्न विभागों में पदोन्नति के पद रिक्त पड़े हुए हैं. फार्मेसिस्ट संवर्ग

में विशेष कार्य अधिकारी और संयुक्त निदेशक फार्मेसी के पद कई वर्षों से प्रोन्नत कर नहीं भरे गए. परिषद के उपाध्यक्ष सुनील यादव कहते हैं, ''पदों का सृजन, मानक निर्धारण आदि ऐसी समस्याएं हैं जिससे सभी संवर्ग प्रभावित हो रहे हैं. जनता भी प्रभावित होती है क्योंकि मानव संसाधन की कमी से जन सेवा में बाधा पड़ती है. दूसरे राज्यों में फार्मेसिस्ट का पदनाम फार्मेसी अधिकारी, चीफ फार्मेसिस्ट को बदलकर चीफ फार्मेसी अधिकारी किया जा चुका है, इस क्रम में यूपी के फार्मेसिस्ट संवर्ग के पदनाम परिवर्तन की मांग की गई है. सभी संवर्गों के पदनाम परिवर्तन से सरकार को कोई वित्तीय भार नहीं आना है, बल्कि यह कोरोना योद्धाओं के लिए एक उपहार जैसा होगा.''

कैशलेस इलाज की लंबित मांग

बड़ी समस्या कर्मचारियों के कैशलेस इलाज को लेकर भी है. प्रदेश सचिवालय में कार्यरत रहे सेवानिवृत्त निजी सचिव राम दयाल वर्मा ने अपने हृदय रोग का इलाज लखनऊ के गोमतीनगर स्थित मेदांता अस्पताल में कराया. इलाज में खर्च हुए दो लाख रुपए का चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में पेश किया. कार्यालय ने वर्मा के दावे को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि उन्होंने लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआइ) या किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में इलाज न कराकर महंगे संस्थान से इलाज कराया है. अगर कैशलेस इलाज की सुविधा होती तो वर्मा को इलाज में आर्थिक नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता. यह सुविधा न होने से प्रदेश के 25 लाख से अधिक राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के भुगतान के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं. कर्मचारी नेता जुगल वाल्मीकि बताते हैं, ''चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को असाध्य रोगों के इलाज के लिए लाखों रुपए का इंतजाम कराना काफी मुश्किल होता है. इस कारण वे सही इलाज नहीं करा पाते हैं. जो लोग पैसों का इंतजाम करके किसी तरह इलाज करा लेते हैं उन्हें चिकित्सा प्रतिपूर्ति के भुगतान के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से लेकर शासन तक चक्कर लगाने पड़ते हैं.''

वाल्मीकि के मुताबिक, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे पर अनावश्यक आपत्तियां लगाई जाती हैं और प्रतिपूर्ति की राशि में भी कटौती कर दी जाती है. इस जटिल प्रक्रिया के चलते राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को गंभीर बीमारी में कैशलेस इलाज की सुविधा का फैसला पिछली समाजवादी पार्टी (सपा) सरकार में हुआ था. वर्ष 2015 में तत्कालीन वित्त आयुक्त और प्रमुख सचिव वित्त राहुल भटनागर की अध्यक्षता वाली समिति ने इस योजना की रूपरेखा तैयार की थी. यह योजना हकीकत में आती उससे पहले वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव आ गए. चुनाव बाद प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी. भाजपा सरकार ने इस योजना का नामकरण पंडित दीन दयाल उपाध्याय

कई विभाग हलकान

- स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत 1,700 कर्मचारियों का 15 जुलाई को तबादला. मृतकों और रिटायर कर्मियों के भी तबादले हुए. नियम विरुद्ध तबादले भी किए गए. यूपी मेडिकल ऐंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्टीरियल एसोसिएशन के आंदोलन के बाद विभाग बैकफुट पर आया.
- वर्ष 2015 में सिपाहियों के 34,716 पदों की लंबित भर्ती प्रक्रिया पूरी करने और वर्ष 2018 में सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाकर अभ्यर्थियों ने 14 जुलाई को लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर बड़ा प्रदर्शन किया.
- स्थानीय निकायों में कार्यरत 2 लाख से अधिक कर्मचारी समय से वेतन, पेंशन और मृतक आश्रितों की नियुक्ति शैक्षिक योग्यता के अनुरूप करने, सेवा और वेतन विसंगतियां दूर करने, संविदा कर्मचारियों का विनियमितीकरण जैसी मांगों को लेकर आक्रोशित हैं.
- राजकीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को आठ माह से वेतन नहीं मिला है. बजट का अभाव बताया जा रहा. इससे शिक्षकों की सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ रही है.
- नोएडा विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का विरोध, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने, संविदा कर्मियों को नियमित करने, विशेष वेतन वृद्धि, आगरा में बिजली वितरण का फ्रेंचाइजी-करण खत्म करने की मांग को लेकर बिजली कर्मचारी 10 अगस्त को कार्य बहिष्कार करेंगे.
- स्वास्थ्य विभाग में 3,500 मल्टीपरपज हेल्थ वर्कर (एमपीडब्ल्यू) मलेरिया, फाइलेरिया समेत विभिन्न बीमारियों की दवा वितरण और जागरूकता में लगे थे. वर्ष 2014 में इनमें से ज्यादातर को हटा दिया गया था. पुनर्नियुक्ति की मांग को लेकर ये वर्कर आंदोलनरत हैं.
- राजस्व लेखपालों को आय-जाति और निवास प्रमाणपत्र जारी करने के खर्च के रूप में प्रति प्रमाणपत्र पांच रुपये देने का फैसला जुलाई 2018 में हुआ था. शासन और राजस्व परिषद के आदेश के बावजूद भुगतान न होने से प्रदेश के लेखपाल संवर्ग में आक्रोश है.
- प्रदेश में सरकारी नौकरियों को आउटसोर्सिंग से भरने को प्रोत्साहन दिए जाने पर कर्मचारियों में गहरी नाराजगी है. आउटसोर्सिंग में नियुक्ति के समय एडवांस वसूली, नवीनीकरण में मुश्किलें, समय से मानदेय भुगतान की समस्याएं को लेकर कर्मचारी नाराज हैं.
- गांव में तैनात सफाई कर्मचारियों को प्रधानों से मुक्त करने की मांग बीते कई वर्षों से हो रही है. सफाई कर्मचारियों की मांग है कि प्रधानों की बजाय उन्हें ब्लॉक डेवलेपमेंट ऑफिसर या ग्राम विकास अधिकारी के अंतर्गत तैनात किया जाए.

लखनऊ में स्वास्थ्य निदेशालय भवन पर अनियमित तबादलों के विरोध में धरना देते स्वास्थ्य कर्मचारी (बाएं).
नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर प्रदेश भाजपा मुख्यालय का घेराव करते अभ्यर्थी (दाएं)

के नाम पर करने के साथ ही इसके क्रियान्वयन संबंधी दिशानिर्देश सितंबर, 2017 में जारी कर दिए. इसके मुताबिक, प्रदेश के राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को लखनऊ में एसजीपीजीआइ, डॉ. राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, केजीएमयू के अलावा इटावा के ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई जैसे संस्थानों में कैशलेस नि:शुल्क इलाज की सुविधा देने का प्रावधान किया गया. इन संस्थानों में सरकार की ओर से कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मुख्य कार्यपालक अधिकारी 'स्टेट एजेंसी फॉर कंप्रहेंसिव हेल्थ ऐंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज' (सांची) से प्रस्ताव प्राप्त कर अलग से एक कार्पस फंड की व्यवस्था करने का भी प्रावधान किया गया.

इस योजना में अनुबंधित निजी अस्पताल और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (सीजीएचएस) को भी शामिल करने का फैसला हुआ था. इस योजना के लिए कर्मचारियों और पेंशनरों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कराया गया. स्टेट हेल्थ कार्ड भी जारी किए गए पर योजना के क्रियान्वयन के लिए 78 करोड़ रुपए का कार्पस फंड बनाने की कार्यवाही अभी तक पूरी नहीं हो पायी है. यूपी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी बताते हैं, ''कैशलेस इलाज की योजना के क्रियान्वयन को लेकर शासन में कई स्तरों पर बातचीत हुई लेकिन उसका अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है. इसके कारण राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स इलाज के बाद शोषण तथा धक्के खाने को मजबूर हैं. इस योजना से सरकार पर कोई अलग से वित्तीय भार नहीं पड़ेगा बल्कि भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी.'' मुख्यमंत्री योगी ने मुख्य सचिव आर.के. तिवारी को दीन दयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के क्रियान्वयन की अड़चनों को दूर करने का आदेश दिया है जिससे 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले योजना के हकीकत में बदलने की संभावना बढ़ गयी है.

मुख्यमंत्री योगी ने संभाली कमान

कर्मचारियों की मांगों के निस्तारण की कमान सीधे मुख्यमंत्री योगी ने संभाल ली है. उनकी पहल पर कर्मचारियों और पेंशनरों को 11 फीसद महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने की राह खुल गई है. सरकार ने महामारी का हवाला देकर वर्ष 2020 में इन भत्तों पर रोक लगा दी थी. परिषदीय विद्यालय की 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी का आरोप लगाकर अभ्यर्थी बीते एक महीने में एससीइआरटी कार्यालय, डिप्टी सीएम, विभागीय मंत्री एवं भाजपा कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर चुके हैं. ये अभ्यर्थी 2 अगस्त को भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास का घेराव करने पहुंचे थे. सुबह करीब 11 बजे अभ्यर्थी मौर्य से अपनी बात कहने को प्रयासरत थे. उसी वक्त योगी अपने सरकारी आवास के बगल में बने हॉल में जनता दर्शन कर रहे थे. उनकी निगाह अभ्यर्थियों पर पड़ी तो उन्होंने अधिकारियों को भेजकर अभ्यर्थियों को बुलाया और उनकी मांग सुनीं. योगी ने अभ्यर्थियों को भरोसा दिया कि अधिकारी उनके साथ बैठक कर समस्याओं को निस्तारण करने का प्रयास करेंगे. उनकी इस पहल से गदगद अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन टाल दिया. शाम को बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव और अगले दिन प्रमुख सचिव ने अभ्यर्थियों से बातचीत की. इससे शिक्षक भर्ती में आरक्षण पर उठ रहे सवालों के हल की राह खुल गई है. प्रदेश सरकार के प्रवक्त और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह बताते हैं, ''प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति बेहद संवेदनशील है. कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार सभी संभव कदम उठा रही है.''

मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने कर्मचारियों की समस्याओं के हल के लिए नए सिरे से आदेश जारी किए. उन्होंने 27 जुलाई को सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर अपने-अपने विभाग और जिलों में हर माह कम-से-कम एक बार मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक करने और उनका निस्तारण सुनिश्चित करने कहा है. कर्मचारियों की सेवा संबंधी समस्याओं के निस्तारण के लिए हर हफ्ते एक बार बैठक करने का भी आदेश तिवारी ने दिया है. लालफीताशाही को मांगों के निराकरण में मुख्य बाधा बताने वाले कर्मचारियों को अधिकारी कितना संतुष्ट कर पाते हैं, इसी से योगी सरकार की कर्मचारियों के बीच सकारात्मक छवि का निर्माण होगा. ■

लाजवाब बेटियों का चमत्कार

तमाम दिक्कतों और दुश्वारियों के बावजूद देश की महिला खिलाड़ियों ने हमारा सिर ऊंचा किया, मगर कुल पदक तालिका निराशजनक, भविष्य में ओलंपिक पदक हासिल करने का यह है ब्लूप्रिंट

बोरिया मजूमदार, तोक्यो में

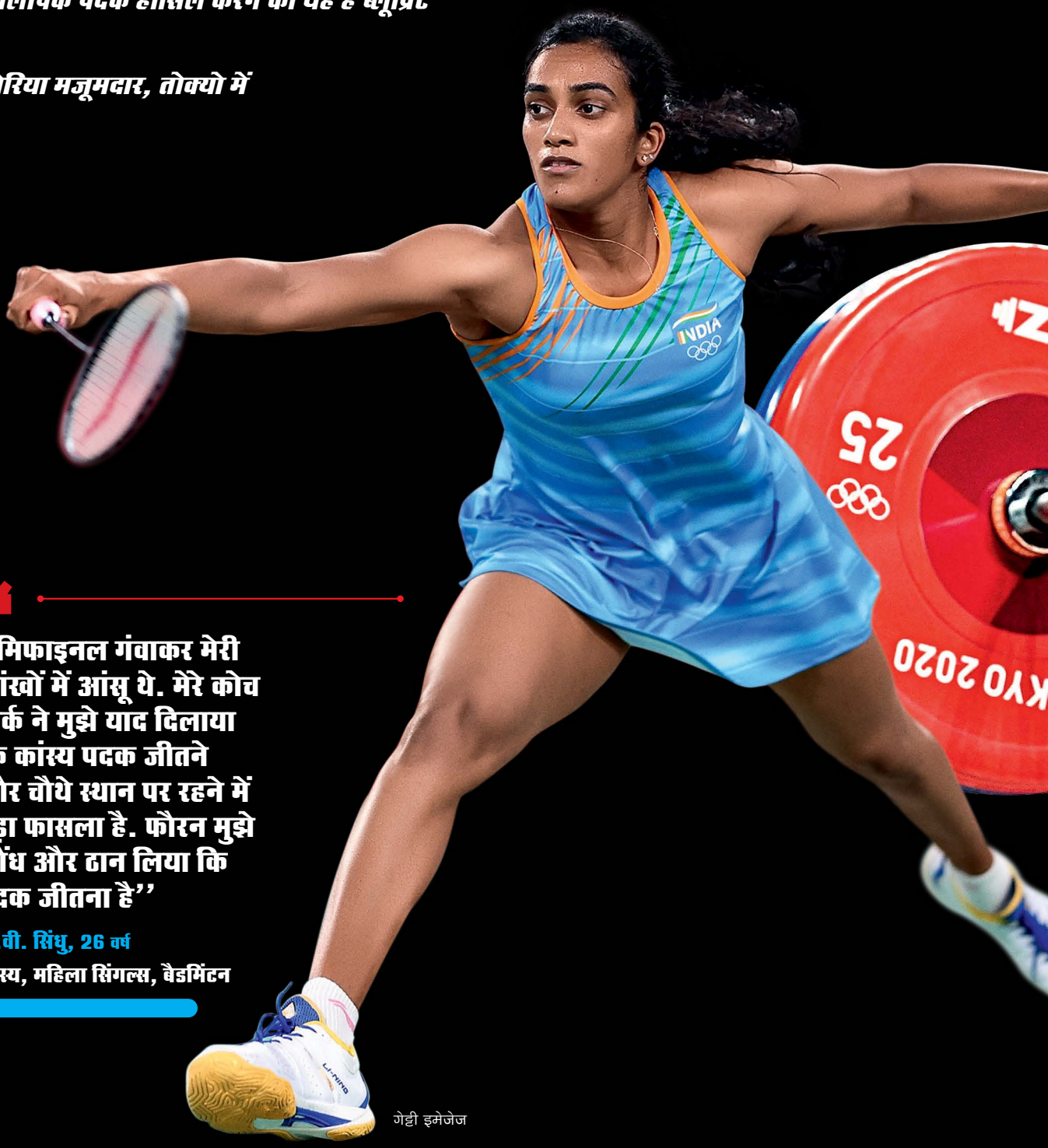

सेमिफाइनल गंवाकर मेरी आंखों में आंसू थे. मेरे कोच पार्क ने मुझे याद दिलाया कि कांस्य पदक जीतने और चौथे स्थान पर रहने में बड़ा फासला है. फौरन मुझे कौंध और ठान लिया कि पदक जीतना है''

पी.वी. सिंधु, 26 वर्ष
कांस्य, महिला सिंगल्स, बैडमिंटन

गेट्टी इमेजेज

TOKYO 2020

“रियो ओलंपिक के बाद मेरा मन खट्टा हो गया था. फिर 2018 के कॉमनवेल्थ खेलों में जीत के बाद मैंने ओलंपिक पदक का सपना देखा. आखिरकार वह सच हो गया”

मीराबाई चानू, 26 वर्ष
रजत, महिला भारोत्तोलन, 49 किलो वर्ग

“मैं एन.सी. चेन से चार बार हार चुकी थी. मेरे लिए खुद से यह साबित करने की चुनौती यह थी कि मैं हरा सकती हूं. मेरे पास कोई तरकीब नहीं थी. मैं खुल के खेली”

लवलीना बोरगोहेन, 23 वर्ष
कांस्य, महिला वेल्टरवेट बॉक्सिंग

एएफपी

पारस सैनी/एसएआई

TOKYO 2020

पी.वी.

जैक गुएज/गेट्टी इमेजेज

सिंधु ने अभी-अभी अपना दूसरा ओलंपिक पदक जीता था और मुसाशिनो फॉरेस्ट स्पोर्ट प्लाजा के स्टैंड में हम जैसे कुछ भारतीय खुशी से झूम उठे थे. आखिरकार, भारत की झोली में आज भी ओलंपिक पदक मुश्किल से आते हैं और सिंधु ऐसी अपवाद हैं, जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता में लगातार दो बार पदक जीतकर भारतीयों का दिल बाग-बाग कर दिया है.

सिंधु को पता था कि मैं विशेष बातचीत के लिए दबाव डालूंगा, और वे खुशी-खुशी तैयार भी हो गईं थीं. लेकिन परिस्थितियां असाधारण थीं और तोक्यो खेलों में कोविड-सुरक्षा मानदंड काफी सख्त थे. हममें से कोई नहीं जानता था, उस समय एक नियमित मैच/स्पर्धा के फौरन बाद 'विशेष' बातचीत कितनी मुश्किल होगी. जैसे ही वे अनिवार्य मैच-बाद डोप टेस्ट से बाहर निकलीं, आयोजकों ने सिंधु को एथलीटों के कमरे तक पहुंचाने के लिए एक सुरक्षा घेरा तैयार कर लिया. बातचीत के लिए बाहर निकलना सरकार के तय अनिवार्य मानदंडों का उल्लंघन होता, और चेतावनी भी कड़ी थी, ''आप उनके साथ जाती हैं तो आप एथलीट विलेज (खिलाड़ियों के ठहरने की जगह) नहीं लौट सकतीं!''

तब तक, भारत में टीवी न्यूजरूम में अफरातफरी मच चुकी थी. सबको लग रहा था कि शायद सिंधु से बहुप्रतीक्षित बातचीत नहीं हो पाएगी. बहुत समझाने के बाद, सिंधु को प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में एक प्रिंट इंटरव्यू (कैमरे को बिल्कुल इजाजत नहीं!) की अनुमति दी गई. वहां एक अधिकारी को यह देखने के लिए तैनात किया गया था कि हम छह फुट की सुरक्षित दूरी हर हाल में बनाए रखें. हमें कोई और रास्ता निकालना था.

सिंधु गेम्स विलेज के लिए निकलीं और मैं अपने होटल की ओर जाने वाली मीडिया बस में चढ़ गया लेकिन उनका एक मैसेज आया तो बीच रास्ते में उतर गया. हमने अंततः सुबह के 3 बजे, रास्ते में किसी अंजान स्थान पर जूम कॉल पर बातचीत रिकॉर्ड की! उन्होंने मुझे जो बताया, उसके बाद लगा कि बातचीत के लिए इतनी मशक्कत सफल रही. सिंधु ने बताया, ''बहुत ज्यादा दबाव था और मुझे पता था कि भारत में लोग मुझसे हर चीज की उम्मीद कर रहे थे. जब मैं खेल रही थी तब मैंने उन भावनाओं को परे रखा और अपना सर्वश्रेष्ठ दिया. यह आसान नहीं होता. इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. अब मैं बहुत खुश हूं.''

पुरुष जो चमके

महिला एथलीटों की चमक से पीछे पुरुषों का प्रदर्शन ढंक गया लेकिन कुछ खिलाड़ियों ने प्रभावशाली रिकॉर्ड कायम किए

नीरज चोपड़ा, 23 वर्ष

भाला फेंक

2018 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता और पूर्व जूनियर विश्व चैंपियन क्वॉलिफिकेशन दौर तक पहले स्थान पर रहे, जहां उन्होंने स्वर्ण के सबसे बड़े दावेदार जर्मनी के जोहान्स वेटर को बाहर कर दिया. पहले थ्रो में चोपड़ा ने 83.5 मीटर के क्वॉलिफिकेशन मार्क को पार कर लिया. शनिवार को नतीजा चाहे जो हो, वे फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय होने का इतिहास बना दिया है.

रवि कुमार दहिया, 23 वर्ष

फ्रीस्टाइल कुश्ती (57 किग्रा)

ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाले दहिया, सुशील कुमार के बाद महज दूसरे पहलवान हैं. दो बाउट को तकनीकी दक्षता से आराम से पार करने वाले दहिया ने सेमीफाइनल में कमाल का जोश और जज्बा दिखाया. उन्होंने एक मिनट से भी कम समय में पलटवार किया. फाइनल में उन्हें चांदी से संतोष करना पड़ा लेकिन कुश्ती का नया सितारा जन्म ले चुका है.

एएफपी

फवाद मिर्जा, 29 वर्ष

इक्वेस्ट्रियन (इवेंटिंग)

सिग्नूर मेडिकॉट के साथ स्पर्धा में जिस घोड़े के साथ उन्होंने 2018 एशियाई खेलों में दो रजत जीते, मिर्जा ने ड्रेसेज में अच्छी शुरुआत की, और वे शीर्ष 10 में शामिल रहे. उनकी रैंकिंग क्रॉस कंट्री और जंपिंग जैसे बाद के राउंड में गिर गई, लेकिन दुनिया में 70वीं रैंकिंग के घुड़सवार ने 25 जोड़ियों के अंतिम दौर के लिए क्वालीफाइ करने के लिए एंप्लॉफ्ब के साथ सवारी की. यह दुनिया भर से 63 सवारों के एलीट ग्रुप के बीच अविश्वसनीय उपलब्धि है.

-सुहानी सिंह

वेंकटराज मेहरी/एएफपी

TOKYO 2020

पत्रकारिता के लिहाज से तोक्यो 2020/21 अब तक के सबसे कठिन ओलंपिक खेलों में गिना जाएगा. लेकिन कभी-कभी दर्द देने वाले इन प्रोटोकॉल पर जोर देना भी जरूरी है क्योंकि इन्हीं की बदौलत आयोजक आयोजन करने में कामयाब रहे. कयामत के दिनों की तमाम आशंकाओं के बावजूद, इन खेलों के प्रमुख प्रतिभागियों–अधिकारियों, एथलीटों, अनुबंधित कर्मचारियों और मीडिया के बीच कोविड के मामले कभी भी 0.02 प्रतिशत के निशान से ऊपर नहीं गए और कुल मिलाकर खेलों का आयोजन अच्छी तरह होता गया है.

हालांकि कुछ बेजोड़ प्रदर्शन देखने को मिले, बावजूद इसके ओलंपिक में भारतीय अभियान बहुत प्रभावशाली तो नहीं रहा. कुछ खिलाड़ियों ने लाजवाब प्रदर्शन किया लेकिन दोहरे अंकों में पदक जीतने की उम्मीद पूरी नहीं हुई, जो तोक्यो के लिए रवाना होते समय वाजिब उम्मीद लगती थी. निशानेबाजी टीम लगातार दूसरे ओलंपिक में कोई कमाल नहीं कर सकी; तीरअंदाज उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे; विकास कृष्ण और अमित पंघाल जैसे मुक्केबाजों को जितना प्रचार मिला था, प्रदर्शन उससे एकदम उलटा रहा; और बैडमिंटन में चिराग शेट्टी और सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी जैसे कुछ खिलाड़ी बदकिस्मत रहे जो अपने दो मैच जीतकर भी क्वार्टर फाइनल में जगह नहीं बना सके.

लेकिन इन निराशाओं और पदकों के सूखे के बीच भी, कुछ साहसी प्रयासों की कहानियां हैं, जिसने रोमांच बनाए रखा. कोई कल्पना कर सकता था कि तीन बार की ओलंपिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की महिला हॉकी टीम को भारत की लड़कियां हरा देंगी. फिर भी रानी रामपाल ने अपनी लड़कियों को *चक दे! इंडिया* करने के लिए प्रेरित किया, जिन्होंने हॉकी स्टिक बस इसलिए उठाई थी कि इससे उनके पास एक पक्का घर हो सके और दिन में दोनों वक्त भरपेट खाना मिल सके. भले ही वे सेमीफाइनल में हार गईं, फिर भी एक अपेक्षाकृत कमजोर मानी जा रही भारतीय टीम ने सभी बाधाओं को पार करते हुए महिला हॉकी में सर्वश्रेष्ठ टीम के खिलाफ जो खेल दिखाया उसने इस खेल के लिए पुनर्जागरण की एक प्रेरक कहानी लिखी. ओई हॉकी स्टेडियम का वह दृश्य जहां मारे खुशी के रोती लड़कियां और लाउडस्पीकर पर बजता हिंदी गाना, यह सब तो शाहरुख खान की फिल्म में ही हो सकता था. इस बार, यह सब हकीकत में था.

33*

पदक ओलंपिक में भारत के हिस्से 1900 से अब तक आए हैं

34*

पदक चीन सिर्फ तोक्यो ओलंपिक में ही जीत लिया है

*5 अगस्त 2021 तक

हॉकी पकड़ने वाली लड़कियां अकेली नहीं थीं. छोटे कदवाली मीराबाई चानू, जो इंफाल से 22 किमी दूर अपने गांव के घर में जलावन के लिए पर्याप्त लकड़ियां लाने के लिए बड़े गट्ठर उठा लेती थीं, ने तोक्यो में प्रतियोगिता के पहले ही दिन भारतीय उम्मीदों की लौ जला दी. रियो में असफलता से लेकर तोक्यो में रजत पदक तक, चानू इस बात का प्रमाण हैं कि लगन और कड़ी मेहनत से सपने साकार हो जाते हैं. बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन के गांव में उनके घर तक जाने के लिए पक्की सड़क नहीं थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने पदक पक्का किया, असम सरकार ने अपने नए चैंपियन के प्रति सम्मान का प्रदर्शन करते हुए सड़क निर्माण शुरू कर दिया, ताकि कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी का अपने घर तक का सफर सुगम हो जाए. चानू और लवलीना ने

जस्टिन सेटरफिल्ड/गेट्टी इमेजेज

तीरअंदाजी

दीपिका कुमारी तोक्यों में नंबर एक रैंकिंग के साथ पहुंची लेकिन उनकी यात्रा क्वार्टर फाइनल तक ही रही, जो तीन ओलंपिक में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था. वे दक्षिण कोरिया की आन सान से हार गईं, जो अंततः चैंपियन बनीं. अतनु दास ने रोमांचक मुकाबले में 2012 के ओलंपिक चैंपियन ओह जिन-हाएक को हरा दिया लेकिन उसके बाद वे टोक्यो के कांस्य विजेता ताकाहारु फुरुकावा से प्री-क्वार्टर फाइनल में हार गए. मिक्स्ड टीम के लिए कुमारी और दास की जोड़ी काम नहीं आई. दास निजी रैंकिंग में प्रवीण जाधव से पिछड़ गए.

कमजोर प्रदर्शन

भारतीय तीरअंदाजों, निशानेबाजों और मुक्केबाजों को लेकर उम्मीदें ऊंची थीं, लेकिन लचर प्रदर्शनों और जल्दी बाहर होने से ज्यादा कुछ हासिल नहीं हो पाया

निशानेबाजी

उम्मीद थी कि भारत के निशानेबाज लंदन 2012 के प्रदर्शन से बेहतर नहीं, तो वैसा प्रदर्शन जरूर करेंगे, जहां भारतीय दल ने दो पदक जीते थे. ऐसा नहीं हो पाया. केवल सौरभ चौधरी ही फाइनल में पहुंचे. बाकी खिलाड़ी दबाव में बिखर गए, जिसमें मनु भाकर और अभिषेक वर्मा सहित कई अंतिम दौर में लक्ष्य को हिट करने में विफल रहे.

पुरुष मुक्केबाजी

बॉक्सिंग टीम में भारत के पुरुष मुक्केबाजी दल के लिए उम्मीदें अधिक थीं, जिसमें फ्लाइवेट में दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी अमित पंघाल शामिल थे. पंघाल, मनीष कौशिक और विकास कृष्ण पहले दौर में ही हार गए. सतीश कुमार एक मैच जीतने वाले अकेले योद्धा थे. अभी भी 2008 बीजिंग में विजेंदर सिंह ओलंपिक पदक जीतने वाले एकमात्र पुरुष मुक्केबाज हैं.

—सुहानी सिंह

निशानेबाजी के खिलाड़ियों को हर सुविधा मुहैया है. फिर भी एनआरएआइ की एक गोपनीय रिपोर्ट के मुताबिक 70 फीसद खिलाड़ी हर बड़ी स्पर्धा में इसलिए पिछड़ जाते हैं क्योंकि वे दबाव में आ जाते हैं या आत्म-नियंत्रण नहीं रख पाते

जहां पदक जीते, वहीं तलवारबाज सी.ए. भवानी देवी, मनिका बत्रा (टेबल टेनिस), कमलप्रीत कौर (डिस्कस थ्रो) ने भी तोक्यो में प्रभावित किया है. यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि भारत के नजरिए से यह ओलंपिक महिलाओं के नाम रहा और उन्होंने पुरुष खिलाड़ियों के मुकाबले भारत को अधिक खुशी दी.

खेलों में और अधिक महत्वपूर्ण खेलपूर्व तैयारियों में भारतीय प्रयासों के करीबी विश्लेषण से पता चलेगा कि आकांक्षाओं को तो परे ही कर दें, सम्मान योग्य प्रदर्शन से भी कोसों दूर क्यों रह जाते हैं. बेशक, हमने कुछ अच्छे कदम उठाए हैं, और कुछ प्रगति भी की है लेकिन ओलंपिक में शीर्ष 10 पदक विजेताओं की सूची में जगह बनाने से अभी भी हम कम से कम एक दशक दूर हैं. तोक्यो भी कुछ अलग नहीं था. हम उम्मीद कर सकते हैं कि निशानेबाजी में आगे कुछ बात बनेगी और शायद बॉक्सिंग में भी, फिर भी पेरिस 2024 में किसी जादुई बदलाव की उम्मीद नहीं है. हमें अपनी आकांक्षाओं को सीमित

TOKYO 2020

धमाकेदार वापसी

आखिर 41 साल बाद पुरुष टीम ने कोई पदक जीता और महिला टीम पहली बार सेमिफाइनल में पहुंची तो भारतीय हॉकी विश्व मंच पर मजबूत दस्तक के साथ लौटी

वर्ष 2011 में भारतीय हॉकी के साथ जुड़ाव के अपने पहले दौर में डेविड जॉन पुरुष टीम के फिटनेस ट्रेनर थे. ऑस्ट्रेलिया के उनके हमवतन माइकल नॉब्स टीम के कोच बस नियुक्त ही हुए थे और उन्होंने भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन के अहम कारणों में शारीरिक फिटनेस (जाहिर है, कमी) को बताया था.

इस जोड़ी ने मिलकर भारतीय खिलाड़ियों के फिटनेस कायाकल्प की संस्कृति की नींव डाल दी, ताकि वे यूरोपीय खिलाड़ियों का मुकाबला बराबरी से कर सकें. नॉब्स और जॉन के प्रशिक्षण में सरदार सिंह, संदीप सिंह जैसे खिलाड़ियों के शारीरिक कौशल और दमखम में नाटकीय इजाफा हुआ. फिर भी, वैश्विक मंचों पर कामयाबी दूर ही रही. 2013 में नॉब्स को अचनाक हटा दिया गया. उनके बाद बहुत सारे कोच आए. शुरू में जॉन को भी हटा दिया गया, लेकिन 2016 में उनकी टीम के उम्दा प्रदर्शन करने वाले निदेशक के रूप में वापसी हुई.

हालांकि, आज भारतीय हॉकी ने आखिरकार बेड़ियां तोड़ दी और बरसों तक पिछड़ने के बाद उम्दा प्रदर्शन कर दिखाया है, लेकिन भारत में नॉब्स और जॉन के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. ग्राहम रीड (पुरुष हॉकी टीम के मौजूदा कोच) और जोएर्ड मारीज्ने (महिला हॉकी टीम की कोच) ने अलग काम यह किया है कि उन्होंने खिलाड़ियों में आत्मविश्वास भर दिया है.

याद रखना चाहिए कि भारतीय हॉकी को खेल की पुरानी शैली से बाहर निकालना था, जिसके तहत उसने पिछली सदी में कामयाबी के शिखर छुए थे. फिर से सीखना शुरू करने की सख्त जरूरत थी. 28 जुलाई, 2021 को लीग स्टेज में ब्रिटेन की टीम से हारी महिला टीम एक अहम मिसाल है कि पुरानी शैली और तरीके अब असरदार नहीं रहे. 1-4 से पराजय के बाद कोट मारीज्ने ने कहा था, ''भारतीय हॉकी की पुरानी शैली अब कारगर नहीं रही. यही खेल उन्होंने आज खेला, लंबे समय तक गेंद को अपने पास रखा और हम हार गए.''

शारीरिक फिटनेस के साथ ही, भारतीय टीम आत्मविश्वास से लबालब है. यह किसी ओलंपिक मुकाबले में सबसे बड़े अंतर से हारने (ऑस्ट्रेलिया के हाथों 1-7 से) के बाद लगातार पांच मैच जीतने में दिखता है. या फिर उस तरीके में, जिससे ग्रुप स्टेज तीन लगातार मैचों में हारने के बाद इसने पहली बार सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई. तोक्यो में विश्व की नंबर 2 टीम ऑस्ट्रेलिया को पीटने के बाद मारीज्ने ने कहा, ''अंतर खुद पर भरोसा करने और फिर सचाई पर लौट आने का है. अगर आप हारते हैं, तो भी आपका भरोसा कम नहीं होना चाहिए, यही बात मैंने लड़कियों से कही थी.''

भारतीय टीम में अभी युवाओं और तजुर्बेकार खिलाड़ियों का अद्भुत मिश्रण है. इसलिए, पी.आर. श्रीजेश, रूपिंदरपाल सिंह और मनप्रीत सिंह जैसे दिग्गजों के साथ हरमनप्रीत और दिलप्रीत सिंह जैसे नए खिलाड़ी भी हैं. महिलाओं की टीम में, अनुभवी रानी रामपाल अगर अपना खेल खामोशी से खेलती हैं तो उन्हें पता होता है कि युवा लालरेमसियामी हमेशा उनकी मदद के लिए मौजूद हैं.

> **''भारतीय हॉकी अपनी खास स्थितियों में पैदा हुई है. इसमें बहुत कुछ हुनर इसलिए विकसित हुई, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों की कद-काठी यूरोपीय खिलाड़ियों की तरह मजबूत नहीं है''**
>
> **ग्राहम रीड-**
> *कोच, भारतीय पुरुष हॉकी टीम*

पुरुष हॉकी टीम के कोच रीड ने ओलंपिक चैनल से कहा, ''भारतीय हॉकी एक खास स्थिति में पैदा हुई है. बहुत सारा भारतीय कौशल इसलिए विकसित हुआ है क्योंकि भारतीय खिलाड़ी यूरोपीय खिलाड़ियों की तरह बड़ी डील-डौल के नहीं होते. हमें दमखम में इस अंतर का पाटना

एएफपी

ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतने पर पुरुष हॉकी टीम के खुशी के पल (4 अगस्त)

है. दुनिया के कुछ सबसे उम्दा खिलाड़ी बड़ी डील-डौल के नहीं हैं. हमारे पास स्टिक का लाजबाव हुनर काफी है और हम उसे इस्तेमाल करना जारी रखेंगे. हम गेंद को पास करना पसंद करते हैं और विरोधी को टैकल करने का मौका नहीं देंगे. हमारा कौशल जर्मनी, नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया से अलहदा है और यही बात भारत को खास बनाती है.''

एक बड़ा अहम कारक हॉकी इंडिया का बढ़ता दबदबा है. नेशनल फेडरेशन ने यह फैसला किया है कि लगभग सभी वैश्विक हॉकी प्रतियोगिताओं का आयोजन भारत में करवाया जाए, ताकि भारतीय खिलाड़ियों को अधिकतम अनुभव मिले और वे दूसरों के हुनर और खेल से वाकिफ हो सकें. भारतीय हॉकी टीमों का अब मुख्य प्रायोजक ओडिशा हाल के दौर में अंतरराष्ट्रीय हॉकी का हब बन गया है.

मार्च, 2008 में भारतीय हॉकी गर्त में चली गई थी, जब यह इंग्लैंड से 2-0 से हारी थी और वह बीजिंग ओलंपिक से बाहर हो गई थी. पहली बार, ओलंपिक में भारतीय टीम शामिल नहीं हो पाई थी. लेकिन तोक्यो 2020 ने भारतीय हॉकी में एक नया अध्याय लिखा है क्योंकि इस बार पुरुष टीम कांस्य पदक लेकर लौटी है तो महिला टीम पहली बार सेमिफाइनल में पहुंचने का हौसला दिखाया है. यकीनन, यह सूर्योदय की तरह है. संभव है, न सिर्फ भारतीय हॉकी का पुराना गौरव और जादुगरी लौट आए, बल्कि नए कीर्तिमान स्थापित हो.

–राहुल रावत

रखने की जरूरत है: हम पेरिस में दो अंकों में पदकों की आकांक्षा रख सकते हैं, लेकिन बड़े विजेताओं की फेहरिस्त में शामिल होने के लायक नहीं हैं.

यहां भारतीय एथलीटों की प्रतिभा या क्षमता पर संदेह नहीं जाहिर किया जा रहा है. न ही यह आशय है कि ये पुरुष और महिलाएं विश्व मंच के लिए तैयार नहीं हैं. लेकिन खेलों में जीतने के लिए प्रतिभा के अतिरिक्त भी काफी कुछ चाहिए. मसलन, निशानेबाजी में सौरभ चौधरी को ही लें. पिछले तीन साल में 19 साल के सौरभ ने 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबलों में कई मेडल जीते हैं. तोक्यो में उनसे पदक की उम्मीद करना स्वाभाविक ही था. उम्मीद के अनुसार, सौरभ ने क्वालीफाइंग दौर में उत्कृष्ट 586 (600 में से) स्कोर किया और 70 सदस्यों वाले मजबूत पूल में पहले नंबर पर आकर फाइनल में जगह बनाई. ऐसा लग रहा था कि वे अपने पूरे लय में हैं. लेकिन पांच शॉट के पहले फाइनल रिले में वे बिखर गए. सौरभ का कुल स्कोर बहुत खराब, मात्र 47.4 था (50 पर), वह भी तब जब पिछले चार वर्षों में उनका स्कोर कभी भी 47 नहीं रहा हो! प्रदर्शन में यह अप्रत्याशित गिरावट ओलंपिक फाइनल में आई.

3

पदक लगातार तीन ओलंपिक में भारत की महिला बैडमिंटन खिलाड़ियों को मिला

5

पदक 2008 से चार ओलंपिक में भारत की कुश्ती को हासिल

लेकिन क्या यह प्रदर्शन सौरभ को एक खराब निशानेबाज बनाता है? क्या वे बड़े मंच के लिए तैयार नहीं थे? जैसे ही वे 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में हारे, सोशल मीडिया पर स्वयंभू विशेषज्ञों ने उन्हें खारिज करना शुरू कर दिया. वे लिख रहे थे कि सौरभ की जितनी हवा बनाई गई थी, वे दरअसल उतने असरदार नहीं है. लेकिन ऐसा तो दुनियाभर के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के साथ हुआ है. नोवाक जोकोविच भी इन बेहद असामान्य खेलों में पदक जीतने में असफल रहे; सिमोन बाइल्स ने मानसिक स्वास्थ्य की परेशानियों का हवाला देकर अपने अधिकांश जिमनास्टिक आयोजनों से बाहर होने का फैसला किया; केंटो मोमोटा हार गए; एशले बार्टी ने पहले दौर में 55 अप्रत्याशित त्रुटियां कीं; और नाओमी ओसाका भी कुछ खास नहीं कर सकीं. सौरभ चौधरी भी इनसान हैं और अभी युवा हैं.

उस झटके के ठीक दो दिन बाद, वे 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में मनु भाकर के साथ रेंज में वापस आए. इस बार वे शानदार फॉर्म में थे. भारत ने पहले क्वालीफाइंग दौर में 582 अंक जुटाए, जो ओलंपिक रिकॉर्ड था. इसमें सौरभ ने शानदार प्रदर्शन करके 300 में से 296 अंक बटोरे थे. दूसरे क्वालीफाइंग दौर में, जहां शीर्ष चार टीमें थीं, सौरभ ने 200 में से 194 स्कोर किया. अगर मनु अपने सर्वश्रेष्ठ के करीब भी होतीं तो शायद सौरभ ने यह पदक भारत के खाते में डाल दिया होता.

यह वही 'ऐसा होता तो वैसा हो जाता' वाली भावना है जो तोक्यो में भारत के प्रदर्शन को परिभाषित करती है. ओलंपिक में भारत के लगातार खराब प्रदर्शन की क्या वजह है? रियो 2016 के बाद वित्तीय सहायता में काफी सुधार हुआ. निशानेबाजों को वे सभी सुविधाएं दी गई हैं जिनकी उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए उन्हें आवश्यकता थी. फिर भी, विभिन्न कोचों में से एक कोच की 2018 में नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआइ) को भेजी गई एक गोपनीय रिपोर्ट कहती है कि हमारे 70 प्रतिशत से अधिक निशानेबाज हर बड़े आयोजन में खराब प्रदर्शन करते हैं. रिपोर्ट में दबाव और आत्म-नियंत्रण में

असमर्थता को इस गिरावट के लिए जिम्मेदार बताया गया है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हमारे पास अब बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी तो हैं, लेकिन हमारे पास खेल विज्ञान की कमी है. मनु भाकर का प्रदर्शन यह दर्शाता है. 25 मीटर पिस्टल के रैपिडफायर सेगमेंट में भाकर के पास एक गोली मारने के लिए 3 सेकंड का अच्छा समय था. उन्होंने शांत होकर और आवंटित समय का भरपूर उपयोग करके निशाना लगाया तो उन्होंने 10.7-10.9 (जहां केवल 10 दर्ज किया जाता है) स्कोर किया; लेकिन जब केवल 1.7 सेकंड में एक शॉट दागा, तो सिर्फ 8 अंक ले सकीं. वे 2 अंकों से फाइनल में जगह बनाने से चूक गईं.

नि:संदेह भाकर बहुत प्रतिभाशाली हैं; लेकिन उसके पास एक चीज की कमी है, जिसे अभिनव बिंद्रा-किसी व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाले इकलौते भारतीय-''निर्णायक 1 प्रतिशत'' का नाम देते हैं. लंदन 2012 के बाद (उन्होंने बीजिंग 2008 में स्वर्ण पदक जीता), बिंद्रा ने पूरे प्रशिक्षण में खेल विज्ञान पर ध्यान दिया और रियो में अपना दूसरा ओलंपिक पदक जीतने के सबसे करीब पहुंच गए. इन युवा निशानेबाजों को आगे जाकर यही करने की जरूरत है: खेल विज्ञान का उपयोग करें और दबाव को संभालना सीखें. यह कहना आसान हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा किया जाता है तो आज हमारे पास जितने प्रतिभाशाली निशानेबाज हैं, वे पेरिस में एक अलग इबारत लिख सकते हैं. एक अन्य कोच ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, ''आप पूछते हैं कि हम विश्व कप जीत जाते हैं लेकिन ओलंपिक पदक नहीं, ऐसा क्यों? जब वे विश्व कप में निशाना लगाते हैं, तो उन्हें पता होता है कि अगला मुकाबला सिर्फ एक महीने दूर है. दिमाग में यही चलता है कि 'अगर इसमें नहीं जीते, तो अगली स्पर्धा जीत लेंगे.' लेकिन जब ओलंपिक में तो दिमाग में यही चलता रहता है कि अगले चार साल बाद फिर से मौका मिलेगा भी या नहीं.'' उनका कहना है कि ओलंपिक में अभी नहीं तो कभी नहीं का दबाव प्रदर्शन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली वजह है.

> **''हम 99 फीसद हासिल कर चुके हैं, लेकिन आखिरी 1 फीसद का संघर्ष हमारे खिलाड़ियों के आगे पहाड़ की तरह खड़ा है.''**
>
> **अभिनव बिंद्रा**
> *ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता, शूटिंग*

हमारे तीरअंदाजों और मुक्केबाजों के साथ भी यही हुआ. दीपिका कुमारी और अतनु दास दोनों अनुभवी खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके प्रशिक्षण में खेल विज्ञान को उतनी जगह नहीं मिली है. कोरिया की एन सैन (अंतिम विजेता) के खिलाफ क्वार्टर फाइनल के दौरान दीपिका के स्वास्थ्य मानकों की समीक्षा से पता चला कि वे खुद को संयत नहीं रख पा रही थीं. वे बहुत संघर्ष कर रही थीं. इसी तरह अतनु दास, दो बार के ओलंपिक चैंपियन को बाहर करने के बाद जापानियों के खिलाफ अंतिम शृंखला में लड़खड़ा गए. यहां भी भारत के तीरअंदाज प्रदर्शन की उसी अस्थिरता से ग्रस्त दिखे.

हालांकि, सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाला प्रदर्शन मुक्केबाज विकास कृष्णन और अमित पंघाल का रहा और वे पहले दौर में ही बाहर हो गए. विकास अपने कंधे में गंभीर चोट के साथ रिंग में उतरे और वे कभी भी मुकाबले में नजर नहीं आ रहे थे. गंभीर रूप से चोटिल कोई व्यक्ति भारतीय दल के सदस्य के रूप

लगन और कीर्ति

भारत की महिला एथलीटों ने तमाम दुश्वारियों के बावजूद अपने जज्बे से विश्व मंच पर छोड़ी छाप

लवलीना बोरगोहेन, 23 वर्ष
बॉक्सिंग

असम के गोलाघाट जिले में बारा मुखिया गांव में अपने मां-बाप को मिलने वाले तानों को याद करती हुई बोरगोहेन कहती हैं, ''लोगों को ऐसा मानना था कि मेरे माता-पिता ने पिछले जन्म में कुछ ऐसा पाप किया होगा कि उनकी तीन बेटियां हुई हैं.'' इन तीन बहनों ने मुए थाई जैसे मार्शल आर्ट में हाथ आजमाया, पर खास कुछ नहीं हो पाया. हालांकि, उनकी जुड़वां बहनों ने खेल छोड़ दिया, लवलीना लगी रहीं और बाद में बॉक्सिंग में जुट गईं. अब हर ओर उनके ओलंपिक मेडल और गांव में बदलाव की चर्चा हो रही है. उनके कांस्य पदक ने यह पक्का कर दिया है कि वे पक्की सड़क से कैसे गांव पहुंचे.

रानी रामपल, 26 वर्ष
हॉकी

हरियाणा के शाहबाद के एक कमरे के घर में पली-बढ़ी, रानी को शुरू में ही एहसास था कि हॉकी स्टिक के जरिए वे दो जून की रोटी के लिए जूझ रहे अपने परिवार को उबार सकती हैं. 15 साल की उम्र में वे राष्ट्रीय टीम में सबसे युवा खिलाड़ी बन गईं. वे 2010 में एफआइएच युवा खिलाड़ी पुरस्कार के लिए नामजद हुईं. 26 साल की उम्र में दिग्गज खिलाड़ी बन चुकी रानी ने लगातार दो ओलंपिक में देश की अगुआई की है. रियो ओलंपिक के एक साल बाद घर खरीदने का उनका सपना पूरा हुआ.

रामेंद्र पाल सिंह/इंडिया टुडे

कमलप्रीत कौर, 25 वर्ष
डिस्कस थ्रो

कौर खेल में जुटने से कम उम्र में शादी के दबाव से बच गईं, जो पंजाब के उनके गांव कबरवाला में लड़कियों की नियति जैसा है. इस साल शुरू में उन्होंने वेबसाइट स्क्रॉल को बताया, ''मैंने सोचा था कि नौकरी पाने और शादी से बचने के लिए खेल मेरा टिकट होगा,'' सौभाग्य से, छह फुट एक इंच लंबी इस लड़की की पीठ पर पिता कुलदीप सिंह का हाथ था. लेकिन वे उन पर आर्थिक बोझ नहीं डालना चाहती थीं, क्योंकि उनके संयुक्त परिवार को खेती से होने वाली मामूली कमाई का ही आसरा था. इसलिए कौर शॉटपुट की ट्रेनिंग के लिए बादल में स्पोर्ट्स अथॉरिटी सेंटर चली गईं और फिर कोच प्रीतपाल मारू के कहने पर डिस्कस थ्रो की ओर मुड़ीं. कौर ने अंडर-20 का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया. उन्हें रेलवे में नौकरी मिली और गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन के राहुल द्रविड़ एथलीट मेंटरशिप प्रोग्राम में चुना गया. तोक्यो में कौर को छठा स्थान मिला. यही कृष्णा पूनिया को भी 2012 लंदन में मिला था.

क्रिश्चियन पिटरसन/गेट्टी इमेजेज

विंसंजो पिंटो/एएफपी

मीराबाई चानू 26 वर्ष
भारोत्तोलन

बचपन में मीराबाई चानू के लिए वजन उठाना ओलंपिक खेलों के सपने से कहीं अधिक उनकी जरूरत थी. छह भाई-बहनों मे सबसे छोटी, चानू माथे पर जलावन ढोती थीं और कई बार उनका वजन उनके दोनों भाइयों से ज्यादा होता था. मां का हाथ बंटाने के लिए वे धान के खेतों में भी काम करती थीं. और मणिपुर के नांगपोक ककचिंग गांव में चाय का खोखा भी चलाती थीं. उनका परिवार मणिपुर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में निर्माण मजदूर रहे उनके पिता की पगार से नहीं चल पाता था. तब 12 साल की उम्र में मीराबाई ने भारोत्तोलन में जुटने का मन बनाया और प्रैक्टिस के लिए रोजाना इंफाल के खुमन लंपक स्टेडियम जाने लगीं. परिवार ने अपने सारे संसाधन इसमें झोंक दिए. उनकी बहनों ने उनके आने-जाने के खर्च के लिए अपनी सारी बचत दे दी, फिर भी कई दफा चानू आधी दूरी पैदल तय करती थी. इन मुश्किलों का सिला मिलना शुरू हुआ, जब चानू अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उम्दा प्रदर्शन करने लगीं और 2017 में विश्व चैंपियन बनने वाली महज दूसरी भारतीय बन गईं. तोक्यों में मिला रजत पदक से उन पर सौगातों की बारिश हो गई है, मणिपुर सरकार और उनके नियोक्ता रेलवे ने नकद पुरस्कारों की घोषणा की है. उनके परिवार को चलाने का उनका वजन शायद कम होता दिख रहा है.

—सुहानी सिंह

में तोक्यो कैसे जा सकता है? ओलंपिक में जाना कोई दावत उड़ाना नहीं है. विकास घायल हो गए थे लेकिन टीम के सूत्रों ने पुष्टि की है कि अमित पूरी तरह से फिट और तैयार थे. फिर उनके साथ क्या गलत हुआ? कुछ लोगों का कहना है कि अमित ने एक रात पहले कुछ नहीं खाया था, और जाहिर तौर पर अगली सुबह स्पर्धा स्थल पर जाने से पहले अधिक खा लिया-फ्लाइवेट मुक्केबाजों को मुकाबले से पहले अपने वजन पर निगाह रखनी होती है. कोचों में से एक ने कहा, ''उसका डाइट इधर-उधर हो गया था, वह संभल नहीं पाया. वह पहले राउंड के अंत तक थक गया था.'' ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर इस प्रकार की चूक अक्षम्य है; प्रतिस्पर्धी एथलीटों की निगरानी और प्रबंधन पेशेवर रूप से किया जाना चाहिए और हर तरह की वैज्ञानिक सहायता तैयार रखी जानी चाहिए.

उच्च प्रदर्शन देने वाले भारतीय मुक्केबाजी के निदेशक सैंटियागो नीवा ने एक चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन किया, ''अमित इटली में इस कोलंबियाई खिलाड़ी (युबरजेन मार्टिनेज) के साथ लड़ चुके थे और हम जानते थे कि वे खतरनाक हैं. अमित को इसे दो राउंड में जीतना था, नहीं तो यह मुश्किल होने वाला था.''

नीवा ने यह भी पुष्टि की कि अमित पहले दौर के बाद थक गए थे. यह कैसे हुआ? भारत के प्रमुख मुक्केबाजों में से एक तीन मिनट की बॉक्सिंग के बाद कैसे थक जाता है? फिर ऐसे 'उच्च प्रदर्शन वाले कोचों' का क्या फायदा और उन्हें साल-दर-साल मोटी रकम क्यों दी जाए जबकि उनकी गुणवत्ता इस स्तर की है?

8

स्वर्ण पदक (और 1 रजत, 3 कास्यं) के साथ भारतीय पुरुष हॉकी टीम अब तक की सबसे कामयाब साबित हुई है

41

वर्षों के बाद भारत की पुरुष हॉकी टीम ने कोई पदक जीता

लगता है कि भारतीय खेल में कुछ चीजें कभी नहीं बदलेंगी. मनिका बत्रा के खिलाफ राष्ट्रीय कोच सौम्यदीप रॉय को साथ रखने से इनकार करने के लिए कार्रवाई की जा रही है, हमें यह भी पूछने की जरूरत है: मनिका के कोच को मान्यता क्यों नहीं दी गई? अगर टीटीएफआइ (टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया) ने महासचिव एम.पी. सिंह को मान्यता नहीं देने और उनकी जगह मनिका की मदद करने का फैसला किया होता तो अनावश्यक विवाद से बचा जा सकता था. आइओए अध्यक्ष नरिंदर बत्रा ने कहा, ''आइओए (भारतीय ओलंपिक संघ) में, हम मान्यता पर निर्णय नहीं लेते हैं. हमारी भूमिका बस डाकघर जैसी है-टीटीएफआइ ने जिनके भी नाम भेजे हमने उन्हें मान्यता दी.'' यह 'बाबू संस्कृति' भारतीय ओलंपिक खेलों में कायम है और इसके परिणाम वही होते हैं, जो मनिका बत्रा के साथ हुआ.

तोक्यो में पदकों की गिनती रियो (जहां हमने 1 रजत और एक कांस्य जीता था) से बेहतर हो सकती है, पर इसमें बल्ले-बल्ले करने जैसी कोई बात नहीं है, महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा से लबरेज 1.3 अरब लोगों के देश के लिए तो निश्चय ही नहीं. क्या पेरिस 2024 में हम कायापलट की उम्मीद कर सकते हैं? इसमें कितना लंबा वक्त लगता है, यह समझने के लिए ब्रिटेन का उदाहरण सही होगा. ब्रिटेन ने 1996 के अटलांटा ओलंपिक में इकलौता स्वर्ण पदक जीता था. 1997 में नेशनल लॉटरी फंड ब्रिटिश ओलंपिक स्पोर्ट्स में लगा दिया गया और डेढ़ दशक में उसने 29 स्वर्ण पदक (लंदन 2012) जीते. रियो में उन्होंने अपने पदकों की तादाद बढ़ाई और छपने जाने तक तोक्यो में टीम समग्र पदक तालिका में पांचवें पायदान पर थी.

भारत में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इसमें कोई शक नहीं कि रियो अत्यंत निराशाजनक था, लेकिन इसने खेल की अनिश्चितता की भी याद दिलाई. आपने कितना भी कठोर प्रशिक्षण लिया और जबरदस्त तैयारी की हो, ऐन फैसले के दिन आप लड़खड़ा सकते हैं. अगर तैयारियों के लिए कोई पदक होता, तो अभिनव बिंद्रा यकीनन उसे जीत लेते. भारत के लिए आश्वस्त करने वाली बात यह है कि ठोस प्रयास दिखाई देने लगे हैं. खेल के लिए धन बढ़ा है. 2016 में केंद्र सरकार खेलों पर करीब 11.5 रुपए प्रति भारतीय (बजट आवंटन: 1,541 करोड़ रुपए) खर्च कर रही थी. 2019 में यह बढ़कर 16.5 रुपए प्रति भारतीय (बजट आवंटन: 2,217 करोड़ रुपए) हो गया था.

राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) 2 करोड़ रुपए की अल्प राशि के साथ 1998-99 में बनाई गई. दो दशकों में इसने 240 करोड़ रुपए जुटाए. इसमें करीब 38 फीसद निजी स्रोतों से, 35 फीसद सरकार की मिल्कियत वाली कंपनियों से और बाकी सरकार से आए. खेल मंत्रालय ने संसद में बताया कि सर्वोत्कृष्ट एथलीटों पर सरकारी खर्च 2014-15 (130 करोड़ रुपए) और 2019-20 (बजट सीमा: 482.5 करोड़ रुपए) के बीच करीब चार गुना बढ़ा है. यह बेहतरीन खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए खेल संघों के जरिए दिया गया.

भारतीय खेल प्राधिकरण ने दिसंबर 2018 में ऐलान किया था कि सरकार की टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के तहत, जो सर्वोत्कृष्ट एथलीटों की पहचान करती और उनके प्रशिक्षण के लिए सहायता देती है, तोक्यो 2020 के लिए खास तौर पर 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं. इसकी स्थापना सितंबर 2014 में की गई और यह 2015 के मध्य से चालू हो गई. 2017 में अभिनव बिंद्रा इसकी चयन समिति के प्रमुख थे, जब 220 एथलीटों को इस योजना से रकम दी गई. 2016 में 17 खेलों पर 19.9 करोड़ रुपए खर्च किए. 2017-18 में यह रकम बढ़कर 28.2 करोड़ रुपए हो गई, जो 19 खेलों के खिलाड़ियों पर खर्च की गई.

राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद कहते हैं, ''(एसएआइ गोपीचंद नेशनल) एकेडमी के लिए करीब 5 करोड़ रुपए मिले. करीब 50 खिलाड़ियों को सहायता दी जाती है. यह इन बच्चों के लिए बहुत बड़ी सहायता है, जो मुझे केंद्र सरकार से मिलती है.''

इसमें गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन, जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स और ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट सरीखे संगठनों की निजी पहलों को भी जोड़ लें, तो साफ है कि सहायक बुनियादी ढांचा धीरे-धीरे कायम हो रहा है. ब्रिटेन में कायापलट 15 साल में हुआ. भारत में यह प्रक्रिया शुरू हुए बमुश्किल चार या पांच साल हुए हैं. हमें हर ओलंपिक के साथ प्रगति की और पेरिस 2024 में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करनी चाहिए. ■

दागने की ताकत
जबलपुर ऑर्डनेंस फैक्ट्री में 2019 में एक प्रदर्शनी के दौरान धनुष होवित्जर

अनिल तिवारी

प्रतिरक्षा | ओएफबी सुधार

आयुध कारखानों का कायापलट

सभी 41 आयुध कारखानों को सात नए सार्वजनिक रक्षा उपक्रमों में ढालने से क्या भारत के तहस-नहस सैन्य उद्योग को नया जीवनदान मिल सकेगा?

संदीप उन्नीथन

भारत में रक्षा मामलों की सर्वोच्च निर्णय समिति— कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस)—ने 16 जून को शुरुआती गोली दाग दी. समिति ने देश के रक्षा औद्योगिक उत्पादन प्रतिष्ठान के अब तक के सबसे महंगे और पेचीदा कायापलट को मंजूरी दी. इसमें 41 आयुध कारखानों को अगले साल तक नए सिरे से ढालकर सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले सात निगमों में बदला जाएगा.

इस कदम का मकसद कुल मिलाकर करीब 80,000 करोड़ रुपए के इन कारखानों को तेजी से उत्पादकता की राह पर लाना है. इनमें 70,000 लोग काम करते हैं और ये मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी महकमा हैं. ये कारखाने मुख्यत: भारतीय सेना के लिए युद्ध टैंक, हथियारबंद लड़ाकू वाहन, रॉकेट लॉन्चर और तोप प्रणालियां बनाते हैं. मगर बरसों से कोई नवाचार न होने और उत्पादों की विविधता घटने से वे न तो निर्यात पर भारत की कमरतोड़ निर्भरता कम कर सके और न ही निर्यात के लिए स्वदेशी हथियार मुहैया करवाकर कूटनीतिक

डीपीएसयू पर लगा दांव

सार्वजनिक क्षेत्र के सात रक्षा उपक्रमों के मुख्यालय पांच शहरों में होंगे

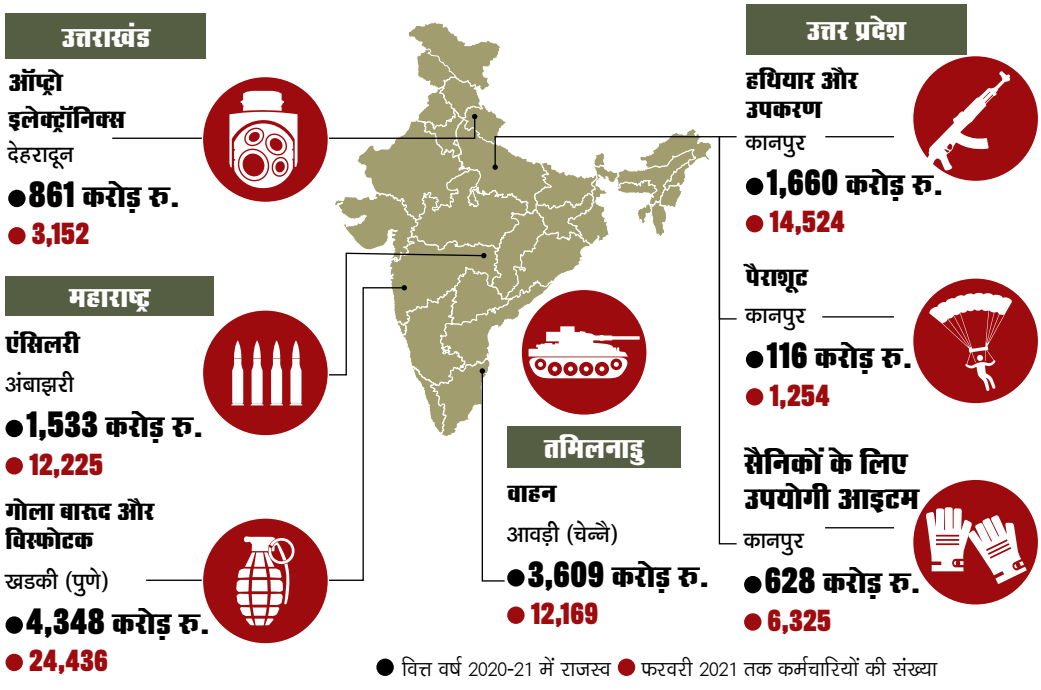

नौ मौजूदा उपक्रम

1. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
2. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
3. बीईएमएल
4. भारत डायनेमिक्स लिमिटेड
5. मिश्र धातु निगम लिमिटेड
6. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
7. गार्डन बीच शिपबिल्डर्स ऐंड इंजीनियर्स लिमिटेड
8. मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड
9. हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड

ग्राफिकः तन्मय चक्रवर्ती

वजन बढ़ा सके.

प्रस्तावित सात सार्वजनिक रक्षा उपक्रम (डीपीएसयू) एचएएल (हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लि.) और मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लि. सरीखे उन मौजूदा नौ उपक्रमों के अलावा होंगे जो वायु सेना और नौसेना को लड़ाकू विमान, हेलिकॉप्टर, युद्धपोत और पनडुब्बियां सप्लाइ करते हैं. ये सारे सार्वजनिक रक्षा उपक्रम मिलकर, रूस और चीन के बाद, दुनिया के तीसरे सबसे बड़े सरकारी स्वामित्व वाले सैन्य औद्योगिक प्रतिष्ठान का निर्माण करेंगे.

रक्षा मंत्रालय (एमओडी) ने 41 आयुध कारखानों को उनके उत्पादों के आधार पर सात डीपीएसयू में ढालने का काम शुरू कर दिया है. आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) को भंग कर दिया जाएगा, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है और आयुध कारखाने इसी के मातहत काम करते हैं. एमओडी के एक बड़े अफसर कहते हैं, ''ओएफबी संयुक्त परिवार की तरह है. संयक्त परिवार में सब जिम्मेदार होते हैं और फिर भी कोई जिम्मेदार नहीं होता. अब हम सात एकल परिवार बना रहे हैं.''

इस वक्त जब भारतीय सशस्त्र बल चीन और पाकिस्तान से सटी अनसुलझी सरहदों पर भारी अलर्ट की स्थिति में तैनात हैं, केंद्र सरकार नहीं चाहती थी कि ओएफबी की ताकतवर कर्मचारी यूनियनें डीपीएसयू की प्रकिया में गड़बड़ी पैदा करें. सरकार ने 30 जून को अनिवार्य रक्षा सेवा अध्यादेश 2021 लागू किया, जिसमें रक्षा कामों को अनिवार्य सेवा और हड़तालों को गैरकानूनी घोषित करके ओएफबी यूनियनों की राष्ट्रयापी हड़ताल के आह्वान की हवा निकाल दी.

डीपीएसयू को स्वायत्तता देने और साथ उन्हें जवाबदेह तथा चुस्त-दुरुस्त बनाने का फैसला ले लिया गया है. इस पुनर्गठन से आयुध कारखानों को उत्पादक और लाभदायक परिसंपत्तियों में बदलने, उनके तमाम उत्पादों की विशिष्टता में गहराई लाने, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और गुणवत्ता तथा लागत-दक्षता में सुधार की उम्मीद है. सरकार ने पिछले साल रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए. रक्षा मैन्यूफैक्चरिंग का टर्नओवर बढ़ाकर 2025 तक 35,000 करोड़ रुपए के निर्यात सहित 1.75 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य है.

एमओडी के रक्षा उत्पादन विभाग के हाथ अगले कुछ महीनों के लिए काम से लबालब हैं. उसे न केवल नए डीपीएसयू के पंजीकरण करवाने हैं बल्कि उनके निदेशक मंडलों की नियुक्ति करके मौजूदा आयुध कारखानों के भीतर उनके कॉर्पोरेट दफ्तर स्थापित करने की थकाऊ प्रक्रिया शुरू करनी है. सातों निगमों के मुख्यालय चार राज्यों के पांच शहरों में होंगे. उनमें से तीन उत्तर प्रदेश के कानपुर में होंगे.

यह प्रक्रिया बीते दो दशकों में भारत के दो सबसे बड़े निगम बनाने से कहीं ज्यादा जटिल होगी. अक्तूबर 2000 में सरकार ने तत्कालीन दूरसंचार सेवा विभाग को निगम में बदलकर भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) बनाया था. 2006 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत चार टकसालों, चार छापेखानों और एक कागज मिल को सरकारी की स्वामित्व वाली संस्था भारत प्रतिभूति मुद्रण और निर्माण निगम लिमि. (एसपीमसीआइएल) में बदला गया था.

आगे की चुनौतियां

बीते चार दशकों में कम से कम चार विशेषज्ञ समितियों ने ओएफबी को निगम

बनाने की सिफारिश की थी. मगर एक के बाद एक सरकारें राजनैतिक इच्छाशक्ति की कमी और ओएफबी यूनियनों की हड़ताल के डर से हिचकती रहीं. निगम बनाने की सबसे हालिया सिफारिश लेफ्टि. जनरल (सेवानिवृत्त) डी.बी. शेकटकर की अध्यक्षता वाली एमओडी की विशेषज्ञ समिति ने दिसंबर 2016 में की थी. समिति ने मुनाफा न दे पाने की वजह से 11 आयुध कारखानों को तत्काल बंद करने का सुझाव दिया था. फिर भी सरकार ने डीपीएसयू के नए ढांचे में सभी 41 आयुध कारखानों और उनके कर्मचारियों को बनाए रखना चुना है.

डीपीएसयू बनाने इस काम का एक हिस्सा भर है. ज्यादा बड़ी चुनौती उन्हें जिंदा रख पाना है. आयुध कारखानों के 120 साल के इतिहास में इन निगमों को रक्षा ऑर्डरों के लिए प्रतिस्पर्धा में उतरना पड़ेगा. आयुध कारखाने सशस्त्र बलों को गोला-बारूद की अबाध आपूर्ति के लिए विशाल युद्ध उत्पादन एजेंसी के तौर पर बनाए गए थे. किसी औपचारिक करार पर दस्तखत नहीं किए गए, केवल इंडेट या मांगपत्र दे दिए गए. 1801 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंपनी की सेनाओं के वास्ते तोप और गोले बनाने के लिए कोलकाता के काशीपुर में गन ऐंड शेल फैक्ट्री कायम की. 1944 तक ब्रिटेन ने 13 और फैक्ट्रियां बनाईं. स्वतंत्र भारत ने 1949 और 2010 के दरमियान 27 और कारखाने स्थापित किए. सबसे बड़ा विस्तार, जिसमें 16 फैक्ट्रियां जोड़ी गईं, 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद हुआ जब भारतीय सशस्त्र बलों का आकार बढ़कर दोगुना हो गया. आयुध कारखानों में पहला बड़ा और सोद्देश्य सुधार 1979 में हुआ, जब चेयरमैन और निदेशक मंडल की अगुआई में ओएफबी का गठन करके सभी 41 इकाइयों को इसके मातहत ले आया गया. मगर ओएफबी के कमजोर होने से हरेक आयुध कारखाना मैनेजर की अगुआई में स्वतंत्र संस्था की तरह काम करता रहा.

चूंकि ये आयुध कारखाने डीओपीपी के मातहत महकमों की तरह काम करते हैं, वे अलग बैलेंस-शीट नहीं रखते. जो सेना उनकी सबसे बड़ी ग्राहक है और जिसे वे टैंक और होवित्जर सहित अपने 1,000 मुख्य उत्पादों के बड़े हिस्से की आपूर्ति करते हैं, उसके साथ किसी करार पर दस्तखत नहीं करते. सातों डीपीएसयू के वजूद में आते ही इस सब पर विराम लग जाएगा.

एमओडी के एक बड़े अफसर निगम बनाने के पीछे तिहरी वजह बताते हैं—सरकार की एक-एक पाई ज्यादा से ज्यादा वसूलना, हथियारों का आयात कम करना और निर्यात बढ़ाना. ये अधिकारी कहते हैं, ''मूल आधार यह है कि मौजूदा ढांचा नाकाम हो चुका है, इसलिए हम पुनर्गठन कर रहे हैं. नए निगम मुनाफे के इरादे से चलाए जाएंगे और गलतियों के लिए जवाबदेह होंगे.''

यह कहना आसान है, कर पाना कठिन. खुले बाजार में डीपीएसयू को सर्वश्रेष्ठ से मुकाबला करना होगा. मसलन, ओएफबी के उत्पादन का सबसे बड़ा हिस्सा विस्फोटक हैं. नई व्यवस्था में 12 कारखानों को पुणे के खड़की स्थित एक निगम के मातहत लाया जाएगा. इसे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी विस्फोटक बनाने वाली नागपुर स्थित कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज सहित निजी क्षेत्र की बेहद चुस्त-दुरुस्त कंपनियों के साथ तगड़े मुकाबले में उतरना होगा. हथियारबंद वाहन बनाने वाले डीपीएसयू को निजी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी लार्सन ऐंड टुब्रो के साथ मुकाबला करना होगा, जिसने चार घंटों के भीतर सेना को 100 स्वचालित होवित्जर (टैंकों के ऊपर लगाई जाने वाली) बनाकर दे दी थीं. सरकारी कारखानों को पुणे स्थित निजी कंपनी भारत फोर्ज के साथ मुकाबला करना होगा. इसके पास तमाम किस्म की होवित्जर और हथियारबंद वाहन हैं, जो सेना को सप्लाई किए जा रहे हैं.

डीपीएसयू की उपादेयता सुनिश्चित करना सबसे बड़ी चुनौती होगी. उन्हें अपने उत्पादों के लिए ऑर्डर हासिल करने के मामले में निजी खिलाड़ियों से होड़ लगानी होगी

डीपीएसयू कारगर हो पाएंगे?

निजी क्षेत्र की एक रक्षा कंपनी के रक्षा व्यवसाय प्रमुख डीपीएसयू के कारगर होने को लेकर संदेह जताते हैं. वे कहते हैं, ''कुछेक बड़े निगम, मसलन वे जो जंग वाले वाहन और गोला-बारूद बना रहे हैं, बचेंगे. बाकी के बारे में मैं यकीन से नहीं कह सकता. ''

ओएफबी के पूर्व अधिकारी आयुध कारखानों के बीच आपसी तालमेल की समस्या की तरफ इशारा करते हैं. खासकर जब 'अंतर फैक्ट्री मांगों' या एक फैक्ट्री की तरफ से सहोदर इकाई से कलपुर्जे, ढलवां और गढ़वा हिस्सों की आपूर्ति की गई मांगों की बात आती है. उन्हें आशंका है कि नए निगम इस 'बैकवर्ड इंटीग्रेशन' या प्रतिगामी संयोजन में रोड़े अटकाएंगे जिससे ऑर्डर पूरे करने में देर हो सकती है. ओएफबी के पूर्व चेयरमैन हरि मोहन कहते हैं, ''हथियारबंद लड़ाकू वाहन एक निगम बनाएगा, पर उन्हें दूसरे निगम इंजन फैक्ट्री से आपूर्ति की जरूरत होगी और कानपुर से, जो तीसरा निगम है, बंदूक की नलियां लेनी होंगी. इनमें से हरेक लेनदेन के लिए अब टेंडर जारी करने और अंतिम ऑर्डर देने होंगे. ठेकों को अंतिम रूप देने में देरी होगी.''

ओएफबी यूनियनें सरकार से अगले पांच साल के ऑर्डरों का भरोसा मांग रही हैं ताकि निगम कारगर हो सकें. ओएफबी के कर्मचारियों की विशाल फौज को लेकर भी सवालिया निशान हैं. रक्षा मंत्रालय का कहना है कि वह ओएफबी के तमाम कर्मचारियों के हितों की हिफाजत करेगा. उत्पादन इकाइयों के कर्मचारियों को शुरुआत में दो साल के लिए डीम्ड डेपुटेशन पर निगमों में भेजा जाएगा. ऐसा करते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारी के तौर पर उनकी सेवा शर्तें नहीं बदली जाएंगी. दो साल बाद कर्मचारी को सरकारी सेवा में बने रहने या नए निगम में हमेशा के लिए जाने का विकल्प दिया जाएगा. निगम की तरफ से दिया गया पैकेज सरकारी वेतनमान से कतई कम नहीं होगा. पेंशन और दूसरे लाभ भी जस के तस बने रहेंगे.

जिन रक्षा जमीनों पर आयुध कारखाने स्थापित हैं, उनका क्या होगा? ओएफबी के पास करीब 60,000 एकड़ रक्षा जमीनें हैं, जिन पर उसने फैक्ट्रियां, आवासीय कॉलोनियां, अस्पताल और खेल सुविधाएं बना रखी हैं. ये जमीनें 'ए1' या मूल रक्षा जमीन की श्रेणी में आती हैं, जिनका किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. एमओडी बारीकी से देख-परख रहा है कि इन जमीनों का इस्तेमाल कैसे किया जाए. इनमें से कुछ डीपीएसयू को लीज पर दी जाएंगी जबकि बाकी एमओडी के अधिकार में रहेंगी. भारत के धमाकेदार रक्षा सुधार लंबे वक्त से चल रहे हैं. अब आखिरकार रक्षा कारखानों की सेहत दुरुस्त हो सकती है. ■

रफ्तार पकड़ने के पुख्ता रुझान

साल 2021 की पहली तिमाही में ऑटो निर्यात में चौतरफा उछाल, दोपहिया वाहनों का निर्यात 2020 के आंकड़े से तीन गुने पर पहुंचा

एम.जी. अरुण

खुशगवार नजारा
मार्च में गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर मारुति सुजुकी कारों की जहाज पर लदाई

वाहनों की घरेलू बिक्री जब कोविड-19 के शिकंजे में छटपटा रही है, भारतीय मैन्यूफैक्चरों के पास खुश होने के लिए कुछ तो है और वह है निर्यात बाजार. एसआइएएम (सोसाइटी फॉर इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स) या सियाम के मुताबिक 2021-22 के वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल से जून) में भारत का कुल ऑटो निर्यात 14 लाख इकाई रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि के आंकड़े से तीन गुना से ज्यादा है. खासकर दोपहिया वाहनों के निर्यात में बड़ा उछाल आया है. एक साल पहले की 3,37,983 इकाइयों के मुकाबले इस अवधि में करीब 11 लाख दोहपिया वाहन निर्यात किए गए. यह बड़ी राहत साबित हुआ है, वह भी ऐसे समय जब बीते डेढ़ साल के दौरान कोविड के चलते लॉकडाउन और लोगों में खर्चों में कटौती के रुझान से उद्योग खस्ताहाली के कगार पर पहुंच गया.

हकीकत तो यह है कि 2021-22 की पहली तिमाही में दोपहिया वाहनों के निर्यात के आंकड़े कोविड के पहले के वक्त से भी बेहतर रहे, पिछले तीन साल के निर्यात से भी बेहतर (देखें ग्राफ *बाहरी बिक्री*). 2021-21 की पहली तिमाही में सवारी वाहनों का निर्यात 1,27,115 इकाइयों पर पहुंच गया, जबकि 2020-21 की इसी अवधि में 43,619 इकाइयां निर्यात हुई थीं. मारुति सुजुकी के चेयरमैन आर.सी. भार्गव कहते हैं, ''इस साल निर्यात बीते साल के मुकाबले निश्चय ही बेहतर रहेगा, क्योंकि हम जिन देशों में निर्यात करते हैं उनमें से कई को भारत सरीखे सख्त लॉकडाउन से नहीं गुजरना पड़ा.'' उनकी फर्म ने इस अवधि में सबसे ज्यादा—45,056 इकाई—सवारी वाहन निर्यात किए. उसके बाद ह्युंडई मोटर्स इंडिया ने 28,88 1 इकाइयां विदेश भेजीं.

वर्ष 2021 के पहले आधे साल में वाहन निर्यात पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 50 फीसद उछाल लेकर 23.61 अरब डॉलर पर पहुंचा, जो 2014 के बाद निर्यात में सबसे अच्छा कारोबार है

साल 2021-22 की पहली तिमाही में सवारी वाहनों की बिक्री 2020-21 की पहली तिमाही के मुकाबले बेहतर थी, पर ये आंकड़े 2019-20 और 2018-19 की पहली तिमाहियों के आंकड़ों से पीछे रह गए. नतीजा यह कि इस साल के आंकड़े लंबे वक्त के रुझान का संकेत हैं या नहीं, इस पर कुछ कहने से पहले उद्योग के जानकार देखो और इंतजार करो का रवैया अपना रहे हैं. सियाम के डायरेक्टर जनरल राजेश मेनन कहते हैं, ''क्षेत्रीय लॉकडाउन ने कंपनियों को भारत में बिक्री से रोका क्योंकि ज्यादातर डीलरशिप बंद थीं, पर कई राज्यों ने कंपनियों को निर्यात करने दिए. हमें देखना होगा कि बिक्री में यह बढ़ोतरी मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ही हुई है या यह टिकाऊ रुझान है.'' उत्पादन के प्रतिशत के तौर पर भी निर्यात पिछले तीन साल की समान तिमाहियों के मुकाबले 2021-22 की पहली तिमाही में करीब 31 फीसद ज्यादा थे.

एक में सुधार तो सबमें सुधार

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 2021 के कैलेंडर वर्ष के पहले आधे साल में ऑटो निर्यात मूल्य के लिहाज से पिछले साल के मुकाबले 50 फीसद से भी ज्यादा बढ़कर 23.61 अरब डॉलर (1.7 लाख करोड़ रुपए) पर पहुंच गया. उसने यह भी कहा कि यह 2014 के पहले आधे साल के बाद से ऑटो निर्यात का सबसे अच्छा कारोबार है, जब निर्यात 25.23 अरब डॉलर (1.8 लाख करोड़ रुपए) के हुए थे. एजेंसियों ने मंत्रालय के एक अफसर को यह कहते बताया कि निर्यात में बढ़ोतरी की वजह यह है कि भारत में कार्यरत दक्षिण कोरियाई कंपनियों ने ऑटो कलपुर्जों की कमी के बावजूद अपने ''उत्पादों की प्रतिस्पर्धी क्षमता'' में इजाफा किया है. दक्षिण कोरियाई कंपनियों ह्युंडई मोटर और किया की भारतीय शाखाओं से अमेरिकी बाजार में सवारी कारों की बिक्री इस साल की पहली तिमाही में साल-दर-साल आधार पर 48 फीसद बढ़ी और इसने दोनों कंपनियों के बिक्री के सबसे ऊंचे रिकॉर्ड तोड़ दिए. भारतीय ऑटो कंपनियों के लिए निर्यात के बड़े ठिकानों में अमेरिका के अलावा पश्चिम एशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ओशआनिया (जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अन्य देश हैं) और हमारे एशियाई पड़ोसी हैं. शीर्ष दोपहिया निर्यातकों में बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर और हीरो मोटोकॉर्प हैं. वित्त वर्ष'21 में भारत के कुल दोपहिया निर्यात में बजाज ऑटो और टीवीएस की हिस्सेदारी 78 फीसद थी. दोपहिया निर्यात के मुख्य क्षेत्रों में अफ्रीका, दक्षिणपूर्व एशिया, दक्षिण अमेरिका, अमेरिका और यूरोप शामिल हैं.

लगता है, ऑटो निर्यात के मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन का शुरुआती असर ऑटो कलपुर्जों के निर्यात पर भी पड़ा है. ऑटोमोबाइल पुर्जों का निर्यात कैलेंडर वर्ष 2021 के पहले आधे साल में साल-दर-साल आधार पर 43.6 फीसद बढ़कर 11.61 अरब डॉलर (करीब 86,000 करोड़ रुपए) पर पहुंच गया. उद्योग की संस्था एसीएमए (ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन) के प्रेसीडेंट दीपक जैन कहते हैं, ''ऑटो कलपुर्जो के उद्योग में आम तौर पर वाहन उद्योग की ही झलक दिखाई देती है, बल्कि उससे भी कुछ बेहतर. हमने निर्यात के साथ-साथ आफ्टरमार्केट बिक्री में बढ़ोतरी को कायम रहते देखा है.''

निर्यात पर फोकस की एक वजह यह है कि वाहनों की घरेलू खरीद क्षेत्रीय लॉकडाउन की वजह से बदहाल है. जैन कहते हैं, ''रिटेलर बहुत ज्यादा माल रखना नहीं चाहते. हम

बाहरी बिक्री

दोपहिया वाहनों के निर्यात में सबसे अधिक उछाल दिखा, 2021-22 की पहली तिमाही में 11 लाख इकाइयां बिकीं, जबकि इसी अवधि में 2018-19 में 8,58,000 इकाइयां और 2019-20 में 8,84,000 इकाइयां बिकीं थीं

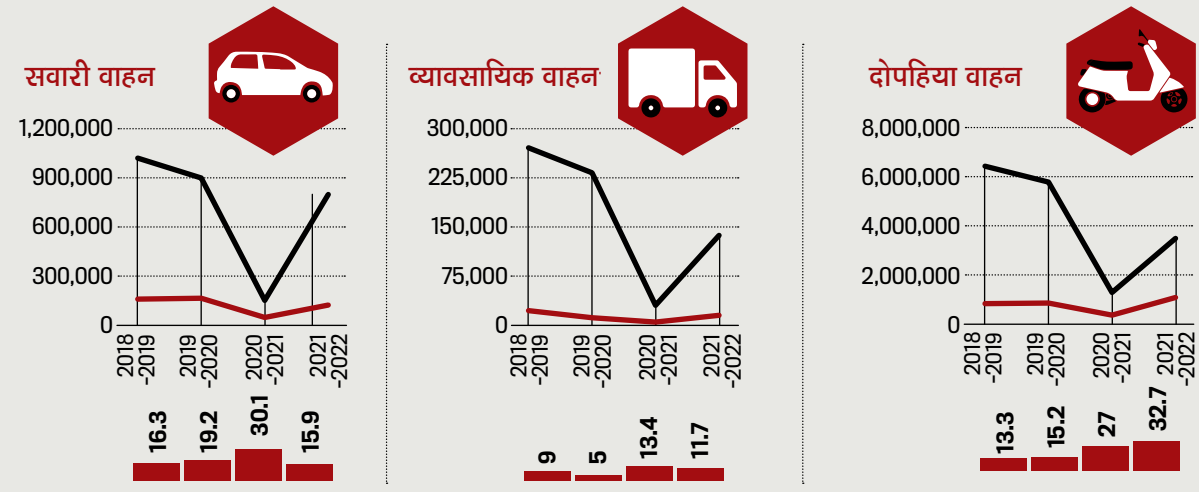

नोटः संबंधित वर्ष में पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के आंकड़े

स्रोतः सियाम

ग्राफिकः तन्मय चक्रवर्ती

उम्मीद कर रहे हैं कि जब पाबंदियां हटेंगी, तो कुछ दबी हुई मांग होगी और लगातार बहाली बिक्री को टिकाऊ स्तर पर ले आएगी.'' असल में, ऑटो पुर्जों की चीन से आपूर्तियां कोविड-19 महामारी के चलते प्रभावित हुई तो कई ग्लोबल ऑटो कंपनियों का मनसूबा कलपुर्जों के स्रोत के तौर पर भारत को प्रमुख केंद्र बनाने का था. इसे 'चाइना प्लस वन' रणनीति कहा गया और यह भारत के लिए बेहद फायदेमंद होती, जो कलपुर्जों की वैश्विक मूल्य शृंखला में फिलहाल महज करीब 1.5 फीसद का योगदान देता है. भारत के कलपुर्जों के निर्यात का 50 फीसद जितना बड़ा हिस्सा अमेरिका और यूरोप के गुणवत्ता-सजग बाजारों के लिए है. एएमसीए की कुछ सदस्य कंपनियों ने कहा कि वे चीन पर निर्भरता कम कर रही हैं, पर जैन बताते हैं कि निर्यात बढ़ाना कोई रात भर का खेल नहीं है.

कलपुर्जा उद्योग केंद्र की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन लाभ (पीएलआइ) योजना के ब्योरों का भी इंतजार कर रहा है. इसके तहत केंद्र ने मैन्यूफैक्चरिंग बढ़ाने और निर्यात बिल कम करने की खातिर ऑटो और ऑटो कलपुर्जा क्षेत्र के लिए 57,042 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है. जैन मानते हैं कि इस योजना से घरेलू उत्पादन और निर्यात दोनों बढ़ेंगे. कंसल्टिंग फर्म मैकिंसी का मार्च 2021 का एक अध्ययन कहता है कि प्रोत्साहन लाभ के साथ ''ऑटोमोटिव सप्लायर अंतरराष्ट्रीय वृद्धि हासिल करने और हाल की अनुकूल हवा का फायदा उठाने के लिए प्रतिस्पर्धी लागतें, प्रक्रियागत विशेषज्ञता, ऊंची गुणवत्ता और नवाचार पर फोकस सरीखी अपनी खूबियों का इस्तेमाल कर सकते हैं.''

आगे का रास्ता

मारुति सुजुकी ने फरवरी में कहा कि उसने अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को अपने निर्यात बढ़ाने की योजना बनाई है और उसकी इन इलाकों में एक साथ कई नए मॉडल लॉन्च करने की योजना भी है. मारुति के लिए एक और बड़ा निर्यात ठिकाना यूरोप है, तो इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका भी. रिपोर्ट कहती हैं कि कंपनी की अल्टो, बलेनो, डिजायर और स्विफ्ट कारें इन बाजारों में लोकप्रिय हैं. जनवरी में कंपनी ने सुजुकी की चुस्त और ऊबड़खाबड़ इलाकों में इस्तेमाल की जाने वाली जिम्नी का उत्पादन और निर्यात शुरू किया. हालांकि घरेलू मांग को पूरा करना उसकी प्राथमिकता है और 2020 में उसके कुल उत्पादन में निर्यात का हिस्सा महज छह फीसद था, लेकिन मारुति की योजना गुजरात की तीसरी मैन्यूफैक्चरिंग लाइन की अतिरिक्त क्षमता का इस्तेमाल निर्यात के लिए करने और भविष्य में इसे कुल उत्पादन के 20 फीसद तक ले जाने की है.

उधर ह्युंडई की योजना भी भारत को कलपुर्जों और वाहनों के अपने एक वैश्विक केंद्र के तौर पर विकसित करने और दक्षिण अमेरिका तथा पूर्वी यूरोप की अपनी फैक्ट्रियों के लिए भारत से कलपुर्जों की खरीद बढ़ाने की है. 2019 में भारत आई किया मोटर्स ने पिछले साल कहा कि वह अपने कॉम्पैक्ट स्पोर्ट्स यूटिलिटी वेहिकल सॉनेट और दूसरे मॉडल के लिए निर्यात के केंद्र के तौर पर भारत का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है. भारत से दूसरे प्रमुख निर्यातकों में फोर्ड इंडिया, निसान मोटर्स, फोक्सवैगन इंडिया और जनरल मोटर्स शामिल हैं.

इनफोर्मेशन और एनालिटिक्स फर्म आइएचएस मार्किट में एसोसिएट डायरेक्टर गौरव वंगाल कहते हैं कि ओईएम (ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्यूफैक्चर्स, उद्योग की बोलचाल में ऑटो निर्माताओं का नाम) इंटरनल कंबस्शन इंजनों वाले वाहनों के लिए भारत को मैन्यूफैक्चरिंग अड्डा बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहनों के पक्ष में हवा है.

ज्यादातर विशेषज्ञों का कहना है कि वाहनों के साथ ऑटो कलपुर्जों के मामले में भी सही किस्म के मौके भारत के सामने हैं. मगर देश को वैश्विक खिलाड़ियों से और ज्यादा निवेश के लिए आज से ज्यादा प्रतिस्पर्धी होना होगा. कई ऑटो निर्माताओं ने भारत को मैन्यूफैक्चरिंग और निर्यात का केंद्र बनाने के इरादा दिखाया है, लेकिन वे अपने मनसूबों को हकीकत में बदल पाएं, इसके लिए लंबा रास्ता पार करना होगा. ■

सुरक्षित रास्ता
पेंच में बनाए गए सुरक्षित रास्ते से गुजरता बाघ

विकास योजनाओं में जानवरों का ख्याल

वन्यजीवों की मौत रोकने के लिए भारत को अब कहीं जाकर बिजली के तार जमीन के नीचे बिछाने और पशु ओवरपास बनाने सरीखे उपायों की सुध आई, भले ही इससे सौर ऊर्जा और हाइवे लागतों में इजाफा हो

रोहित परिहार

साल 2018 में सड़क और रेल दुर्घटनाओं में 161 जंगली पशु मारे गए, तीन दशकों में रेल दुर्घटनाओं में दो सौ हाथी मारे गए, जिनमें 65 की जान बीते तीन साल में गई. बिजली के तारों की चपेट में आकर भारत के सारस पक्षियों की एक फीसद आबादी खत्म हो गई. सीहोर जिले में स्थित रातापानी टाइगर रिजर्व स्टेशन पर बीते पांच सालों में रेलों की पैंट्री कार से फेंकी जूठन के कारण हुई दुर्घटनाओं में 100 से ज्यादा जंगली पशु मारे गए, जिनमें पांच बाघ और सात तेंदुए थे.

ये रूह कंपकंपा देने वाले आंकड़े वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया के हैं. इसका संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 21 अप्रैल 2021 को वन्यजीवों और पर्यावरण के लिए संभावित जोखिम पैदा करने वाले सीधे बुनियादी ढांचे के विकास में शमन उपायों को विवेकाधीन के बजाए अनिवार्य बना दिया. तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे के साथ न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और वी. रामासुब्रह्मण्यम की तीन जजों की पीठ ने यह आदेश जाने-माने पर्यावरणवादी और पूर्व अफसरशाह एम.के. रणजीतसिंह की दो साल पहले दाखिल जनहित याचिका पर दिया था. जजों ने कहा कि पर्यावरण न्याय तभी हासिल किया जा सकता है ''जब हम इनसानी हित पर जोर देने वाले 'एंथ्रोपोसेंट्रिज्म' (मानवकेंद्रितवाद) के सिद्धांत से हटकर प्रकृति-केंद्रित 'इकोसेंट्रिज्म' (पर्यावरणकेंद्रितवाद) की तरफ जाएं, जिसमें इनसान कुदरत का अंग है और गैर-इनसानों की अंतर्भूत अहमियत है. दूसरे शब्दों में, मानव हित को अपने आप तरजीह नहीं मिल जाती और इनसानों की गैर-इनसानों के प्रति मानव हित से स्वतंत्र जिम्मेदारी है.'' अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना और केंद्र-प्रायोजित वन्यजीव एकीकृत विकास योजना इकोसेंट्रिज्म के सिद्धांत पर ही आधारित हैं.

अदालत ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या सोन चिरैया को बचाने के लिए बिजली के तार जमीन के नीचे बिछाने का आदेश दिया है. इस पर अकेले राजस्थान में 22,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे. थार में कई नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का मंसूबा बनाया गया है, जिनके लिए हाइ-वोल्टेज बिजली के तारों के विशाल नेटवर्क की जरूरत होगी. भारतीय उपमहाद्वीप की मूल प्रजाति सोन चिरैया को बचाने के लिए अब इन्हें जमीन के अंदर बिछाना होगा. वजन में सबसे भारी यह पक्षी भारत में 2011 में करीब 250 थे, जो 2018 में महज 150 रह गए. भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआइआइ) देहरादून के सर्वे के मुताबिक, इन तारों में उलझकर बिजली से उनकी मृत्यु दर 15 फीसद है. ये अगल-बगल दूर-दूर तक देख पाते हैं, जबकि सामने की नजर तंग होती है. उड़ते वक्त नीचे जमीन पर नजर रखने के चलते तारों के करीब आने पर ये चतुराई से उनसे निकल नहीं पाते और उलझकर मारे जाते हैं. यही नहीं, उनके इलाकों में विशाल भूभागों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाए जा रहे हैं, जिन्होंने इनकी अंडे सेने की जगहें छीन ली हैं. रणजीतसिंह कहते हैं, ''सौर ऊर्जा उतनी हरित नहीं है.''

भारत वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण (सीएमएस) का मौजूदा अध्यक्ष है. सीएमएस ने फरवरी 2020 में सोन चिरैया के लिए भारत की संगठित कार्य योजना को मंजूरी दी और जैसलमेर में नवोन्मेषी संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम चला रहा है. यहां इनसानी देखरेख में 17 चूजे जन्मे हैं, जो अब संस्थापक आबादी का काम करेंगे. बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के डायरेक्टर डॉ. विभाष पांडव कहते हैं, ''भारत में महज सौ बची रह गई सोन चिरैया की अकेली इंटेंसिव केयर यूनिट थार मरुस्थल है.'' डब्ल्यूआइआइ के डीन वाइ.वी झाला लंबे वक्त से सोन चिरैया के लिए प्राथमिकता क्षेत्रों की हिफाजत की वकालत करते रहे हैं, ताकि देखरेख में जन्मी उनकी आबादी खुले में छोड़ने पर बिजली के तारों या जानवरों के हाथों मारी न जाए.

पुनर्जीवन का रास्ता

एक और नई बात यह हुई कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) राजस्थान में वाहनों के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से होकर गुजरने के लिए दो समानांतर सुरंग बनाएगा, हरेक 3.65 किमी लंबी और चार लेन की होगी. ये सुरंगें 1,350 किमी लंबे आठ लेन के दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का हिस्सा होंगी. 90,000 करोड़ रुपए की यह परियोजना जनवरी 2023 में पूरी होने की उम्मीद है.

ये सुरंगें वन्यजीवों की बेरोकटोक आवाजाही के लिए एशिया के पहले पशु ओवरपास होंगी. इन पर 741.77 करोड़ रु. की अतिरिक्त लागत आएगी. इनके दोनों सिरों पर 500-500 मीटर की ढलान होगी और नियमित अंतरालों पर उन्हें जोड़ने वाला 30 मीटर लंबा रास्ता होगा, ताकि आपातस्थिति में ट्रैफिक को सबसे दाहिनी लेन की तरफ मोड़ा जा सके. मकुंदरा से गुजरने वाली सड़क को चार-लेन में बदलने का काम पर्यावरण मंजूरियां नहीं मिलने के चलते बरसों से लटका है. यह हिस्सा कोटा को झालावाड़ और उज्जैन को इंदौर से जोड़ता है. पहले एनएचएआइ ने मुकुंदरा पर दोमंजिले फ्लाइओवर का सुझाव दिया था, पर सौ मीटर के भीतर ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का स्मारक होने से यह आगे नहीं बढ़ा. मौजूदा चार-लेन एक्सप्रेसवे अब क्लोवर लीफ के जरिए सुरंगों से जुड़ेगा. शमन के दूसरे उपाय भी किए जाएंगे. मसलन, रणथंभौर टाइगर रिजर्व के पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र से गुजरने वाली 53.4 किमी लंबी पट्टी पर तीन मीटर ऊंची चारदीवारी और समर्पित ध्वनि तथा चकाचौंध बैरियर लगाना.

ग्राफिकः तन्मय चक्रवर्ती

अड़चनों से निकलना

ये पहल सराहनीय हैं, पर कई चुनौतियां भी हैं. मसलन, भारतीय सोन चिरैया की हिफाजत के लिए बिजली के तार जमीन के नीचे बिछाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मार सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर पड़ेगी. शीर्ष अदालत ने पक्षियों के लिए जो इलाका तय किया है, उसके ज्यादातर हिस्से में 94 गीगावॉट की प्रस्तावित सौर ऊर्जा परियोजनाएं हैं. ये 2030 तक 450 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा हासिल करने के भारत के लक्ष्य के लिए बेहद अहम हैं. शीर्ष अदालत ने लागत की भरपाई केंद्र और राज्य सरकारों, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल और प्रतिपूरक वनीकरण कोष (सीएएमपीए या कंपेनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड) पर छोड़ दी है. सौर ऊर्जा निवेशकों का कहना है कि प्रति यूनिट लागत 1.50 रुपए तक बढ़ सकती है. मगर पर्यावरणवादियों का आरोप है कि वे याचिका लंबित रहने के दौरान ही चालाकी से हड़बड़ी में परियोजनाएं ले आए. कॉर्बेट फाउंडेशन के डायरेक्टर केदार गोरे कहते हैं, ''राजस्थान और गुजरात में शीर्ष अदालत की शर्तों का पालन किए बगैर जमीन के ऊपर बिजली के तार लगाने का काम चल रहा है और न ही तारों पर बर्ड डायवर्टर लगाए गए हैं (जिनकी सुप्रीम कोर्ट ने जमीन के नीचे तार बिछाने तक जरूरत बताई है).'' रणजीतसिंह कहते हैं कि अगर निवेशक शमन उपायों की भारी लागत से परेशान हैं तो विकल्पों की तलाश करें, ''इंदिरा गांधी नहर के ऊपर सौर पैनल लगाना कैसा रहेगा?''

हमें पक्षियों और जानवरों की सुरक्षा के उपायों की जरूरत क्यों है

- भारत के भूभाग में 21.34 प्रतिशत जंगल है और इसमें से 4.89 प्रतिशत हिस्सा संरक्षित है, जिसमें 103 नेशनल पार्क, 536 वन्यजीव अभयारण्य, 67 कंजर्वेशन रिजर्व और 26 सामुदायिक रिजर्व शामिल हैं. 26 टाइगर रिजर्व के बीच से सड़कें गुजरती हैं जिनसे जीव जंतुओं की स्वच्छंद आवाजाही बाधित होती है

- साल 2018 में रेल और सड़क हादसों में जान गंवाने वाले जंगली जानवरों की संख्या 161 थी. तीन दशकों में दो सौ हाथियों की जान रेल हादसों में गई है, इनमें से 65 मौतें पिछले तीन सालों में हुईं. बिजली तारों की चपेट में आकर सारस क्रेन की एक प्रतिशत आबादी ही खत्म हो चुकी है.

रैखिक या लंबी और सीध वाली आधारभूत ढांचों में वन्यजीवों की हिफाजत की कीमत

22,000 करोड़ रुपए
अनुमानित लागत है जैलसमेर में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के रहवास में बिजली तारों को भूमिगत करने की. इनमें से अधिकतर सोलर प्रोजेक्ट से जुड़ी हैं

742 करोड़ रुपए
का अतिरिक्त खर्च आएगा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को पार करने के लिए आठ लेन की 4.87 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने में

1,150 करोड़ रुपए
का अतिरिक्त खर्च आएगा रणथंभौर नेशनल पार्क में ओवरपास, अंडरपास और अन्य सुरक्षा के इंतजामों पर

बिजली क्षेत्र के अफसर पूछते हैं कि मरुथली नेशनल पार्क में भूमिगत और रेंगने वाली प्रजातियां बड़ी तादाद में रहती हैं, ऐसे में जमीन के नीचे बिजली के तार बिछाने से क्या पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर असर नहीं पड़ेगा? वे हैरानी जाहिर करते हैं कि क्या 33 केवी से ज्यादा के हाइटेंशन बिजली तारों को भी हटाया जा सकता है. शीर्ष अदालत ने हाइटेंशन तारों को हटाने की संभावना पर विचार के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाई है. 33 केवी के तारों को जमीन के ऊपर लगाने की लागत के मुकाबले (जो 6 लाख रुपए हो सकती है) जमीन के नीचे तार लगाने पर 28 लाख रुपए प्रति किमी तक खर्च करने पड़ सकते हैं. 66 केवी के तार बिछाने की लागत और भी ज्यादा है. राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुबोध अग्रवाल कहते हैं कि वे प्रभावित होने वाली मौजूदा पाइपलाइन परियोजनाओं का आकलन करवा रहे हैं.

जहां तक एनएचएआइ की परियोजना की बात है, एजेंसी ने पर्यावरण को होने वाले नुक्सान की भरपाई के लिए 80 करोड़ रुपए जमा कर दिए. मगर वन विभाग एक्सप्रेसवे से 30 किमी दूर बसे दो गांवों को दूसरी जगह बसाने के लिए 120 करोड़ रुपए मांग रहा है. एनएचएआइ ने यह कहकर इनकार कर दिया कि उसे सीएसआर के नियमों को मानने के बाध्य नहीं किया जा सकता. अलबत्ता उसने वादा किया है कि अगर मंजूरी देने वाली केंद्र सरकार की संस्थाएं आदेश देंगी तो वह रकम अदा कर देगा.

इकहरी सोच के जोखिम

तो क्या वन्यजीव इलाकों के बीच से गुजरने वाली रैखिक या सीधी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में शमन उपाय अब नियम बन जाएंगे? भारत का 21.34 फीसद हिस्सा वनों से ढका है. इसमें 4,89 फीसद संरक्षित वन हैं, जिसमें 103 नेशनल पार्क, 536 वन्यजीव अभयारण्य, 67 कंजर्वेशन रिर्जव और 26 समुदाय रिजर्व हैं. टाइगर रिजर्व घोषित 26 संरक्षित क्षेत्रों से सड़कें गुजरती हैं, जिन्हें पार करना वन्यजीवों के लिए तकरीबन नामुमकिन हो जाता है. यहां तक कि रेंगने वाले जानवर और परिंदे भी कई लेन वाली तेज रफ्तार सड़कों या चौड़ी नहरों को पार नहीं कर पाते.

झाला कहते हैं कि शेर-बाघ और कुछ अन्य प्राणी तो सुरक्षित रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कैरकल, जो केवल रणथंभौर में मिलते हैं, ऐसा नहीं करते. जैसा कि पेंच टाइगर रिजर्व में देखा गया है. एनएचएआइ जयपुर के चीफ जनरल मैनेजर मुकेश कुमार जैन जोर देकर कहते हैं कि रणथंभौर से गुजरने वाले एक्सप्रेसवे की मार्गरेखा में किसी भी बदलाव के लिए आबाद गांवों की जमीन का अधिग्रहण करना होगा, मानव आबादी को हटाना पड़ेगा, मोड़ बनाने होंगे जिनसे वाहनों की रफ्तार कम होगी और भीड़ बढ़ेगी, और इस सबसे एक्सप्रेस गलियारे का राष्ट्रीय और वित्तीय राजधानी के बीच सबसे तेज और छोटा रास्ता होने का उद्देश्य ही मटियामेट हो जाएगा.

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जुलाई 2019 में संसद में कहा था कि 'एक गरीब देश' को तय करना ही होगा कि वह विकास की जरूरतों को अनदेखा करके पर्यावरण की रक्षा पर कब तक सार्वजनिक धन खर्च करता रह सकता है. कांग्रेस सांसद के. सुरेश जानना चाहते थे कि क्या मंत्री जी पेंच की तरह, जहां राजमार्ग को चौड़ा करते वक्त शमन उपायों पर 240 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य में टाइगरों की रक्षा के लिए मैसूरू और वायनाड के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर अंडरपास बनाने पर विचार करेंगे. प्रमुख जांचकर्ता बिलाल हबीब की देखरेख में तैयार और पिछले साल जारी डब्ल्यूआइआइ की रिपोर्ट ने पेंच में ऐसे नौ चौराहों की उपयोगिता पर रौशनी डाली थी. अठहत्तर कैमरों से अंडरपास से गुजरते इनसानों, पालतू जानवरों, वन्य और घरेलू बिल्लियों और कुत्तों की 91,284 तस्वीरें खींची गईं. इनके विश्लेषण से पता चला कि जंगली जानवरों की आठ प्रजातियां कम या ज्यादा इन अंडरपास का इस्तेमाल कर रही थीं. 11 अलग-अलग चीतों को नौ में से छह अंडरपास को कुल 89 बार पार करते देखा गया.

एनएचएआइ का दावा है कि रणथंभौर में वन्यजीव सुरक्षा उपाय पेंच से बेहतर होंगे. 53.5 किमी के गलियारे में 1.5 किमी लंबा पशु अंडरपास, 1.7 किमी की एलिवेटेड गलियारा और 300-300 मी. के पांच पशु अंडरपास होंगे. वातायनों के साथ 3.5 किमी की भूमिगत बॉक्स संरचना और बड़ी तादाद में क्रॉस संरचनाएं, बड़े और छोटे रिज भी बनाए जाएंगे. तीन मी. ऊंची चारदीवारी जंगली जानवरों को मुख्य सड़कमार्ग पर घुसने से रोकेगी. इसके अलावा, जंगली जानवरों की सुरक्षित आवाजाही और जलनिकासी के लिए टाइगर गलियारे में खुलने वाले अतिरिक्त रास्तों के साथ एक बड़ा पुल, चार छोटे पुल और 13 पुलिया भी प्रस्तावित हैं. ये निर्माण उन जगहों पर किए जाएंगे जहां राज्य वन्यजीव विभाग ने टाइगरों की आवाजाही दर्ज की है. वृक्षारोपण और 41 करोड़ रुपए के शोर अवरोधक से शोर, कंपन और चकाचौंध के निष्प्रभ या न्यूनतम होने की उम्मीद है. इन उपायों से 50 किमी के रास्ते की लागत 22 करोड़ रुपए प्रति किमी बढ़ जाएगी.

सवाल यह है—क्या यह पर्याप्त होगा? ■

नया सुपरस्टार

मीतेश तनेजा

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक के बाद एक रिलीज से अभिनेता मनोज बाजपेयी इस नए बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार बनकर उभरे हैं

सुहानी सिंह

मनोज बाजपेयी कहते तो यही हैं कि उन्हें स्टारडम की तमन्ना नहीं है, ''मुझे बस काम देते रहो और सुपरस्टार का यह तमगा दूसरों को दो. मुझे अच्छे काम की चाह है. मैं इस लिहाज से लालची हूं कि कोई मुझसे मेरा एक भी अच्छा किरदार न ले जाए.'' अदाकर की विनम्रता और समर्पण प्रेरक हैं, मगर शायद यह भी दर्ज किया जाना चाहिए कि महामारी ने स्टारडम की परिभाषा ही बदल दी है. सिनेमाघर दर्शकों को लुभाने की जद्दोजहद कर रहे हैं और 100 करोड़ रुपए की फिल्म नामुमकिन सपना मालूम देती है. ऐसे में वेब शो के धुरंधरों को बोलबाला है. बाजेपेयी के द *फैमिली मैन* (2019) के दोनों सीजन आम राय से हिट करार दिए गए हैं, लिहाजा वे अब लोकप्रिय अदाकार भर नहीं, घर-घर में जाना-पहचाना नाम हैं. इस हफ्ते वे थ्रिलर फिल्म *डायल 100* लेकर ओटीटीस प्लेटफॉर्म जी5 पर लौटे हैं. ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक के बाद रिलीज से बाजपेयी इस नए बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार बनकर उभर रहे हैं. इनमें पिछले महीने नेटफ्लिक्स पर आई एंथोलॉजी फिल्म रे भी शामिल है, यह सत्यजित रे के काम पर आधारित है.

बाजपेयी कहते हैं कि *डायल 100* से वे मायूस नहीं हैं. यह फिल्म सिनेमाघरों के लिए बनी, पर डिजिटल पर रिलीज हो रही है. वे कहते हैं, ''मुझे लगता है कि एक नया दर्शकवर्ग उभरा है, जिसकी मेरा काम देखने में दिलचस्पी है. मेरे (पहले के) काम में उनकी दिलचस्पी अभिभूत करने वाली है.'' कहा जा सकता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्मों के उभार ने पंकज त्रिपाठी (*मिर्जापुर,* 2018), के.के. मेनन (*स्पेशल ऑप्स,* 2020), जयदीप अहलावत (*पाताल लोक,* 2020) और बाजपेयी सरीखे कलाकारों को खास फायदा पहुंचाया. हां, उनकी अदाकारी की साख पर कभी कोई संदेह नहीं था, पर फिल्मों में जोरदार भूमिकाएं पाने के लिए उन्हें कभी हाथ-पैर मारने पड़ते थे. जब मिलने भी लगे, तो स्टार-केंद्रित वितरण व्यवस्था ने उनसे दर्शक चुरा लिए.

बाजपेयी कहते हैं कि द *फैमिली मैन* की बदौलत वे 'चुनने का मौका' हासिल कर पाए. ओटीटी ने भौगोलिक रुकावटें मिटाने में मदद की, लिहाजा बाजपेयी को भरोसा है कि और ज्यादा दर्शक उनके काम की तलाश कर लेंगे. वे आंखों-देखा सबूत बताते हैं. उत्तराखंड में एक फिल्म की शूटिंग करते वक्त उन्होंने देखा कि लोग अपने मोबाइल पर वेब सीरीज देखने में मशगूल थे, ''जरा कल्पना करें कि पांच साल बाद ओटीटी की क्या संभावनाएं होंगी, कि यह सब कहां जा सकता है.''

बाजपेयी ने 1998 में पर्दे पर धूम मचा दी. उस साल उनकी तीन फिल्में आईं—*सत्या, शूल* और *कौन.* 2000 के दशक में यह नेशनल अवार्ड विजेता कई बिसरा दी जाने लायक फिल्मों में आया. बाजपेयी के लिए ये नाकामियां 'चूल्हा जलाए' रखने का तरीका भर थीं. वे कहते हैं, ''कइयों को लगता है कि यह मुश्किलों या मायूसी का दौर था. नहीं था. मैंने खुद पर काम किया. मैं नाकामी या नामंजूरी को निजी तौर पर नहीं लेता.'' वैसे उस बुरे दौर ने उन्हें सिखाया कि मनपसंद भूमिकाएं तो उन्हें खोजनी ही होंगी. वे ऐसे डायरेक्टरों से मिले जो उनकी पसंद की फिल्में बना रहे थे. जल्दी ही प्रकाश झा ने उन्हें *राजनीति (2010),* अगुराग कश्यप ने

गैंग्स ऑफ वासेपुर (2012) और नीरज पांडेय ने *स्पेशल 26 (2013)* में लिया.

अब बाजपेयी को पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं रह गई है. उन्हें बस पक्का करना होता है कि अपने यकीन के मुताबिक पीछे दौड़ने वाले खासकर स्वतंत्र फिल्मकारों को पूरा वक्त और तवज्जो दें. बीते दशक में आखिर ये इंडी डायरेक्टर ही थे जिन्होंने उन्हें उनके करियर की पहचान बनाने वाले रोल दिए—हंसल मेहता के साथ *अलीगढ़* (2015) और देवाशीष मखीजा के साथ *भोंसले* (2018). दोनों फिल्मों में सधी, सटीक और संवेदनशील अदाकारी के लिए उन्होंने एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड हासिल किया.

बाजपेयी कहते यही हैं कि वे 'मुख्यधारा और स्वतंत्र सिनेमा में फर्क' नहीं करते, पर आने वाली फिल्मों से स्वतंत्र सिनेमा के साथ उनका याराना जाहिर होता है. हाल में उन्होंने कन्नड़ फिल्म *तिथि (2015)* के लिए जाने जाने वाले राम रेड्डी, दिलचस्प फैमिली ड्रामा *तितली (2014)* के निर्देशक कनु बहल की फिल्में पूरी कीं. *सोनचिरैया (2019)* और *रे (2021)* के बाद वे अभिषेक चौबे के साथ फिर काम कर रहे हैं. राज और डीके के अपने तयशुदा काम निपटा लें, तो बाजपेयी उनके साथ *द फैमिली मैन* का काम फिर शुरू करेंगे. वे एक और वेब सीरीज के आने का इशारा भी करते हैं. कहते हैं, ''अच्छी बात यह है कि इन डायरेक्टरों से मेरी पटती है और वे मुझे समझते हैं.''

मनोज बाजपेयी कहते हैं कि द फैमिली मैन की बदौलत वे प्रोजेक्ट चुनने का मौका हासिल कर पाए

लंबी छुट्टी के बाद, जिसमें कोविड-19 की पारी भी है, बाजपेयी को परवाह नहीं है कि ये फिल्में कहां और कैसे रिलीज होती हैं. वे कहते हैं, ''अभिनेताओं से प्लेटफॉर्म या जॉनर के प्रति पूर्वाग्रह रखने की उम्मीद नहीं की जाती. उनकी दिलचस्पी बस अदाकारी में होनी चाहिए. यही मैं करता हूं.'' बाजपेयी सरीखे कुछ ही हैं जो इतनी सहजता से किरदारों में जान डाल देते हैं. ■

किताबें

मोती भरा कमंडल

मोहम्मद वक़ास

अफगानिस्तान के शाह अब्दुर्रहमान 1885 में लुधियाना दरबार में आए. वहां 'इल्म के बादशाह' से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा, ''हिंदुस्तान में जो खुशी आपसे मिलकर हुई वो किसी से नहीं हुई.'' इसी तरह, 1888 में ईरान के बादशाह दो ही मकसद से आएः एक तो वायसराय से मिलना और दूसरा उस शख्स से मुलाकात करना जिसके प्रेस ने फारसी की इतनी किताबें छापी थीं, जितनी उस समय पूरे ईरान में नहीं छपी थीं. उस अजीमुश्शान शख्स का नाम था मुंशी नवल किशोर.

मथुरा के एक गांव में जन्मे नवल किशोर भार्गव उर्दू-फारसी के साथ ही अंग्रेजी के विद्वान थे. अपने करियर की शुरुआत लाहौर में *कोहिनूर* अखबार से की. फिर लखनऊ में नवल किशोर प्रेस की स्थापना की और *अवध अखबार* निकाला, प्रेस के लिए कागज की जरूरत महसूस हुई तो पेपर मिल खरीद लिया. 'हिंदू मौलवी और मुसलमान पंडित' नवल किशोर के कामकाज और वेश-भूषा देखकर अमेरिकी ईसाई धर्म प्रचारक बिशप जॉन फ्लेचर हर्स्ट उन्हें 'कट्टर मुसलमान' मान बैठे थे.

राजकुमार केसवानी की *जहान-ए-रूमी* और *दास्तान-ए-मुग़ल-ए-आज़म* ने संभवतः आखिरी शाहकार *कशकोलः सफ़ीना-ए-उर्दू के नाख़ुदाओं की दास्तानें* में उर्दू अदब के 13 किरदारों की जिंदगी को बेहद दिलचस्प अंदाज में पेश किया है.

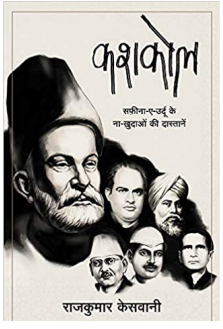

कशकोलः सफ़ीना-ए-उर्दू के नाख़ुदाओं की दास्तानें
लेखकः राजकुमार केसवानी
मंजुल पब्लिशिंग हाउस
कीमतः 350 रुपए
पन्नेः 293

सबसे पहले, मिर्ज़ा ग़ालिब की कहानी हज़रत निजामुद्दीन बस्ती में उनकी मजार से शुरू होती है. पूरी अक़ीदत के साथ लिखी गई मिर्ज़ा के किरदार को बयान करने के लिए वे गुज़रे जमाने के मलिक राम जैसे गालिब विशेषज्ञों को उद्धृत करते हैं. और उद्धृत करने का अंदाज देखिएः ''सवाल मिर्ज़ा गालिब को 'नौशा मियां' कहकर मुख़ातिब करने को लेकर है. यूं तो छोटा-सा और आसान जवाब दे सकता हूं, लेकिन सोचता हूं किसी और के जरिये यह बात कह दूं, तो एक टिकट में दो मजे हो जाएंगे.'' वे अपने पसंदीदा शायर की तारीफ अपनी तरफ से नहीं करते. ''ग़ालिब के परस्तारों में अकेले नेहरू ही नहीं थे. सियासी नजरिये से दो अलग-अलग ख़ेमों में खड़े लीडरान इस जगह एकमत रहे हैं.'' वे 1998 में ग़ालिब इंटरनेशनल सेमिनार में अटल बिहारी वाजपेयी के बयान को उद्धृत करते हैंः ''अहद-ए-मुग़लिया ने हिंदुस्तान को तीन चीजें दी हैं—ताज महल, उर्दू ज़बान और ग़ालिब की शायरी.'' पूरे अध्याय में जगह-जगह उनकी शेर का इस्तेमाल ऐसे किया गया है, जैसे ग़ालिब के दीवाने केसवानी को दीवान-ए-ग़ालिब पूरी तरह याद हो.

हिंदुस्तानी शेक्सपियर आग़ा हश्र कश्मीरी का अध्याय बीसवीं सदी की मशहूर अदाकारा-गायिका और आग़ा हश्र की बीवी के बयान से शुरू होता हैः ''नौजवान तुमसे पूछने आया करेंगे, हमें बताओ, आग़ा हश्र कौन था? वह किस अंदाज में बैठकर लिखा करता था. उसके गुफ़्तगू करने का ढंग क्या था? वह किस तरह का लिबास पहनता था? वह किरदार कैसे तरतीब देता था? हमें बताओ कि आग़ा हश्र को तुमने किस-किस रंग में देखा है?'' *यहूदी की लड़की, रुस्तम सोहराब, बिल्वा मंगल* आदि जैसे कालजयी नाटक लिखने वाले आग़ा हश्र के बारे में केसवानी इन सारे सवालों का जवाब पूरी तफ़्सील के साथ देते हैं. बयान की बानगी देखिएः ''नमाज़ पढ़ते उन्हें कभी किसी ने देखा नहीं और रोज़ा रखने की फ़ुरसत कभी मिली नहीं... वो खड़े-खड़े ऐसी गालियां ईजाद कर लेते थे कि पहली बार सुनने वाले के होश फ़ाख़्ता हो जाते... दीन-ओ-मज़हब की हिदायतों से इस क़दर फ़ासले पर रहने वाले आग़ा हश्र के किरदार का यह भी एक अनोखा रंग था कि वक़्त आने पर वे अपने मज़हब के हक़ में सीना तानकर खड़े हो जाते.''

केसवानी ने शीर्षक के चयन से लेकर इस किताब के लेखन में मन की मानी. वे बताते हैं, ''प्रचलित भाषा में कशकोल नहीं, कश्कोल है. न जाने क्यों इस पर मन नहीं मानता. लिहाजा, चलन छोड़ मन की मानी.'' चलन छोड़ने का नतीजा यह निकला कि एक-एक अदीब की दास्तान कशकोल में मोती की तरह है. पाठक तस्दीक कर सकते हैं कि दिल से जो बात निकलती है, असर रखती है. ■

हाशिए वालों का हमदर्द

नागेश कुकनूर ने साल 1998 में *हैदराबाद ब्लूज* से दस्तक दी. दो दशकों बाद भी यह फिल्मकार ओटीटी का आनंद लेते हुए चलताऊ सिनेमा को चकमा दे रहा है

सवाल+जवाब

● डिज्नी+हॉटस्टार सिरीज *सिटी ऑफ ड्रीम्स* के लिए आपका संदर्भ बिंदु क्या था?

मेरी प्रेरणा *द वायर* थी. शो की सबसे हैरानीभरी बात यह थी कि क्रिएटर्स ने हर एक हर सीजन के [बाल्टीमोर के] अलग-अलग पहलुओं को गहराई के साथ उठाया था. मैं लोगों को आहत किए बगैर बंबई की पड़ताल करना चाहता था और लोगों को उसकी झलक देना चाहता था कि कथित 'सिटी ऑफ ड्रीम्स' में होता क्या है. सिरीज का फॉर्मेट आपको अनेक अलग-अलग जिंदगियां दिखाता है. इसमें कोई सीमाएं नहीं हैं.

● आपने महामारी के बीच में सीजन 2 की शूटिंग की. इसके बारे में बताइए?

यह सबसे मजेदार शूट से सबसे ज्यादा दुखदाई शूट में बदल गया. सब कुछ ठीक चल रहा था [मार्च 2020 में] और शो का काम समाप्त करने में 18 दिन बचे थे. तभी हमें उड़ती खबर मिली कि कोरोना नामक वायरस आ रहा है. तीन दिन बाद हमें इसे बंद करना पड़ा. मैंने सबसे कहा कि कि हम दो हफ्ते में फिर से मिलते हैं. (हंसते हुए) हम आखिर जनवरी में शूटिंग फिर शुरू कर सके.

● हाशिए के किरदारों से आप हमदर्दी रखते हैं...

कोई छिपी हुई ताकत मुझे उस ओर ले जाती है. क्या यह घिसे-पिटे उबाऊ हीरो के बेदाग किरदार देखने से ज्यादा रोमांचक नहीं है? व्यावसायिक सिनेमा मुझे इसलिए बोरिंग लगता है क्योंकि इसमें आगे क्या होगा, यह बताना बहुत आसान है. लेखन में मेरा आग्रह दर्शकों को बहुत सहज तरीके से अचरज में डालने वाला होता है.

● आपकी पहली तेलुगू फिल्म *गुड लक साक्षी* के इस साल रिलीज होने की उम्मीद है. कैसा लग रहा है?

यह एक साथ रोमांचक और डरावना, दोनों है. अभी तक तो तेलुगू लोग मुझसे पूछते थे, 'आप अपनी मातृभाषा में कब कुछ बनाने जा रहे हैं?' मैं कहूंगा, मैं पर्याप्त आश्वस्त नहीं था. यह सच था. हैदराबादी होने के नाते, तेलुगू के मुकाबले दक्खिनी मुझे ज्यादा आसान लगती है, मैं अपनी मां से भी इसी में बात करता हूं. इस फिल्म में लोग मेरी जबरदस्त मीन-मेख निकालेंगे.

–युहानी सिंह

आज तक

देश का नं. 1 हिंदी न्यूज़ ऐप

जुड़े रहिए हर खबर से,
कहीं भी, कभी भी

अभी डाउनलोड करें

aajtak.in/app

उपलब्ध है

IndiaContent

SEARCH FOR EDITORIAL IMAGES ENDS HERE